

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

खण्ड 3, अंक 2

अधिकृत विवरण

## विषय सूची

मंगलवार, 22 दिसम्बर, 1992

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)1
सदस्यों का नाम लेना	(2)5
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(2)7
सदस्यों का नाम लेना	(2)11
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(2)12
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर।	(2)21
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)21
सदस्यों का नाम लेना/उनको वापिस बुलाना	(2)26
प्रेस वालों पर हमला	(2)26
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव --	(2)27
सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण हरियाणा में कृषि अर्थ व्यवस्था में गिरावाट आने सम्बन्धी	(2)28

वक्तव्य-- कृषि मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण सम्बंधी	(2)29
सदस्यों का नाम लेना	(2)33
नियम 104 का निलम्बन	(2)34
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव / वक्तव्य पुनरारम्भ)	(2)40
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	(2)45
तारांकित प्र न संख्या 337 और जानकारी देना	(2)45
वर्ष 1986-87 के लिये अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(2)46
वाक-आउट	(2)48
वर्ष 1986-87 के लिये अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(2)49
बैठक का समय बढ़ाना	(2)76
वर्ष 1986-87 के लिये अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(2)76

## हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 22 दिसम्बर, 1992

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9:30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ई वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

### तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर, अब सवाल होंगे।

#### **Collection of Money by the officers of Excise and Taxation Department**

Shri Jai Parkash: Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state whether any case of collection of money by any officer of the Excise and Taxation Department from the Industrialists as contribution towards the Chief Minister's fund during the period from 1987-88 to 1990-91 has come to the notice of the Government; if so, the district wise details thereof together with the action taken or proposed to be taken against the concerned officers?

Excise and Taxation Minister (Shri A.C. Chaudhry): A complaint was received from the District Sonipat Petroleum Dealers Association in December] 1988 against Shri K.S. Nain, Deputy Excise and Taxation Commissioner that he has been demanding money from the petrol pump dealers for the Chief Minister's relief fund. Another Complaint was received in August, 1989 on behalf of the industrialists and traders of Faridabad regarding collection of

money by him in the name of the Chief Minister and his son for elections. The matter is under investigation.

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूँ उन्होंने कई अधिकारियों के बारे में बताया है। इनके महकमें के जिला फरीदाबाद के जो बड़े अधिकारी है यह बड़े आला अफसर है, उनकी प्रोटेक्शन में वहाँ पर काले तेल का धन्धा बड़े जारों पर है। उसमें बड़े भारी टैक्स की चोरी की जाती है। क्या मंत्री जी के पास इनके खिलाफ कोई कम्प्लैन्ट आई है और क्या उन्होंने इनके खिलाफ कोई ऐक्टान लिया है?

**श्री अध्यक्ष:** यह क्वैशन प्रेजेन्ट क्वैशन के बारे में नहीं है, यह तो पास्ट का है।

**श्री जय प्रकाश:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि उस समय के चीफ मिनिस्टर कौन थे, ऐक्साइज और टैक्सेशन विभाग के किन किन अधिकारियों के खिलाफ यह रिपोर्ट थी और आज तक इस रिपोर्ट पर ऐक्टान लेने में देरी क्यों हुई?

**श्री ए०सी० चौधरी:** स्पीकर सर, अगर उस वक्त की सारी बातों को खोलकर रख दें तो उसकी सारी दुर्गन्ध अपने घरों में ही नहीं, इंडिया भर में फैल जाएगी। दुख की बात है कि उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी देवी लाल जी थे। उस केस में डिले इसलिये हुई कि उन्होंने दिखावे के लिए विजिलैन्स को केस मार्क कर दिया और बिना रिपोर्ट आए सिर्फ दो लाइनो में मेसज अप कर दिया कि विद दि

कंसैन्ट आफ चीफ मिनिस्टर केस फाइल कर दिया गया है और अफसर को सिर्फ हिदायत दे दी गई। जितने भी केसिज गए हैं, उनको उसी तरीके से इन्होंने फाइल करवा दिया परिणामस्वरूप लोगों ने डर के मारे कम्प्लेन्ट देना बन्द कर दिया कि हमारे खिलाफ भारी आंतक पैदा कर देंगे। श्री रणवीर सिंह ने चीफ मिनिस्टर के नाम पर 26-6-89 को डी० ओ० लैटर लिखा जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल्ज दीं उसके बावजूद भी उन्होंने उस कोई ऐकान नहीं लिया, मगर जब उसका रिमाइन्डर आया तो हमने उसकी छानबीन की और 20-1-92 को केस विजिलैन्स को दे दिया। उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है।

**श्री मनीराम केहरवाला:** स्पीकर सर, सारा हरियाणा जानता है कि कर्ण सिंह नैन उस समय के मुख्यमंत्री के पांचवें बेटे कहलाते थे। इनकी जो भी जायदाद है, उसके बारे में सारी इन्क्वायरी करवाई जाए।

**श्री ए०सी० चौधरी:** स्पीकर साहब इसमें विजायतें तो बहुत हैं लेकिन इन्साफ का तकाजा इस बात की मांग करता है कि भले ही वह दोशी हद से ज्यादा हो, लेकिन हर उस बात को जो रिकार्ड से सबसटांयिट हो सकती हो या जिसमें वजन मिलता है, वह जरूरी तौर पर इन्क्वायर हो। इन्क्वायरी रिपोर्ट में अगर वह दोशी पाया गया तो उसको बखसंगे नहीं।

**प्रो० सम्पत सिंह:** स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जवाब देते वक्त बताया है एक कम्प्लेंट आयी थी जो इन्होंने विजिलैन्स को भेज दी। विजिलैन्स ने कहा कि इसमें कोई केस बनता नहीं है। इसलिए

इसको फाईल कर दिया गया। जहां तक टैक्टफूल की बात करते हैं, यह बात इनकी बिल्कुल गलत है। अगर कहीं पर मेरे हाथ का लिखा हुआ शब्द मिल जाये या मेरी तरफ से साईन किया हुआ हो कि मैंने यह लिखा हो कि ऐसे मामलों में आप टैक्टफूल रहें, तो मैं देनदार हूँ। आज इस सरकार को आये हुए डेढ़ साल हो गया है। डेढ़ साल में स्पीकर साहब क्या इन्होंने इतना ही काम किया है कि 6 महीने के बाद उसको विजीलेंस को हैंड ओवर किया है? अभी तो इसकी विजीलेंस रिपोर्ट आनी बाकी है। एक साल हो गया है, दिसम्बर का महीना और है। इसका मतलब तो यह है कि इसमें से आप पोलिटीकल आउट-पुट निकालने के सिवाये और कोई बात नहीं कर रहे हो। अब मैं सही सवाल पर आता हूँ। क्या पिछले, दिनों जब इनके यहां पर ए०ई०टी०ओ० से ई०टी०ओ० की प्रोमो नन्ज हो रही थी और उनकी पोस्टिंग का चक्कर चला तो 40 लोगों की प्रोमो न करने बाद एक महीने तक उनकी पोस्टिंग पेंडिंग रखी गयी। इस बारे में चीफ मिनिस्टर साहब के पास रिक्वायत आयी कि एडी नल इ०टीसी० लैवल का अफसर कैसे ख गया। चीफ मिनिस्टर ने उसको सस्पेंड किया फिर उसको बहाल क्यों कर दिया गया? क्या कोई सौदा निश्चित हो गया इसलिये उसको बहाल कर दिया गया?

**श्री ए०सी० चौधरी:** स्पीकर साहब, के अन्धे को हरा ही हरा सूझता है अब इन्होंने बात भ्रु करी है तो सुन लें। मैंने यही कहा है यह बात आन रिकार्ड है। इन्होंने यह लिखा है:—

“Tactlessness was shown in collection of contribution to C.M’s Relief Fund, brings bad name . The issue seems to have snow balled and led to a strike of petroleum dealers.”

यह सोनीपत के पेट्रोल पम्प डीलर्स की एक कम्प्लेंट आयी थीं उसमें उन्होंने यह कहा था कि 11,000 से 21,000 रूपये हर पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फर्स्ट स्टेज पर टैक्स होकर आते हैं, वह टैक्स पे करके आते हैं, उनकी डायरेक्टली इन्वाल्वमेंट नहीं थी। जब वह लोग इनके काबू में नहीं आये या उन्होंने असमर्थता प्रकट की तो उनके ऊपर सख्ती करते हुए इतना कर दिया कि उनके उपर छापे मारे गये। आदमी को पीटा गया। उनको यह कहा कि हम ऐसे ही आपको भी पीटेंगे। उस वक्त इन्होंने हड़ताल की थी। तो उस फाईल पर मंत्री जी ने लिखा है:—

“No action is required at present. DETC, Sonapat may be asked to be more tactful in such matters.”

यह 14-2-1989 के दस्तख्त है। अगर मेरे भाई को अंग्रेजी न आती हो तो मैं इसका तरजुमा कर दूँ। (व्यवधान व भाोर) मैंने मंत्री कहा है, इनका नाम नहीं लिया है। जब एक रिक्वायट आयी कि इस अफसर ने करणान की, सी०एम० ने उसको सस्पेंड किया, तो स्पीकर साहब, इस सरकार को यह क्रेडिट जाता है कि यह सरकार बड़े से बड़े आदमी को भी नहीं बख्भाती। ( भाोर एवं व्यवधान)



**प्रो० सम्पत सिंह:** स्पीकर साहब, उसको बहाल इन्होंने क्यों किया? स्पीकर साहब, उसको अगले दिन ही बहाल कर दिया गया। ( तोर एवं व्यवधान)

**श्री ए०सी० चौधरी :** स्पीकर साहब, उको हमने एक महीने से ज्यादा सस्पेंड रखा था उसके बाद पैडिंग इंकवायरी बहाल किया है जब चारों तरफ से .....( तोर एवं व्यवधान)

**प्रो० सम्पत सिंह:** जब सौदा तय हो गया तो उसको बहाल कर दिया.....( तोर एवं व्यवधान)

**श्री ए०सी० चौधरी:** स्पीकर साहब, ये सौदा भाब्द इसतेमाल कर रहे है। ये मुझे सच्ची बात कहने के लिए मजबूर कर रह है। असली सरकार तो इस समय है सौदा करने वाली सरकार तो इनकी थी, जो चली गई। ( तोर एवं व्यवधान)

**श्री मनीराम केहरवाला:** स्पीकर साहब, क्या यह वही अफसर नहीं है, जिसका सुप्रिया कांड में जिक्र किया गया था? ( तोर एवं व्यवधान) क्या यह अफसर सुप्रिया कांड में गवाह नहीं था? ( तोर एवं व्यवधान)

**श्री ए०सी० चौधरी:** स्पीकर साहब, यह जो सवाल था, यह टैक्से इन से बाहर का है। यह वही अफसर था जिसकी कम्प्लेंट की गई है और वह सबस्टांि एट होती है। यह अफसर मौके पर था। स्पीकर साहब, यही अफसर था जिसने सुप्रिया कांड पर देवी लाल को रिपोर्ट की थी। ( तोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब जैसह कि मैंने पहले

अर्ज किया कि जो सवाल था, उसने इन सब बातों का कोई सम्बन्ध नहीं है। जो उसके बारे में कम्प्लेंट है, वह मैं। पढ़कर सुना देता हूँ:—

Shri K.S. Nain, D.E.T.C. absented himself from duty and he went to Chautala the day, the daughter-in-law of Shri O.P. Chautala expired and he phoned to Ch. Devi Lal for this happening.”

I mean to say that the rules are the same even for a peon or an Officer. How did he leave the station without permission?

**प्रो० सम्पत सिंह:** अगर किसी की मृत्यु हो जाती है क्या लोग जाते नहीं? क्या किसी के साथ पर्सनल रिले इंज नहीं होते? अकेले कोई औफिियर रिले इंज ही नहीं होते, किसी के भाई भतीजे भी अफसर लगे हुए हैं। क्या आपके घर में आपके साले की मृत्यु नहीं हुई? ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** इस मामले को आगे न बढ़ाएं, यही पर खत्म करें। अब श्री अमर सिंह धानक अपना सवाल पुट करें।

**सदस्यों का नाम लेना**

**प्रो० सम्पल सिंह:** स्पीकर साहब, यह मामला बड़ा गम्भीर है ( गोर)

**श्री धीरपाल सिंह:** .....

**प्रो० सम्पत सिंह:**.....

श्री सतबीर सिंह कादयान: .....

( गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ये जो भी कुछ मेरी इजाजत के बिना बोल रहे हैं, यह सब रिकार्ड न किया जाए। रिकार्ड पर कोई बात नहीं आएगी।

(इस समय श्री सम्पत सिंह, श्री धीरपाल सिंह, श्री सतबीर सिंह कादयान फिर बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष: सम्पत जी, आप बैठिये। ( गोर एवं व्यवधान)  
मिनिस्टर साहब फाईल में से पढ़कर बोल रहे थे and he has every right to read. (Interruptions)

मुख्य मंत्री: (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष माहेदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। ( गोर एवं व्यवधान)

श्री अमर सिंह: अध्यक्ष माहेदय, मुख्य मंत्री महोदय किस बात पर क्वै चन आवर में प्वायंट आफ आर्डर रेज़ कर रहे हैं? ( गोर) क्या क्वै यन आवर में प्वायंट आफ आर्डर होता है?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। it is for me to decide यह काम आपका नहीं है।

प्रो०सम्पत सिंह: .....

सिंचाई मंत्री: अध्यक्ष महोदय, आप इनको समझाएं, यह यहां सदन की मर्यादा में रहे और ठीक ढंग से बीहेव करें। ( गोर)

श्री धीरपाल सिंह: .....

श्री अध्यक्ष: जो भी दोनों तरफ से इस तर की बातें भुरु हुई है, वे रिकार्ड पर नहीं आएंगी। मिनिस्टर साहब ने जब से जवाब दिया है, वहां तक ठीक है। ( गोर)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, आप हमारी बात तो सुन रहे हैं और उसे रिकार्ड पर भी रहीं आने दे रहे है और उधर से जो कुछ कह रहे है, उनको आप मना नहीं कर रहे हैं? ( गोर)

**Mr. Speaker:** Sampat Singh Ji] I warn you. If you go out of the limits, you will be named.

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, आपको हमारी बात तो सुननी ही पड़ेगी। ( गोर)

**Mr. Speaker:** You cannot force me.

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मेरी आप से हम्बल रिक्वैस्ट है कि आप हमें मि से कि सुनें तो सही। ( गोर एवं व्यवधान)

**Mr. Speaker:** I warn you again. If you persist, I will have to name you. (interruptions) Sampat Singh ji, I name you. Please leave the House.

(At this stage Prof. Sampat Singh withdrew from the House.)

(At this stage Shri Dhir Pal Singh continued speaking without permission of the Chair.)

श्री धीरपाल सिंह: स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनें।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, धीर पाल सिंह जी, आप बैठिये।

श्री धीरपाल सिंह: हम आपसे रिक्वैस्ट कर रहे हैं। आप हमारी बात को सुनें तो सही ?

**Mr. Speaker:** Dhir pal Singh Ji, I also warn you. Please take you seat.

श्री धीर पाल सिंह: स्पीकर साहब आप हमारी बात को सुन तो लें।

**Mr. Speker:** I name Shri Dhir Pal Singh. He may please withdraw from the House.

(At this stage Shri Dhir Pal Singh withdrew from the House.)

श्री दरियाओं सिंह: स्पीकर साहब, हमें अपपनी बात कहने का तो अधिकार दें ( तोर)

श्री अध्यक्ष: अप बीच में न बोलें। जब में खड़ा हूँ तो आप बैठ जाएं।

(At this stage Shri Daryao Singh continued speaking without permission of the Chair.)

**Mr. Speaker:** Shri Daryao Singh Ji also name you. Please go out.

(At this stage Shri Daryao Singh withdrew from the House.)

### तारांकित प्र न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

#### **Expenditure incurred on Account of TA/DA etc. in Respect of the Chairman of Haryana Harijan Kalyan Nigam**

**Shri Amar Singh:** Will the Minister of State for Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes be please to state the month wise total expenditure incurred on account of bills of the telephone, TA/DA and residential accommodation of the present Chairman of the Haryana Harijan Kalyan Nigam from the date of his appointment to-date?

**मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):** विवरण विधान सभा के पटल पर रखा जाता है।

हरियाणा हरिजन कल्याण निगम के अध्यक्ष का दूरभाष, टी० ए०/डी० ए० और रिहायश पर किये गये खर्च का मासवार विवरण:—

समय	दूरभाष पर व्यय	मास	टी०ए०/डी० ए०	(आंकड़े रूपयों में) निवास स्थान का किराया
1	2	3	4	5

23-8-91 से 22-10-91	5244.00	8 / 91	2079.00	348.40
23-10-91 से 24-12-91	4965.00	9 / 91	750.00	1200.00
25-12-91 से 25-2-92	4290.00	10 / 91	750.00	1200.00
26-2-92 से 25-4-92	4330.00	11 / 91	750.00	1200
26-3-92 से 24-5-92	1009.00	12 / 91	750.00	1200
26-4-92 से 25-6-92	7099.00	1 / 92	750.00	1200
25-5-92 से 25-6-92	296.00	2 / 92	750.00	1200
26-6-92 से 25-7-92	3252.00	3 / 92	750.00	1200
26-8-92 से	6734.00	4 / 92	750.00	1200

25-10-92				
1-11-92 से 31-12-92	250.00	5 / 92	750.00	1200
		6 / 92	750.00	1200
		7 / 92	750.00	1200
		8 / 92	750.00	1200
		9 / 92	750.00	1200
		10 / 92	750.00	1200
		11 / 92	750.00	1200
कुल योग	37469.00		13329.00	18348.40

**श्री अमर सिंह:** स्पीकर साहब, 23-8-91 से 1-11-92 तक टेलीफोन टी०ए०/डी०ए० और एकोमोडे 1न का खर्चा 69,146.00 रुपए का आया है। मैं जानना चाहता हूँ कि हरिजन कल्याण निगम का कुल कितना बजट है और उसमें से हरिजन वelfैयर पर कितना खर्च किया गया?

**चौधरी भजन लाल:** अध्यक्ष महोदय, जहां तक चेयरमैन के खर्चे का ताल्लुक है, वह बहुत ही थोड़ा है। अमर सिंह जी आप भी



मंत्री रहे हैं और आप सारे आंकड़े देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि इस चेयरमैन का खर्चा बहुत थोड़ा है। जहां तक हरिजन कल्याण निगम के बजट 15 करोड़ रूपए का है और भोयर कैपिटल 13.75 करोड़ रूपए का है। इसमें से आधा पैसा भारत सरकार देती हैं। इस निगम के जरिए हम गरीब लोगों को भैंस के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए और मीन वगैरह खरीदने के लिए लोन देते हैं जिसमें 50 प्रतिशत सबसिडी देते हैं। लोन भी 4 प्रतिशत ब्याज पर देते हैं। आपने पूछा था कि इकसा बजट कितना है, यह मैंने बता दिया है। कुल बजट का दो प्रतिशत स्टाफ पर खर्च आता है और बाकी का पैसा लोगों के हित के लिए खर्च किया जाता है।

**साथी लहरी सिंह:** स्पीकर साहब, हरिजन कल्याण निगम की एक स्कीम थी जिसके तहत हरिजनों को जमीन दी जानी थी। उस स्कीम के तहत काफी लोगों ने जमीन के ब्याने भी दिए हैं लेकिन उनके केस रिजैक्ट कर दिए गए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जो स्कीम आपने चलाई थी, वह गवर्नमेंट आफ इंडिया की स्कीम है और उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पैसा नहीं देना है, तो क्या हरिजनों को दो-दो एकड़ जमीन दिलाई जाएगी?

**चौधरी भजन लाल:** अध्यक्ष महोदय, हमने हरिजन भाईयों को लोन देने के लिए जो स्कीम बनाई है, उसमें भारत सरकार की तरफ से सबसिडी भी मिलती है। सबसिडी भी उन हरिजन भाईयों को मिलेगी जिन्होंने लोन लेने के लिए एप्लीकेशन दे रखी है। जो भी हरिजन

भाई लोन के लिए कंडीशन पूरी करता है, उसको बजट की सीमा के अन्दर अवयव ही लोन दिया जाएगा।

**श्री पीर चन्द:** अध्यक्ष महोदय, हरिजन कल्याण निगम के चेयरमैन इति तहार छपवा कर यह आम मुनियादी करते फिर रहे हैं कि सरकार ने हरिजनों को लोन देने के लिए दो करोड़ रुपये दिए हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या उस निगम के चेयरमैन को इस तरह के इति तहार छपवा कर मुनियादी करने की पावर है और क्या वह हरिजनों को लोन दे सकेगा? इसे अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे माननीय सदस्य लहरी सिंह जी ने कहा है कि हरिजनों को जमीन देनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ कि हरिजनों को जमीन जरूर दी जानी चाहिए क्योंकि लगभग 500 हरिजन परिवारों ने जमीन के लिए जमींदारों को सिक्कोरिटी के तौर पर पैसे दिए हुए हैं, यदि उनको लोन नहीं मिला तो उनका वह पैसा मारा जाएगा और आप उनकी मदद करना चाहते हैं, वह नहीं होगी।

**चौधरी भजन लाल:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बात कही है कि इस निगम के चेयरमैन ने बहुत सारे इति तहार छपवा रखे हैं और मुनियादी कर रहे हैं कि सरकार ने हरिजनों को मदद के लिए दो करोड़ रुपये दिए हैं, आप ले लें। अध्यक्ष महोदय, चेयरमैन का यह काम है कि सरकार की जो पालिसी है या जो प्रोग्राम है, उसके बारे में लोगों को जानकारी दे। लोगों की मदद के लिए सरकार ने जो पैसा दिया है, उसके बारे में जानकारी दें। यह कोई बुरी बात नहीं है। वह तो अच्छा काम कर रहे हैं। आपको इस बारे में तकलीफ नहीं होनी

चाहिए। यदि वह लोन के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं तो इसमें बुरी बात नहीं है। इस निगम के चेयरमैन ने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा था, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। प्रजातन्त्र में कोई भी आदमी किसी के खिलाफ चुनाव लड़ सकता है।

**श्री पीर चन्द:** अध्यक्ष महोदय, केवल उन्होंने ही नहीं बल्कि मेरे खिलाफ तो 12 और आदमियों ने भी चुनाव लड़ा था। यदि उस चेयरमैन ने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह हरिजनों को मिएगाइड करें।

**श्री अध्यक्ष:** पीर चन्द जी, आप बैठ जाएं।

**साथी लहरी सिंह:** स्पीकर साहब, इनके सवाल का जवाब नहीं आया।

**श्री अध्यक्ष:** लहरी सिंह जी, आप कृप्या करके बैठ जाएं। इने सवाल का जवाब आ चुका है।

**चौधरी फूल चन्द मुलाना:** स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि हरिजन कल्याण लिनगम स्थापित होने के बाद हरिजनों को लोन के रूप में बहुत ज्यादा सुविधाएं मिली है और क्या उन्होंने उस पैसे से अपने काफी काम-धंधे भुरु किए है तथा उससे कुल कितने हरिजनों को फायदा हुआ है?

**चौधरी भजन लाल:** अध्यक्ष महोदय, इस स्कीम के तहत इस साल हमने लगभग 2 करोड़ 50 लाख रूपए जमीन के लिए हरिजनों को दिए हैं और वर्ष 1990-91 में 11518 हरिजन भाईयों को तथा 1992-93 में 6123 हरिजन भाईयों को लोन दिया गया।

**साथी लहरी सिंह:** स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन हरिजन भाईयों ने जमीन का ब्याना दे दिया, क्या उनको जमीन मिलेगी?

**चौधरी भजन लाल:** अध्यक्ष महोदय, अगर वे कंडीशन पूरी करते हैं तो हर हालत में जमीन मिलेगी।

**श्री अमर सिंह:** स्पीकर साहब, भारत सरकार ने खस तौर से हरिजनों को जमीन के लिए पैसा दिया है। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक कितने हरिजन भाईयों को जमीन मिली है?

**चौधरी भजन लाल:** चालू साल में 2 करोड़ 50 लाख रूपया रखा है और अगले साल इससे अधिक पैसा रखने जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक गरीब हरिजनों को फायदा पहुंच सके।

**श्री अमर सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि इस स्कीम के तहत अब तक कितने लोगों को जमीन दी गई और कितने लोगों को पैसा दिया गया है?

**चौधरी भजन लाल:** जहां तक जमीन देने का ताल्लुक है, वह एक अलग बात है। जमीन पर दो तरह से लोन दिया जाता है। एक

जमीन तो वह है जो सरप्लस से निकली है और हरिजनों को दी जाती है। जिसकी जमीन सरप्लस में निकलती है, उसको सरकार एकमु त पैसा देती है और फिर जिसको जमीन दी गई है, उससे कि तां में लेती है। दूसरे जो लोग प्राइवेट आदमियों से जमीन खरीदते हैं, उनको लोन दिया जात है। ऐसे लोगों को जिने पास दो एकड़ तक जमीन है, उनको लोन लेने की सुविधा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इस स्कीम के तहत हम अगले साल में ज्यादा पैसा रखने जा रहे हैं, ताकि अधिक गरीब हरिजनों को फायदा हो सके।

**श्री अमर सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो 2 करोड़ 50 लाख रूपया दिया है, उसमें से कितने लोगों को पैसा दिया गया?

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया)

### सदस्यों का नाम लेना

**श्री सतबीर सिंह कादयान:** अध्यक्ष महोदय, इस समय सदन के अन्दर विपक्ष के नेता नहीं हैं। उनके बगैर सदन सूना हो गया है.....

.....

**श्री अध्यक्ष:** कादियान जी, आप बैठिए।

**श्री सतबीर सिंह कादयान:** अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि आपने उनको नेम कर दिया जिस कारण अब वे हाऊस में नहीं है। उनके बगैर सदन सूना हो गया है .....

श्री अध्यक्ष: मेरी इजाजत के बगैर जो बोला जा रहा है वह रिकार्ड न किया जाये।

श्री सतबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय,.....

**Mr. Speaker:** Kadian ji, I warn you. Please take your seat, otherwise I will have to name you.

(At this stage Sh. Satbir Singh Kadian continued speaking without permission.)

**Mr. Speaker:** I name Shri Satbir Singh Kadian.

(At this stage Shri Satbir Singh Kadian withdrew from the House. The other members of the Janata Party also left the House.)

### तारांकित प्र न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री अमर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने बताया है कि भारत सरकार की तरफ से हरिजनों की वelfैयर के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपया आया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस पैसे के आने के बाद राज्य सरकार की तरफ से क्या-क्या कार्यवाही हुई? यानि मेरे कहने का मतलब यह है कि कितने हरिजनों को दो एकड़ जमीन दी गई और कितने लोगों को लोन दिया गया?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): 250 हरिजनों को हमने इस स्कीम के तहत 1-1 लाख रुपये चालू साल में दिया है और जैसा मैं

पहले दो-तीन बार कह चुका हूँ कि अगले साल के लिए और पैसा इस स्कीम में डाल रहे हैं। ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब हरिजनों को पैसा मिल सके।

### **Replacement of Old Buses**

**Shri Ram Bhajan Aggarwal:** Will the Minister of State for Transport be pleased to state-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to replace the old Buses by new one, if so, the number thereof; and

(b) Whether the Government intend to purchase the New Buses during the current financial year; if so, the number thereof?

**परिवहन राज्य मंत्री (श्री बलबीर पाल भाह):**

(क) जी हां, वर्ष 1992-93 के दौरान 521 बसों को नई बसों से बदलने का प्रस्ताव है।

(ख) जी हां, वर्ष 1992-93 के दौरान कुल 636 नई बसें खरीदने का प्रस्ताव है, (जिनमें बदली जाने वाली 521 बसें भी शामिल हैं)।

**श्रीमती चन्द्रावती:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से जानना चाहती हूँ कि दादरी डिपो में कितनी बसों के भीड़ खड़कियां टूटी हुई हैं और कितनी बसें रोजाना ब्रेक डाउन हो रही हैं? आम तौर पर हम देखते हैं कि लोहारू और दादरी के बीच में

बसे ब्रेक डाउन मिलती है। इसके साथ ही साथ कृप्या यह भी बता दें कि कितनी बसें टायर न होने की वजह से चल नहीं पा रही है?

**श्री बलहबीर पाल भाह:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मानीय सदस्या को यह बताना चाहता हूँ कि सारे डिपुओं की पोजी उन पर हमारी नजर रहती है। जहां तक सभी डिपुओं पर बसों की कमी का ताल्लुक है कुछ मिस-मैनेजमेंट की वजह से भी हो सकता है लेकिन कुछ समय पहले मण्डल कमी उन की रिपोर्ट पर चले आन्दोलन में जो कुछ हुआ, उसकी वजह से बसों का काफी नुकसान हो गया था। मुझे हाऊस में यह कहते हुए बड़ी भार्म महसूस होती है कि दादरी डिपो की हालत बसों के मामले में अच्छी नहीं है। इस साल इस डिपो में रिप्लेसमेंट के लिए 14 बसें दी जानी है। ये ऐसी बसें हैं जिनकी एवरेज लाईफ 8 साल हो चुकी होगी और 6 लाख किलोमीटर चल चुकी होंगी। इन 14 बसों में से 8 हमने भेज दी है, बाकी की बसें दिसम्बर के एण्ड में या जनवरी, 15 तक भेज दी जाएंगी स्पीकर सर, जाहं तक पुरानी बसों की रिपेयर का ताल्लुक है, हम को ि । । करेंगे कि सभी डिपुओ पर थोड़ा-बहुत रिपेयर का काम भी हो सके और रिपेयर के बाद सभी बसों की सेवा सुचारु रूप से चल सके। टायरों की कहीं को कमी नहीं है। जहां तक बसों के ब्रेक डाऊन हाने के सम्बन्ध है, इस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि पूरे दे । में हरियाणा की रोडवेज की दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में मिनिमम ब्रेक डाउन है।

**श्री राजेन्द्र सिंह बिसला:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, ने सदन को आ वासन दिया है कि 636 बसें खरीदी जाएंगी जिसमें से 521



रिप्लेस की जाएंगी और बाकी 115 नई बसें होंगी जो कि डिपुओं को दी जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, जिला फरीदाबाद की पलवल और बल्लबगढ़ तहसीलों में हरियाणा रोडवेज की बसों की परफारमेंस बहुत की पुअर है। अध्यक्ष महोदय, इन तहसीलों के कई गांवों के लगभग 200—200 लोग ऐसे हैं जो कर्मचारी हैं और नौकरी करने के लिए रोज दिल्ली जाते हैं। 3-3 घण्टे तक लोगों को बसें नहीं मिलती और वे वहां पर खड़े रहते हैं। मैंने मंत्री महोदय को स्वयं भी एक पत्र लिखा है परन्तु इसके बावजूद भी स्थिति में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इनकी कृपा दृष्टि हमारे जिला फरीदाबाद पर क्यों नहीं है?

**श्री बलबीर पाल भाह:** स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि फरीदाबाद जिले में 25 बसों की रिप्लेसमेंट इस वर्ष की जानी है जिसमें से 18 बसें दी जा चुकी हैं। यह बात ठीक है कि जितनी आवयकता है, बसें उससे कम। जितनी बसें इस समय चल रही हैं उनकी ऐवरेज परफारमेंस तकरीबन 4 प्रति 100 बढ़ी है। 1992-93 वर्ष के नवम्बर महीने तक बसों पर पर-फारमेंस की इफैक्टिवनेस 299 किलो मीटर रही जब कि दे 100 में निर्धारित इफैक्टिवनेस 300 किलो मीटर प्रति बस है (विघ्न) जहां तक माननीय सदस्य का कहना गांवों में बसें नहीं मिलती, तो मैं बताना चाहूंगा कि प्लानिंग कमीशन का जो प्रोग्राम है, उसके मुताबिक ही हम को 100 मिलाने का प्रोग्राम करेंगे। (विघ्न)

**श्री राजेन्द्र सिंह बिसला:** स्पीकर साहब, हमें प्लानिंग कमी उन से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने मंत्री महोदय से स्पैसिफिक सवाल पूछा है और मैं इस बारे में उनसे आवासन चाहता हूँ।

**श्री अध्यक्ष:** जो सवाल इन्होंने पूछा है, असप उसको आवासन इनको दीजिए।

**मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):** स्पीकर साहब, बिसला साहब ने जो सवाल पूछा है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। बिसला साहब ने स्पैसिफिक सवाल पूछा है। हर विधायक का फर्ज है कि वह अपने हल्के की तकलीफों को यहां सदन में रखें। स्पीकर साहब, डेढ़-दो साल पहले एक आन्दोलन चला था जिसमें बहुत सी बसों को जला दिया गया था। उस समय की सरकार ने खड़े रह कर बसों को जलवाया था। स्पीकर साहब, जब बाड़ खेत को खुद ही खाने लगे तो उस खेत का क्या हाल होगा? अध्यक्ष महोदय, जहां तक गांवों में बसों की कमी का सवाल है, हमने कुछ रूटों पर पब्लिक के पढ़े लिखे नौजवानों को जो बेकार हैं, रूट परिमित देने का फैसला किया है ताकि लोगों की तकलीफ दूर हो। जो लोग बेरोजगार हैं, हम चालते हैं, उनको भी रोजगार मिल जाए। हमने पिछले दिनों कैबिनेट में फैसला किया है और रत को मैंने पार्टी मीटिंग में भी बताया था कि हमने एक कमेटी बना दी है, उस कमेटी के मैम्बर जिलावाइज डिसाइड करेंगे कि कौन-कौन से रूट्स पर प्राइवेट बसें चलाई जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, अगर सारी डिटेल्स में अभी बताने लगूंगा तो काफी समय लग जाएगा। पालिसी के बारे में मैं बाद में बता दूंगा।

**श्रीमती चन्द्रावती:** अध्यक्ष महोदय, दादरी डिपो की लोहारु में जो बसें चलती हैं, वे बसें सब की सब बहुत ही खस्ता हालत में हैं। मैं मंत्री जी से यह आ वासन चाहती हूं कि ये सारी बसें जल्दी ही रिपेयर हो जाएंगी।

**चौधरी भजन लाल:** मैं भी यी कह रहा हूं कि बसें बहुत कम हैं और उनकी रिपेयर भी होने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, उन सभी बसों को जो लिंक रूट्स पर चलती हैं, हम ने इनल हाई-वे और स्टेट हाई-वे पर लगा देंगे। वहां पर जो प्रोब्लम होगी, वह भी दूर हो जाएगी। आप देखेंगे कि आने वाले महीनों में लोगों को इस पालिसी का कितना लाभ मिलेगा।

**श्री बीरेन्द्र सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि 521 बसें रिप्लेस करेंगे और 636 नई बसें खरीदेंगे। साथ ही मुख्यमन्त्री जी ने अभी कहा कि वे बेरोजगारों को छोटे-छोटे रूट्स पर प्राइवेट बसें चलाने का लाईसैंस देंगे। जब ये प्राइवेट बसों कके लाईसैंस दे रहे हैं साथ ही ये 636 बसें नई खरीदने जा रहे हैं, इसमें से 521 बसें रिप्लेस वाली हैं तो यह जो बाकी 115 नई बसे खरीदी जा रही है, यह क्यों खरीदी जा रही है?

**श्री बलबीर पाल भाह:** अध्यक्ष महोदय, यह जो योजना है, हमार विस्तार भी उसी के मुताबिक होगा और अगले साल जो एडी इन है, वह भी डालाह जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि आबादी बढ़ रही है और लोगों को जरूरीयात भी बढ़ रही है। अध्यक्ष माहेदय, हमारी

सरकार का वायदा है कि हमने लोगों को सुविधाएं देनी है। हम यह मानते हैं कि कई रूट्स को स्ट्रेंथन करेंगे और छोटे-छोटे रूट्स में लोगों को उठाएंगे। हरियाणा में लोगों को दिक्कत नहीं होगी, यह मैं आवासन देता हूँ।

**श्री राम भजन अग्रवाल:** अध्यक्ष महोदय, यह मेरा प्रश्न है और इस पर मुझे सप्लीमेंटरी पूछने का हक है। (गौर एवं व्यवधान) आप मुझे भी सवाल पूछने का मौका दें।

**श्री अध्यक्ष:** ठीक है, आप मुलाना साहब के बाद पूछ लेना।

**चौधरी फूल चन्द मुलाना:** अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के टाइम में कुछ बसिज जला दी गई थीं और कुछ मिनी बसिज खरीदी गई थी। मिनी बसों को खरीदने में गलती की गई थी। परिणामस्वरूप वे बसिज वायबल नहीं हैं और यह एक घाटे का सौदा है जिसकी वजह से सरकार को घाटा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, क्या उसी कारण से बसों की बहुत ज्यादा दिक्कत है?

**श्री बलबीर पाल भाह:** अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि जो 225 बसें खरीदी गई थीं, वे वाकई ही डिपार्टमेंट पर बोझ हैं और अन्दाजन इन बसों से 4 करोड़ का घाटा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि 1990-91 में जो 116 बसें रिप्लेस होनी थीं, अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि उस वक्त जो पिछली सरकार ने निर्णय लिया था, अगर वह निर्णय सोच समझ कर लेती तो इस सरकार को यह घाटा न होता। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि

मुलाना जी के हल्के में 24 बसों की रिप्लेसमेंट बनती है। अध्यक्ष महोदय, ये मिनी बसें बिल्कुल भी वायेबल नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा फ्लीट परफारमेंस 299 किलोमीटर पर बस है। अगर मिनी बसिज को निकाल भी दिया जाए तो यह एवरेज 310 किलोमीटर से ऊपर जाती है और जो 5.6 करोड़ रूपये का मुनाफा हुआ है, उससे भी कहीं अधिक का मुनाफा होता। यह सारा भार मिनी बसजि की वजह से, गलत पोलिसीज की वजह से और तोड़-फोड़ की वजह से हुआ है, इसलिए हमें ज्यादा दिक्कत आ रही है।

**श्री राम भजन अग्रवाल:** अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताने की कृप्या करेंगे कि भिवानी डिपो में टोटल बसें कितनी हैं और उन बसों के अन्दर कितनी बसें अनसर्विसेबल है? साथ ही क्या सरकार का इरादा इन अनसर्विसेबल बसों को रिप्लेस करने का है? अध्यक्ष माहेदय, इन खराब बसिज की वजह से सवारियों को बहुत दिक्कत आती है और उन्हें मैटाडोर आदि वाहनों में जाना पड़ता है जिससे स्टेट को काफी नुकसान होता है। इसलिए क्या मंत्री महोदय यह भी बताएंगे कि यह जो स्टेट को नुकसान हो रहा है, वह कितना हो रहा है और इस नुकसान की पूर्ति के लिये सरकार क्या कर रही है? अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह भी बताएंगे कि सरकार जो नयी बसें खरीद रही है, उनमें भिवानी डिपो में कितनी बसें आयेंगी?

**श्री बलबीर पाल भाह:** अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि सारे हरियाणा में फील्ड एवरेज 4.5 साल के लगभग है। भिवानी डिपो में जो बसें आठ साल से

ऊपर चल चुकी है यह 6 लाख किलोमीटर से ऊपर चल चुकी हैं, वे केवल 13 बसिज है। इनमें से 5 बसिज की रिप्लेसमेंट की जा चुकी है और बाकी 8 बसिज और की जाएंगी। जहां तक टूटी-फूटी बसिज हका सवाल है, उसके लिये मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछलो दिनों कुछ हादसा, मंडल कमी इन की वजह से हुआ था ( गोर एवं व्यवधान) सर, भिवानी में क्या हुआ? जो ट्रैक्टरों के ड्राईवर्ज थे, उनको भर्ती कर दिया गया और उनके हाथ में बसें दे दी गयीं। उन्होंने बसो का सत्याना कर दिया। इसके अलावा वहां पर बसों की काफी तोड़-फोड़ भी हुई जिसका खमियाजा अब जनता को भुगताना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम आज टूटी हुई बसों पर भी लागते है तो कल ही उनको तोड़ दिया जाता है सरकार कब तक इनको रिपेयर करती रहेगी? अब तो भिवानी के लोग खुद ही यह बताएं कि वह बसो की छतों पर भी गों को क्यों तोड़ते हैं? सर वहां से हऐसे बहुत से मामले सुनने को आ रहे है। ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री धर्मपाल सिंह:** स्पीकर सर, जैसा कि मानीय मंत्री जी ने बताया कि भिवानी जिले के अन्दर 13 बसिज बदलनी है, 5 तो बदल दी है लेकिन बाकी बसिज अभी नहीं बदली है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि दादरी डिपो के अन्दर कितनी बसें ऐसी है जो बदलने के काबिल हैं और उनमें अब तक कितनी बसें बदल दी गयी है और कितनी अगले साल में बदलने का विचार है? साथ ही मंत्री जी यह भी बताएं कि इस साल कुल कितनी बसिज इन्होंने खरीदी है और इनमें से कितनी दादरी डिपो को दी है? क्या मंत्री जी का दादरी डिपो को बन्द

रखने का विचार है या कुछ और बसिज देकर दादरी डिपो को चालू रखने का विचार है? इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या दादरी डिपो में ट्रैक्टरों के ड्राईवर्ज भी भर्ती हुए हैं? अगर हुए हैं तो क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी?

**श्री बलबीर पाल भाह:** स्पीकर सर, दादरी डिपो में 108 बसें हैं इनमें से कुल 14 बसें इस साल बदलने का प्रावधान है और 14 में से 8 बसें इस कार्य हुतु दी जा चुकी है। जहां तक ऐडी इनल बसिज देने का सवाल है, जब हम पुरानी बसों को बदल लेंगे तक रिकवायरमेंट को देखकर, हम नयी बसों को ऐलोके इन करेंगे, उसमें ऐसा कोई संशय नहीं होना चाहिये। जहां तक अगले साल का सवाल है, मेरे पास अभी सूचना नहीं है, उन्हे निर्देश दे दिए गए हैं कि वे अच्छी तरह चलाना सीख लें और अब वे सीख भी गए हैं।

### **Primary Schools Run in Private Buildings**

**Shri Karan Singh Dalal:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the total number of Primary Schools functioning in private buildings in Faridabad district;

(b) Whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the buildings for the Primary Schools as referred to in part (a) above; and

(c) If so, the time by which the buildings for the schools as referred to in part (a) above are likely to be constructed?

**शिक्षा मंत्री (श्रीमती भान्ति राठी):**

(क) जिला फरीदाबाद में ऐसे 14 राजकी प्राथमिक विद्यालय हैं।

(ख) जी हां, 5 स्कूल भवनों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(ग) निश्चित समय अवधि बताना सम्भव नहीं।

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जहां उन्होंने यह माना है कि 14 स्कूल ऐसे हैं जो गैर-सरकारी इमारतों में चल रहे हैं और पांच स्कूल भवनों को बनाने का प्रस्ताव है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि दो प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनकी इमारतों की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है और ये कभी भी गिर सकते हैं गांव के लोगों के बार-बार कहने के बावजूद भी इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो प्राइमरी स्कूल बहुत खस्ता हालत में है, उनके बारे में ये क्या करने जा रहे हैं?

**श्रीमती भान्ति राठी:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि जो कुछ उन्होंने पूछा है इस बारे में पूरा विवरण मेरे पास इस वक्त उपलब्ध है। जहां तक आपने दो और स्कूलों का जिक्र किया है, उसके बारे में आप अलग से नोटिस दें तो हम उसका जवाब दे देंगे।



## **Gosadan in the State**

**Smt. Chandrawati:** Will the Minister of State for Animal Husbandry be pleased to state-

(a) the districtwise number of Gosadan in the State together with the location and number of animals in each Gosadan at present; and

(b) whether any funds have been earmarked for above said Gosadans during the current financial year?

**आवास राज्य मंत्री (राव धर्मपाल):**

(क) केवल दो गौसदन राज्य में काय्रत है, जो हिसार तथा माण्डेवाला (जिला यमुनानगर) में सिथत है। इस समय हिसार में 432 तथा माण्डेवाला में 126 पंजु है।

(ख) चालू वित्त वर्ष के बजट में 5.25 लाख तथा 2.39 लाख रूपये की राशि क्रमशः हिसार तथा माण्डेवाला गौसदन के लिए प्रावधान है।

**श्रीमती चन्द्रावती:** स्पीकर सर, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती थी कि कुल कितने गौसदन हैं?

**राव धर्मपाल:** बहिन जी, प्रदेश में 92 गौसदना हैं और गौसदन सिर्फ दो ही हैं।

**श्रीमती चन्द्रावती:** स्पीकर सर, मैंने गौसदना और गौसदन को एक मानकर सवाल पूछा था।

**श्री अध्यक्ष:** चन्द्रावती जी, आप गौ ाला के बरें में अलग से पूछ लें ।

**राव धर्मपाल:** गौसदन का मतलब यह है कि वहां पर नकारा और बेकार प ़ु पाले जाते है । गौ ाला में हर तरह के प ़ु पाले जाते है ।

**श्रीमती चन्द्रवती:** स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि बीमार या जिन प ़ुओं का ऐक्सीडैन्ट हो जाता है, ऐसे प ़ुओं को गौ ाला यह गौसदन में पहुंचाने का क्या कोई इन्तजाम आपके पास है?

**राव धर्मपाल:** अध्यक्ष महोदय, इस काम के लिए हमारे पास कैटल कैचिंग पार्टी होती है । यदि किसी की नजर मे कार्ई बीमार प ़ु होता है तो वे डभ०सी० या म्युनिसिपल कमेटी के प्रजीडैण्ट को अनुरोध करते हैं या जो प ़ु फसल उजाड़ते है, ऐसे प ़ुओं को हमारी कैटल कैचिंग पार्टी ट्रक में बैठाकर ले जाती है ।

**श्रीमती चन्द्रावती:** स्पीकर सर, इन प ़ुओं को कैटल कैचिंग पार्टी नहीं ले जाती है । दो जगहों पर तो मैंने देख है । जींद में मैंने देख है कि बीमार और ऐक्सीडैण्डलन प ़ु सड़क पर पड़े रहते है, भूखे मरते है । वे बाजारों की गंदगी खकर बीमार हो जाते है । ऐसे प ़ुओं को वहां से ले जाने का सरकार कोई न कोई इन्तजाम करना चाहिये । इस तरह का अब तक कोई इन्तजाम नहीं है । उप प ़ुओं पर कोई पैसा खर्च नहीं किया जात है ।

**राव धर्मपाल:** स्पीकर साहबख अक तक बहिन जी की तरफ से कोई रिपोर्ट कायत इस बारे में हमारे पास नहीं आयी है। आगे यदि यह कोई ऐसी रिपोर्ट कायत करेगी तो हम उसको एग्जामिन करायेगे और जरूरी कार्यवाही करेगे। (व्यवधान एवं भाोर)

**श्रीमती चन्द्रावती:** स्पीकर साहब, हमारे पास एक यही काम नहीं रह गया है कि हम पंजाब के बारे में सरकार को बताते रहें। (व्यवधान एवं भाोर)

**राव धर्मपाल:** जहां जहां से हमें ऐसी रिपोर्ट मिलती है, हम इस तरह के पंजाब को मंगवाकर गौंवालाओं में भिजवाते हैं।

**श्रीमती चन्द्रावती:** हिन्दू कहलाने वाले लोगों को ईमानदारी से अपने आप गौंवालों की रक्षा करनी चाहिये। मैं इस बात का मुख्य मंत्री महोदय से आवासन चाहूंगी कि ऐसे पंजाब के लिये सरकार द्वारा गौंवालाओं और गौंसदनों में ठीक से इन्तजाम किया जायेगा और बीमार और आवार पंजाब को यहां पर गौंवालाओं, और गौंसदनों में रखा जायेगा, मैं इस किस्म का आवासन मुख्य मंत्री महोदय से चाहूंगी। (व्यवधान एवं भाोर)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

**साथी लहरी सिंह:** स्पीकर साहब, यह एक बड़ा ही सीरियस क्वेश्चन है। आप चण्डीगढ़ से पंचकूला भाहर की तरफ आते हैं। पंचकूला भाहर में कोई भी ऐसी सड़क नहीं है, जहां 10-20 गायें सड़क पर न बैठी हों। यहीं नहीं, आप किसी भी हरियाणा के भाहर में चले

जायें, सारे भाहरों में बुरी हालत है। गौएं भाहरों में रास्ते रोके खड़ी रहती है। ऐसे बेचारे और बेसहार पशुओं की देखभाल के लिये सरकार का क्या नजरिया है? आज जितने भी मांस खाने वाले आदमी हैं उनको .....

**श्री अध्यक्ष:** ऐसी चीज को रिकार्ड न किया जाये।

**एक आवाज:** ये क्या बात करते हैं।

**साथी लहरी सिंह:** .....

**चौधरी भजन लाल:** यह इतनी सीरियस बात नहीं थी जितनी बना दी गयी है। मानवता का एक ही धर्म है। गऊ जिसको हम लोग माता कहते हैं, उसकी रक्षा करना हमारा सब का परम कर्त्तव्य बनता है। लेकिन चौधरी लहरी सिंह ने ऐसी बात कह दी कि मांस खाने वाले भायद गऊ का मांस भी ख लेते होंगे।

(व्यवधान व भोर).....

**साथी लहरी सिंह:** मैंने ऐसा नहीं कहा है। होटलों में जहां पर मांस बनता है, वहां पर क्या पता चलता है कि वह गाय का मांस है या किसी दूसरे जानवर का है?

**चौधरी भजन लाल:** जहां तक गऊओं के रख-रखाव का ताल्लुक है? उसके लिये गौ-सदन है और गौ आलाएं है। जहां से भी हमारे पास मांग आती है, हम हर गौ आला की उतनी मदद करते हैं जितनी उनको जरूरत होती है जहां पर चारा नहीं होता चारा भिजावाने

की कोर्िाा करते हैं चा पैसा भिजवाते हैं, उनकी पूरी देखभाल हम करवाते है। लेकिन हमारे समाज का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि जो अवारा गरुंए फिरती है, उनकी तरफ ध्यान दें। यह कोई अच्छी बात नहीं है कि जब तक गाय दूध देती है, तब तक हम उसको रखते हैं और जब दूध देना बंद कर देती है, सूख जाती है तो उसका रस्सा खोलकर छोड़ देते है। क्या कोई अपने मां बाप को इस तरह से छोड़ता है। हमें ऐसी गरुओं को नहीं छोड़ना चाहिये जिससे कि वे मंडियों में या इधर उधर मुंह मारती फिरती रहें। इसलिये लोगों का धर्म बनता है कि हम गरु की सेवा करें और हमारे दिमाग में सेवा का भाव होना चाहिए। स्पीकर साहब, जहां से भी हमें लिखकर आता हैं कि फलां गरु ाला की हालत ठीक नहीं है, तो हम उसकी मदद करते है। स्पीकर साहब, मैं सभी माननीय सदस्यों को वि वास दिलाना चाहता हूं कि अगर वे लिखकर भेजेगें कि किसी गरु ाला कि हालत ठीक नहीं है तो हम उस गरु ाला की मदद करेंगे। हम पूरी कोर्िाा करेंगे। ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र सिंह बिसला:** आन ए प्वायंट आफ आर्डर। ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप सब लोग बैठ जाएं उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी।

**श्री राजेन्द्र सिंह बिसला:** आन ए प्वायंट आफ आर्डर। ( गोर एवं व्यवधान)

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गये)

**श्री अध्यक्ष:** आप सब लोग बौठ जाएं उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी। ( तोर एवं व्यवधान) आप बैठ जाइए, फिर आपकी बात सुनी जाएगी ( तोर एवं व्यवधान) राजेन्द्र सिंह जी, आप बैठ जाओ फिर आपकी बात सुनेंगे। ( तोर एवं व्यवधान) उन्होंने अपनी बात रैक्टीफाई कर दी है। ( तोर एवं व्यवधान)

**चौधरी भजन लाल:** चौधरी लहरी सिंह का मतलब यह था कि जो लोग मांस खाते हैं उनमें गाय का मांस मिलाया जा सकता है। उन्होंने अपनी बात साफ कर दी है। ( तोर एवं व्यवधान)

**Mr. Speaker:** Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारंकित प्र नों के  
लिखित उत्तर

### **Desilting of Distributaries**

**Shri Chhattar Singh Chauhan:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state-

(a) Whether the Government is aware of the fact that the Distributaries, Minors and Sub-minors in district Bhiwani have not been desilted for the last few years; and the reasons therefor; and

(b) If so, the time by which the afore-said distributaries, minors and sub-minors are likely to be desilted?

सिंचाई मंत्री (चौधरी जगदी ा नेहरा):

(क) जिला भिवानी में डिस्ट्रीब्यूट्रीज, माईनरों तथा सब-माईनरों की प्रत्येक वर्ष में आव यकतानुसार एंव धन की उपलब्धि पर सफाई करवाई जा रही है ।

(ख) 11/92 तक 269.47 किलोमीटर लम्बी भिन्न भिन्न नहरों की सफाई की जा चुकी है ।

**Construction of a Bridge on Badhana&Kuchrana Khurd  
Distributary**

**Shri Ram Kumar Katwal:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bridge on the Badhana&Kuchrana Khurd distributary in Rajaund Constitutency; if so, the time by which it is likely to be constructed?

सिंचाई मंत्री (चौधरी जगदी ा नेहरा): हां ।

इस पुल का निर्माण कार्य अगले वित्तीय वर्ष में किए जाने का प्रस्ताव है ब ार्ते कि धन राि ा उपलब्ध हो ।

**Construction of Road**

**Shri Pir Chand:** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a link road form village Hajrawa to Ali Sadar in Hisar district during the year 1992-93?

लोक निर्माण मंत्री (भवन एवं सड़कें) (श्री आनन्द सिंह डांगी): रतिया निर्वाचन क्षेत्र में गांव हजरावां खुर्द से सदर अली तक पहुंच मार्ग, संभवतः संदर्भित सड़कों का निर्माण पहले ही वर्ष 1984-85 में कर दिया गया है।

### **Judicial Court**

**Shri Krishan Lal:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) Whether there is any proposal under, consideration of the Government to set up a Judicial Court in Sub-Division Assand in district Karnal; and

(b) if so, the time by which the said court is likely to start functioning?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) जी हां।

(ख) मामला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः समय निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता।

### **Power Projects**

**Shri Jai Parkash:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the efforts so far made by the present Government to expedite the construction of the Super Thermal Power Plant



Project at Yamuna Nagar, Gas-based Power Plant at Faridabad and Hydro Power Project at Dadupur; and

(b) the time by which the aforesaid projects are likely to be constructed/completed?

**मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):** (क) तथा (ख) विवरण सदन के मेज पर प्रस्तुत है।

### विवरण

(क) हरियाणा राज्य द्वारा किए गए अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप यमुनानगर थर्मल पावर परियोजना के चरण-1 (2+210) मैगावाट पर कार्य भारत सरकार के राष्ट्रीय थर्मल पावर कार्पोरेटान (निगम) द्वारा प्रारम्भ किया गया था। आरम्भिक सिविल निर्माण क्रियाकलापों (एक्टीवीटज) में पर्याप्त प्रगति हुई, जिसपर अब तक राश्ट्रक्रीय थर्मल पावर कार्पोरेटान 5 करोड़ रूपये से अधिक खर्च कर चुका है। चूंकि राश्ट्रक्रीय थर्मल पावर कार्पोरेटान के अपने निवेशनीय वैकल्पिक स्रोत समाप्त हो चुके हैं इसलिए भारत सरकार धन के वैकल्पिक स्रोत की तलाश में है। यदि भारत सरकार ऐसा भीघ करने में असफल हो जाती है तो राज्य सरकार ने राज्य क्षेत्र में इस परियोजना को क्रियान्वित करने की पेशकश की है। फरीदाबाद गैस पर आधारित पावर प्रोजैक्ट के लिए भी प्रस्ताव प्रथम चरण में 400 मैगावाट की क्षमता का बेस लोड पावर स्टेजान के रूप में कार्यन्वयन के लिए राष्ट्रीय थर्मल पावर कार्पोरेटान द्वारा प्रक्रियाधीन है। इस परियोजना के लिए धन की व्यवस्था को राष्ट्रीय थर्मल पावर

कापोरे इन द्वारा आन्तिम रूप दिया जा रहा है और राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना को भुरु करने के लिए सत्त प्रयास किए जा रहें है ।

जहां तक दादुपुर लघु परियोजना का सम्बन्ध है, यह परियोजना प्रस्तावित वृद्धि नहर पर दादुपर हैड वर्कस के 6.5 कि० मी० पर डाऊन स्ट्रीम पर स्थित की जानी थी जिसको कि वि व बैंक की सहायता से धन मिलता था। इस परियोजना के क्रियान्वन को तेजी से करने के विचार से अब इसको दादुपुर हैड वर्कस पर क्रियान्वयन करने के लिए पुनः प्रस्ताव किया गया है। सं गोधित परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं की पूर्व योग्ताओं का आकलन के लिये टैण्डर जारी कर दिये हैं तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया के अधीन है।

(ख) कार्य आरम्भ करने के प चात उपरोक्त परियोजनओं के निर्माण के लिये लगने वाला सम्भावित समय निम्न प्रकार से है:—

(1) यमुनानगर थर्मल विद्युत परियोजना 4 से 5 वर्ष तक।

(2) फरीदाबाद में गैस पर आधारित पावर प्लांट 2 से 3 वर्ष तक।

(3) दादुपर लघु जलीय परियोजना 3 से 4 वर्ष तक।

**Categorywise Number of Posts in Cooperation Department**

**Shri Amar Singh:** Will the Minister for Cooperation be pleased to state-

(a) The total number of class 1, and class II, class III and class IV employees belonging to Scheduled Castes working in the Cooperation Department as at present; and

(b) Whether there is any short fall in the reservation; if so, the time by which the short fall is likely to be wiped off?

**सहकारिता मंत्री (श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया):**

(क) सहकारिता विभाग में इस समय श्रेणी प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ के अनुसूचित जाति से सम्बन्धित कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है:—

श्रेणी प्रथम	5
श्रेणी द्वितीय	5
श्रेणी तृतीय	319
श्रेणी चतुर्थ	88

(ख) श्रेणी 1, श्रेणी II व श्रेणी 4 में अनुसूचित जातियों के आरक्षण में कोई कमी नहीं है फिर भी श्रेणी तीन के पदों के आरक्षण में कुछ कमी है जिनकी स्थिति निम्न प्रकार है:—

वरिष्ठ लेख परीक्षक 2

निरिक्षण (आडिट) 1

जहां तक कमी को पूर्ण करने में समय लगने का सम्बन्ध है, इस बारे में प्रस्तुत है कि इस कमी को आरक्षण नीति अनुसार भविष्य में भरने वाली रिक्तियों से पूरा किया जाएगा।

### **Tubewells Connections**

**Shri Ram Bhajan Aggarwal:** Will the Chief Minister be please to state-

(a) the total number of electricity connections for Tubewells released in district Bhiwani during the current financial year 1992-93 to date.

(b) whether any applications for the Tubewells Connections are lying pending as at present in District Bhiwani; if so, the number thereof; and

(c) The steps, if any, taken or proposed to be taken by the Government to expedite the release of connections as referred to in part (b) above?

**मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):**

(क) जिला भिवानी में अक्टूबर 1992 तक ट्यूबवैलों के 164 बिजली कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं।

(ख) जिला भिवानी में दिनांक 31-10-92 तक ट्यूबवैल कनेक्शनों के 5142 आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हुए हैं।

(ग) पिछले वर्ष ट्यूबवैलों को तेजी से बिजली देने का एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था जिसके कुछ हिस्से के रूप में अक्टूबर 1991 से मार्च, 1992 तक की अवधि में जिला भिवानी में 775 ट्यूबवैल कनेक्टान जारी कर दिये गये थे। जबकि पिछले वर्ष की तदनुसार अवधि के दौरान केवल 262 कनेक्टान जारी किये गए थे। वर्ष 1990-91 में 338 कनेक्टानों की तुलना में वर्ष, 1991-92 में कुल 880 ट्यूबवैल कनेक्टान जारी किए गए थे।

### अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

#### **Realiation of Amount in District Faridabad**

**Shri Karna Singh Dalal:** Will the Minister of State for Transport be pleased to state the total amount realized through various challans/fines imposed by the Secretary, R.T.A., Faridabad and G.M., Haryana Roadways, Faridabad during the calendar year 1992 to-date in District Faridabad?

**परिवहन राज्य मंत्री(श्री बलबीर पाल भाह):** सचिव आर०टी०ए० फरीदाबाद व महाप्रबन्धक, हरियाणा फरीदाबाद द्वारा विभिन्न चालानों/जुर्मानों द्वारा 1992 के कलेंडर वर्ष (जनवरी 1992 से नवम्बर 1992 तक) में निम्नलिखित धन राशि एकत्रित की है:—

1 महाप्रबन्धक,

हरियाणा राज्य परिवहन, फरीदाबाद 12,45,976.00

रु०

2 सचिव

आर०टी०ए० फरीदाबाद

(गुडगांव तथा फरीदाबाद जिला)

53,58,595.00

रु०

---

योग 66,04,571,.00 रु०

---

### सदस्यों का नाम लेना/उनको वापिस बुलाना

(इस समय प्रो० सम्पत सिंह ने हाउस में प्रवे । किया तथा सीट पर आकर बैठ गये)

**श्री अध्यक्ष:** सम्पत सिंह जी, आप हाउस में कैसे आ गए है? आपको तो नेक कर दिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था?

**चौधरी भजन लाल:** स्पीकर साहब, ये कैसे आ गए? ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको निकाल देना चाहिए।

**प्रो० सम्पत सिंह:** अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बैठ जाता हूँ।

**श्री धीरपाल सिंह:** स्पीकर साहब, हम सभी आपके आदे । का पालन करेंगे।

**श्री अध्यक्ष:** अगर आप ऐसी रिव्वैस्ट करते हैं तो मैं उन आर्डर्ज को रिवोक कर सकता हूँ। ( तोर एवं व्यवधान) अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने अपने को अमैण्ड कर लिया है। (व्यवधान)

**श्री सतबीर सिंह कादयान:**स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब डिक्टे इन दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।

**प्रो० सम्पत सिंह:** मैं आपके आदे 1 का पालना करूंगा, मैं आपको वि वास दिलाता हूँ।

**श्री अध्यक्ष:** अगर आदे 1 की पालना करेंगे तो आर्डर्ज रिवोक किये जाते हैं और अब आप डिस्क इन में भाग ले सकते हैं।

### **प्रैस वालों पर हमला**

**श्री राजेन्द्र सिंह बिसला:** अध्यक्ष महोदय, आने मुझे दो मिनट दिए, इसके लिए आपका धन्यावाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि कल 6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में मस्जिद गिराने के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव सदन के नेता ने, सदन के अन्दर प्रस्तुत किया था इस घटना की सारे दे 1 के लोगों ने भर्त्सना की है व निन्दा की है। इसी सम्बन्ध में, मैं सारे सदन से आग्रह करूंगा कि जिस तरह से मस्जिद गिरा कर इन लोगों ने सारे दे 1 की जनता की भावनाओं को ठेस पहुँचाई है, उसी के साथ हमारे प्रैस के भाइयों के साथ भी वाहं पर बड़ा दूर्व्यवहार किया गया है। हमारे दे 1 के अन्दर प्रैस को पूरी आजादी है उस को भी हमारे संविधान के अनुसार

अपने विचार प्रकट करने का पूरा हक है। प्रैस के अपने फण्डेमैन्टल राईट्स हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जर्नलिस्ट लेडीज पत्रकार के कपड़े तक इन लोगों ने फाड़ दिये। प्रैस वालों के कैमरे तक तोड़ दिये गये, इस सभी हरकातोां को हमें पूरी तरह से कंडैम करना चाहिये। प्रैस वालों को वहां तक जाने नहीं दिया गया उनको आगे जाने से रोका गया उनको मारा पीटा गया। यह कितनी निन्दास्पद बात है। उन प्रैस वालों ने दे आ के राष्ट्रपति को इस सम्बन्ध में एक मैमोरैन्डम दिया है। इसलिये मेरी इस सारे सदन से प्रार्थना है कि मेरे इस सुझाव को भी इस प्रस्ताव के साथ जोड़ दिया जाए। (धन्यवाद)

**मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल):** अध्यक्ष महोदय, बिसला साहब ने ठीक बात कही है। कल हमारे से यह मिस हो गया था। उनके इस सुझाव को भी उसी निन्दा प्रस्ताव के साथ जोड़ दिया जाए। ( गोर एवं व्यवधान)

**आवाजें:** राम सिं बराड़ को मारने की धमकी दी गई थी, उस में भी सदन विचार करें। ( गोर एवं व्यवधान)

**चौधरी भजनलाल:** अध्यक्ष महोदय, ये किस की बात कर रहे हैं? जो कुछ सिरसा से हुआ जो मेहम में प्रैस वालों के साथ लोगों ने करवाया, वह किसी से भूला हुआ नहीं है। दे आ के लोगों से पूछो। अयोध्या के अन्दर प्रैस वालों के साथ आप लोगों ने क्या करवाया, वह भला दे आ में किस से छिपा हुआ है?( गोर एवं व्यवधान)



श्री अध्यक्ष: यह बात रेजोल्यूशन में तो नहीं जोड़ी जा सकेगी लेकिन जो हाउस फीलिंग्स हैं, वे कन्वे कर दी जाएंगी।

चौधरी भजन लाल: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। It is unanimously agreed.

### ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

सरकार को किसान विरोधी नीतियों के कारण हरियाणा में कृषि अर्थव्यवस्था में गिरावट आने संबन्धी

**Mr. Speaker:** Hon'ble Members, I have received a notice of an adjournment motion from Shri Sampat Singh and 14 other members of his party regarding collapse of agricultural economy in Haryana because of anti-farmers policies of the Government. I have converted it into calling attention motion and also admitted it. Shri Sampat Singh may read his notice and the concerned Minister may make a statement thereafter.

1 प्रो० सम्पत सिंह 2 श्री धीरपाल सिंह 3 श्री धीरपाल सिंह 4 सरदार जसविन्द्र सिंह 5 चौ० जिले सिंह जाखड़ 6 चौ० बलवन्त सिंह मैना 7 श्री कृष्ण लाल 8 श्री राम कुमार कटवाल 9 श्री दरयाओं सिंह राजौरा 10 श्री मनी राम 11 श्री अमर सिंह ढांडे 12 श्री मोहन लाल पिप्पल 13 चौ० सूरजभान काजल 14 श्री रमेश कुमार 15 चौ० भरथ सिंह

(इस महान सदन का ध्यान एक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं, अर्थात् सरकार की किसान विरोधी नीतियों के

कारण हरियाणा में कृषि अर्थव्यवस्था में गिरावट पिछले साल की तुलना में खाद बीज बिजली डीजल कीटना तक दवाइयों तथा खेती मीनरी की कीमतें लगभग दुगनी हो गई है, जबकि कृषि उत्पादों की कीमतें आधी रह गई है। इस सबसे बढ़कर बिजली और सिंचाई पानी की भारी कमी है। स्थिति यहुं तक पहुँच गई है कि खेती करके जीविका कमाना एक खतरे वाला साधन बन गया है। अतः सरकार से निवेदन करते हैं कि वह इस सम्बन्ध में सदन में एक वक्तव्य दे।)

### वक्तव्य—

कृषि मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

Agriculture Minister (Sh. Harpal Singh): Considering that agriculture is a dominant sector of the economy of Haryana, State Government have made concerted efforts for increasing the production and productivity of all major crops in the State and there by increase income of the farmers. As a result of these efforts all time high and record production has been achieved in case of wheat, cotton, sugarcane, oilseeds etc. during the year 1991-92. This tempo has been maintained and the state is likely to harvest the foodgrains production of more than 100-00 lakh tonnes during 1992-93. Likewise, the production of cotton and oilseeds is likely to touch a new height of 14.50 lakh bales and 8.50 lakh tonnes, achieved duringh 1991-91. These production levels are records in themselves. There is no denying the fact that prices of agricultural inputs have slightly increased over the last year but increase in production has more than offset the impact of increased prices and in totality, the farmers have gained larger income over the last year.

The prices of fertilisers seeds and pesticides have not doubled as alleged. The DAP fertilisers after allowing subsidy is being sold at Rs. 350 per bag as against Rs. 234 per bag during last year. On the other hand the prices of CAN and urea have been reduced from Rs. 140 to Rs. 100 per bag of CAN and Rs. 153 to Rs. 138 per bag of urea showing a reduction of 29% and 10% respectively.

In case of seed, the rise in prices has been nominal, which goes up with the increase of procurement/market prices of these commodities and the benefit of this increase goes to the seed grower farmers.

The overall price rise in case of pesticides is about 10% but in case of isoproturon (wheat weedicides), there is no increase at all.

Position of irrigation and power supply to the farm sector has been very good. Indeed, the power supply to farm sector is being given on Priority basis. During 1990-91, 242 crore units of power were supplied to the farm sector whereas during 1991-92, it went up to 320 crore units and it may further touch a level of 380 crore units during 1992-93. It may be pointed out that per unit cost of production comes to Rs. 1.20 whereas only Re. 0.50 is being charged from the farmers. As a result of this, HSEB is likely to bear a loss of Rs. 266.00 crores during 1992-93. Thus, even after the modest increase in the power rates agricultural sector would continue to receive power at highly subsidised rates.

The pace of mechanisation of farm operations is on an increase. At present, there are 1.33 lakh tractors and 10.85 lakh assorted farm implements (like Harrows, cultivators, seed drills and

threshers etc.) the price of tractor have increase by 4% to 5.5% of different makes and that a implements by 10% over the last year. The Government with a view to providing relief to the small and marginal farmers has sanctioned a scheme for subsidising the cos to small tractors @ Rs. 30,000 per tractor of 18 H.P. or less.

The farmers continue to receive remunerative price of various crops during the current year, through last year the prices were unusually high. The price of cotton this year range between Rs. 1065 to Rs. 1115 per Qtl. as against Rs. 870 per qtl. in 1990-91. The price of Basmati paddy this year range between Rs. 800 to Rs. 1200 per qtl. as against Rs. 560 per qtl. in 1990-91 and Rs. 435 per qtl. in 1988-89.

It may be mentioned that Government of India announced an increase of Rs. 4 per qtl. in the support price of paddy this year which is all time highest increase. Earlier this, increase used to be quite nominal ranging from Rs. 3 to Rs. 10 per qtl. Similarly in case of support price of wheat the increase last year (1991-92) was the highese i.e. Rs. 55 per qtl., whereas earlier this increase was of the order of Rs. 5 to Rs. 10 per qtl. Gopvernment of India is expected to announce the minimum support price of rabi crops shortly and it is expected that the farmers will get remunerative price for rabi crops with sufficient increase to cover increae in cost of various inputs.

**प्रो० सम्पत सिंह:** स्पीकर साहब, मानीय मंत्री जी ने यह माना है कि कौस्ट औफ प्रोडक् इन बढ़ी है। मै। सवाल पूछने से पहले यह कना चाहूंगा कि इन्होंने अपने रिटन रिप्लार्ड में पावर इन्क्रीज का जिक्र नहीं किया, केवाल पावर का रेट बताया है?

**श्री हरपाल सिंह:** स्पीकर साहब, पिछले साल 240 करोड़ यूनिट बिजली की सप्लाई की थी और इस साल 320 करोड़ यूनिट बिजली की सप्लाई है।

**प्रो०सम्पत सिंह:** स्पीकर साहब, मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि टैरिफ में कितनी इन्क्रीज है?

**श्री हरपाल सिंह:** उसमें स्लाईट इन्क्रीज है।

**प्रो०सम्पत सिंह:** स्पीकर साहब, मंत्री जी ने यह माना है कि कौस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है और दूसरी तरफ जो उत्पादन है, उसके भाव इन्होंने पिछले साल से कम्पेयर न करके, उससे पहले साल के साथ कम्पेयर किए हैं। यह भी माना है कि पिछले साल के मुकाबले यूरिया तथा कैन के भाव घटे हैं जबकि डी०ए० पी० के भाव बढ़े हैं इस स्थिति में जब बिजली के रेट बढ़ गए और इन-पुट्स के रेट बढ़ गए, स्पीकर साहब हरियाणा के किसानों ने बिजली के बिल नहीं भरे, सरकार ने उन के बिजली के कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिए। डिस्कनेक्शन का किसानों ने विरोध किया। इन्द्री और पीलूखेड़ा में किसानों पर लाठी चार्ज किया गया। जो किसान अपनी मांगों को लेकर चण्डीगढ़ आ रहे थे, उन पर चण्डीगढ़ पुलिस ने लाठी चार्ज करके उनको यहां से धकेल दिया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार कृषि लागत खर्च पर सबसिडी देगी और क्या फसलों के दामों में गिरावाट को पूरा करने के लिए बोनस देगी?

**मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):** अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी ने ऐसी बात कह दी, जैसे इनको उन बातों का ज्ञान ही न हो। ये सारी बातें जानते हैं मुझे इनके भोलेपन की बात समझ नहीं आती। ये अपना जमाना भूला जाते हैं हमारी सरकार आने के बाद हमने किसानों को बहुत अच्छे भाव दिए हैं। मैं आपको इनके वक्त की बात बताता हूँ। इन्होंने 1989-90 में बासमती चावल का रेट 550 रूपए क्विंटल के हिसाब से किसानों को दिया था और 1990-91 में 500 रूपय क्विंटल से ज्यादा नहीं दिया था। पिछले साल 1500 रूपए से लेकर 1800 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बासमती जीर बिकी है। इस बात को सारे प्रदेश का किसान जानता है। इस साल भी 100 रूपए से लेकर 1200 रूपए प्रति क्विंटल बासमती जीरी का भाव है।

**प्रो० सम्पत सिंह:** पिछले साल के मुकाबले में इस साल बासमती के रेट तो कम हो गए।

**चौधरी भजन लाल:** आप सुनने की हिम्मत रखें। हम आपकी पूरी तसल्ली करेंगे। कई दफा चाहे बिजनैस हो और चाहे किसान की फसल का भाव हो सप्पा लग जाता है, एक दम भाव अच्छे मिल जाते हैं। भारत सरकार भाव तय करती है। भारत सरकार ने जो भाव तय किए वह आज आपके सामने हैं। हमारी सरकार आने के बाद हमने किसानों को बहुत अच्छे भाव दिए हैं। आपके जमाने में जब आप कभी 2 रूपए क्विंटल के हिसाब से और कभी 5 रूपए क्विंटल के हिसाब से भाव बढ़ाते थे। आपके समय में धान का रेट 188 रूपए क्विंटल था। हमारी सरकार आने के बाद 225 रूपए क्विंटल, 245 रूपए क्विंटल, 295

रुपए क्विंटल और 296 रुपए क्विंटल धान का भाव किसानों को दिया है। भारत सरकार जो स्पोर्ट प्राइस तय करती है अगर मार्किट में उससे कम रेट हो जाता है, तो सरकार खुद परचेज करेगी इस तरह से किसानों को 40-50 रुपए फालतू मिलता है।

**प्रो० सम्पत सिंह:** खाद के रेट भी तो काफी बढ़ गए।

**चौधरी भजन लाल:** अध्यक्ष महोदय सम्पत सिंह जी कह रहे हैं कि खाद मंहगी हो गई। मैं इनको इनका दिमाग ताजा करने के लिए बताना चाहूंगा। ये किसानों की बात करते हैं। जब इनका राज होता है, तो किसानों का नाम भी नहीं लेते किसानों को भूल जाते हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा और यह बात ठीक है कि खाद का भाव बढ़ा है लेकिन जो खाद बाहर से आती है, उसका भाव बढ़ा है। फिर भी भारत सरकार ने उसको सबसिडाइज्ड करके 55 रुपए पर बैग सबसिडी दी है। हमने भारत सरकार से रिक्वैस्ट की कि पंजाब और हरियाणा का किसान बहुत मेहनती है, इसलिए उनको खाद पर सबसिडी देनी चाहिए। खाद का भाव ठीक होना चाहिए। भारत सरकार ने हमारी बात पर गौर किया और खाद पर सबसिडी दी। मैंने यह प्वायंट कमेटी की मीटिंग में भी रेज किया था। भारत सरकार ने इसका रेट 55 रुपये पर कट्टा कम किया है, इनको यह पता होना चाहिये। ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री धीरपाल सिंह:** उस समय डी०ए०पी० खाद का क्या रेट था ( गोर एवं व्यवधान) मुख्य मंत्री ने हमारी सरकार के समय के भाव बताए हैं लेकिन अब क्या रेट हैं, या नहीं बता रहे? ( गोर एवं व्यवधान)

**चौधरी भजन लाल:** अध्यक्ष महोदय, डी०ए०पी० के भाव बढ़े हैं लेकिन यूरिया का रेट 15 रूपये पर कट्टा सस्ता हुआ है।

**श्री धीरपाल सिंह:** आप ठीक जवाब नहीं दे रहे, सदन को गुमराह कर रहे हैं। ( गोर एवं व्यवधान)

**चौधरी भजन लाल:** आप मेरी बात तो सुनिये। ( गोर एवं व्यवधान)

### सदस्यों का नाम लेना

**श्री धीरपाल सिंह:** आप किसी बात का कोई ठीक जवाब नहीं दे रहे हैं। आप तो .....( गोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** धीरपाल सिंह जी, आप बैठ जाइए। ( गोर एवं व्यवधान)

**मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):** मुझे फक्र है कि मैं ..... बेचते बेचते यहां तक पहुंचा। इस काम के लिये भी काफी पैसा चाहिए ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री धीरपाल सिंह:** .....

**श्री अध्यक्ष:** ये भाब्द रिकार्ड न किए जायें। मेरी परमि तान के बिना जो कुछ बोला जा रहा है वह रिकार्ड न किया जाये। धीर पाल



सिंह जी, आप बगैर इजाजत के बोल रहे हैं। मैं आपको नेम करता हूँ।  
You may please withdraw form the House.

(At this stage Shri Dhir Pal Singh continued speaking without permission).

**प्रो० सम्पत सिंह:** स्पीकर साहबए इनकी तरफ से आंकड़े ठीक नहीं दिए जा रहे, ये जो कह रहे हैं, सरासर गलत कह रहे हैं।  
( तोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** सम्पत सिंह जी, आप बगैर इजाजत के बोल रहे हैं, इसलिये मैं आपको भी नेम करता हूँ। Please withdraw from the House. ( तोर एवं व्यवधान)

**Mr. Speaker:** Sergeant-at Arms, remove them from the House. (interruptions).

(At this stage, both the members, Shri Dhir Pal Singh and Shri Sampat Singh did not withdraw form the House and continued speaking without permission)

**श्री राम कुमार कटवाल:** यह सरासर अन्याय हो रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। ( तोर एवं व्यवधान)

(At this Stage, Shri Ram Kumar Katmal, a member from the Janata Party surrounded the members and prevented the Sergaent-at-Arms from executing the orders of the Hon. Speaker).

**श्री अध्यक्ष:** कटवाल साहब, मैं आपको भी नेम करता हूँ।  
( तोर एवं व्यवधान)

(The Hon. Member Shri Ram Kumar Katwal continued Preventing the Sergeant-at-Arms from executing the order of the Hon'ble Spaker).

**श्री अध्यक्ष:** आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ( तोर एवं व्यवधान) ऐसा है कि हमने पहले चौधरी सम्पत सिंह जी और चौधरी धीरपाल सिंह जी को नेम किया है इसलिए आप दोनों बाहर चलें जाएं। सम्पत सिंह जी, आपने उधर गैलरी की तरफ नहीं जान है क्योंकि लौबी भी हाउस का ही पार्ट है। ( तोर एवं व्यवधान) राम कुमार कटवाल जी को बाद में नेम किया है, आप इनको भी बाहर ले जाएं। ( तोर एवं व्यवधान)

(At this stage, the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch&Ward staff, took the members out of the House.)

## नियम 104 का निलम्बन

**श्री सतबीर सिंह कादयान:** स्पीकर साहबखु मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। ( तोर) स्पीकर साहब, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आदरणीय सदस्य चौधरी धीरपाल सिंह पर पहले आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने भावना में बहकर आक्षेप लगाए हैं और उन्होंने अपना जवाब दिया। इसी बीच यहां बहुत भाोरगुल हो गया, सत्ता और पक्ष की और से भी तथा विपक्ष की और से भी। आपने उनको नेम कर दिया और आपके मा र्गिल ने कानून का पालन नहीं किया और बिना सोचे समझे दूसरे विधायकों को पकड़ कर बाहर निकालने की को ि । । की। यह

सब गैर कानूनी और संविधान के खिलाफ है। इसके लिये सदन के नेता को माफी मांगनी चाहिए। ( गोर एवं व्यवधान)

**मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूँ कि इनका रवैया किस तरह का है आपने कल भी देखा था और आज भी देखा है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। यह इनकी प्लैनिंग है कि हर बात पर कुछ न कुछ जरूर कहना है और सरकार का जो प्वायंट आफ व्यू है, उसको जनता तक नहीं पहुंचाने देना है। इन्होंने तो वाक-आउट करना है। अध्यक्ष महोदय, ये तो आपके आदे की भी अवहेलना करते हैं। ये बार बार चेयर को चैलेंज करें, इस बात को यह सदन बर्दा त नहीं कर सकता। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे पार्लियामेन्टरी मिनिस्टर एक प्रस्ताव रखेंगे और आप इसको स्वीकृति दीजिए। अध्या महोदय, यह जो दो तीन लोग जान बूझ कर इस हाउस को चलने नहीं देते, उनको इस हाउस से निकालने की कार्यवाही की जाए।

**श्री अध्यक्ष:** उनको तो आज के लिए निकाल दिया गया है।

**चौधरी जगदी त नेहरा:** अध्यक्ष महोदय, हम रैस्ट आफ दि सै इन के लिये मो इन मूव करते हैं कि इन तीनों को रैस्ट आफ दि सै इन के लिये निकाला जाए क्योंकि इनका जो बर्ताव था या जो कंडक्ट था, वह तो आपने देख ही लिया है। ये बार बार दृचेयर को डिफाई कर रहे हैं ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप मो इन मूव कीजिए। ( गोर एवं व्यवधान)

(इस समय सतबी कादयान बोलने के लिये खड़े हो गये)

कादयान जी आप बैठिए otherwise, I will name you also.

**Irrigation Minister (Chaudhri Jadish Nehra):** Sir, I Beg to move-

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding the suspension of Sarvshri Sampat Singh, Dhir Pal Singh and Ram Kumar Katwal for the remainder of the Session.

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding the suspension of Sarvshri Sampat Singh, Dhir Pal Singh and Ram Kumar Katwal for the remainder of the Session.

**श्री वीरेन्द्र सिंह:** अध्यक्ष महोदय, आज तो आपने एक न ले लिया है और एक न होने के बाद प्रस्ताव आया है। मैं निवेदन करता हूँ कि अगर कल कोई बात हो जाये तो फिर आप एक न लें। यह मो न तो आपकी भान के खिलाफ होगा कि आप उन्हें हमे न के लिए सै न से निकाल दें। मैं पार्लियामैन्ट अफेयर मिनिस्टर से भी निवेदन करता हूँ कि आज तो एक न हो चुका है और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यह चेयर पर रिफ्लेक् न होगा। अध्यक्ष महोदय, हम चेयर की ही सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं और सबसे ज्यादा सम्मान हमें चेयर का ही करना चाहिए।

**मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):** अध्यक्ष महोदय, अभी वीरेन्द्र सिंह जी ने जो बात कही है, हमारी कभी भी ऐसी मं ता नहीं रही हैं ये मानीय सदस्य भी चुन कर आये हैं। इनका भी जनता की बात यहां पर कहने का हक है। परन्तु ये सरकार की हर बात को दूसरे तरीके से लेते हैं और सदन की कार्यवाही चलने नहीं देते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज आपके नेम करने के बावजूद भी ये सदन में आ गए थे परन्तु हमने कहा कि इन्हें बैठने दिया जाए। हम तो यह चाहते हैं कि हर एक सदस्य को हाउस की कार्यवाही में शामिल होने दिया जाए। आपने कर्ण सिंह दलाल को भी नेम किया था परन्तु हमने उनको वापिस बुला लिया था। अध्यक्ष महोदय, आपने भी अपने आदमी भेजे। इधर से पीर चन्द जी और लहरी सिंह भी गए थे, परन्तु वे निकल गए। इसका मुझे पता नहीं है। लेकिन हमारा हमें ता यही नजरिया रहा है कि कोआप्रे ान से हाउस का माहौल ठीक रहना चाहिए। अगर सरकार में कोई कमी है तो वे क्रिटिसाइज करें। इस बारे में हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन यह कोई तरीका नहीं कि बार-बार हाउस की कार्यवाही में बाधा डाली जाए। इसी कारण से आपको उनको नेम करना पड़ता है। लेकिन एक बात वीरेन्द्र सिंह जी ने कही है, हम उनका आदर करते हैं क्योंकि वे एक सीनियर मैम्बर हैं। अगर ये इस बात की गारन्टी लेते हैं कि कल इनका रवैया बिल्कुल ठीक रहेगा तो हमें उन्हें बुलाने में कोई एतराज नहीं होगा। ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री सतबीर सिंह कादयान:** अध्यक्ष महोदय, गारंटी कौन किसकी लेता है?

**चौधरी भजन लाल:** हम आपने सभी लोगों की गारन्टी लेते हैं। ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** कादयान जीए अगर आप उनकी गारन्टी देते है तो बताएं।

**श्री सतबीर सिंह कादयान:** अध्यक्ष महोदय, मामला यह था कि अदरणीय मैमबर ने क्वै चन पुट किया था और मुख्य मंत्री जी जवाब दे रहे थे और जवाब बड़ा उलझ-पुलझ आ रहा था। हमने जो सवाल किया था, वह यह था कि एक साल के दौरान यानी 24 जुलाई 1991 के बाद डी०ए०पी० फर्टीलाइजर और यूरिया फर्टीलाइजर दोनों की कीमतें बढ़ीं है।

**श्री अध्यक्ष:** आप सिर्फ यह बताएं, do you assure the House for their good behaviour for tomorrow and day after tomorrow?

**श्री सतबीर सिंह कादयान:** अध्यक्ष महोदय, वह तो विपक्ष के नेता हैं और उनसे सब उम्मीद करते हैं। उनकी कौन जिम्मेदारी नहीं ले सकता? उनके बारे में सब जानते हैं। उनकी जिम्मेदारी हरियाणा का एक-एक व्यक्ति ले सकता है और मैं भी उनकी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अगर हमारी भावनाओं को ठेस लगेगी तो हमारे 16 के 16 विधायक वाक आउट करेंगे, नारे भी लगायेंगे, अपनी बात भी कहेंगे। हम किसे से भी दबेंगे नहीं। हम भी चुनें हुए प्रतिनिधि हैं।

**श्री वीरेन्द्र सिंह:** स्पीकर सर, मैंने आपसे इसलिए अर्ज की है कि आज आप अपना फैसला दे चुके हैं लेकिन अगर आपके फैसले को गवर्नमेंट आगे दो दिन के लिए एक्सटेंड करवाये तो मेरे हिसाब से यह आपके उपर रिफ्लैक्ट न होगा। मैंने इसीलिए मुख्यमंत्री जी से और पार्लियामेंट्र अफेयर्स मिनिस्टर से गुजारि की है कि स्पीकर साहब हमारे राइट्स के और हम सबके कस्टीडियन हैं। सारा हाउस उनकी इज्जत करता है। इसलिए एक इंसीडेंट के लिए इनके फैसले को रिवाइज मत करवाईये। अगर को नैक्स्ट इंसीडेंट हो तो आप दोबार से मो न मूव कर सकते हैं। मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि स्पीकर साहब का फैसला रिवाइज न करवाये और वैसे भी स्पीकर साहब आज के इंसीडेंट के लिए तो ऐक्ट न ले ही चुके है।

**सिंचाई मंत्री (चौधरी जगदी ा नेहरा):** स्पीकर साहब, जैसा कि वीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि इनको सारी सिटिंगज के लिए न निकाला जाये, सर हम भी यही चाहते हैं, लेकिन यह फैसला आपको करना है कि क्या आगे के लिए उनका कंडक्ट ठीक रहेगा? कल भी हमने आपके द्वारा उन लोगों को नेम करने के बावजूद यहां आने पर कोई ऐतराज नहीं किया था। कल आपने उनको नेम करने के बाद यह कहा कि उनको सीटिंग में हिस्सा लेने दिया जाये तो हमने कुछ नहीं कहा और आज भी हम इस बात के हक में नहीं थे कि उनको बाहर निकाला जाये। लेकिन आपने उनको आज के दिन के लिए नेम कर दिया और हमारे प्रै ार के बावजूद भी आपने कहा कि इनको सीटिंग में पार्टिसिपेट करने देते हैं ओर अपने फैसले को रिवोक कर दिया। सर,

इनका बिहेवियर और कंउक्ट ऐसा है कि ये लोग हर बात में बीच में ही बोलते हैं। ये कभी अपनी आदलत नहीं बदल सकते और न ही कोई इनकी गारंटी ले सकता है ( गोर एवं व्यवधान) सरख बात करने का तौर तरीका होता है। हम यह नहीं चाहते कि हाउस में इस तरह की बातें आयें जिससे कि माहौल खराब हो। हम यह तो चाहते हैं कि हमारी ये लोग नुक्ताचीनी करें लेकिन हर बात में नुक्ताचीनी करना ठीक नहीं है। हाउस का काम इनको ठीक तरीके से चलने देना चाहिए। सर, ये लोग आपकी भी इज्जत नहीं करते क्योंकि आपने खड़े होने के बावजूद भी ये लोग बैठते नहीं हैं। कल भी आज भी, एक बार नहीं दसियों बार, ये लोग आपके खड़े होने के बाद बैठे नहीं हैं। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि इन तीनों को रेस्ट ऑफ सीटिंग के लिए निकाला जाये।

**Mr. Speaker:** Kadian Sahib, do you assure?

**श्री सतबीर सिंह कादयान:** बिल्कुल, सर स्पीकर साहब। आप फ़ैसला तो दे ही चुके हैं। अगर मान लें कि किसी ने छोटा क्राईम किया हो तो उसको छोटी ही सजा मिलनी चाहिए और अगर बड़ा क्राईम किया हो तो सजा बड़ी मिलनी चाहिए। स्पीकर साहब, यह नहीं कि छोटे क्राईम के लिए आप उम्र कैद कर दें। आज की सजा तो आप दे ही चुके हैं। हमारे मैम्बर जा चुके हैं। लेकिन अगर आप छोटे क्राईम में बड़ी सजा देंगे तो यह कहां का न्याय है? वह आज की सजा तो ले ही चुके हैं और बाहर भी जा चुके हैं। सम्पत सिंह हमारे विपक्ष के नेता हैं



और कटवाल साहब भी हमारे आदरणीय मैम्बर हैं। ये सभी मैम्बर बाहर भी जा चुके हैं।

**श्री अमर सिंह:** स्पीकर साहब, हाउस में आपका आदे 1 मानना हर मैम्बर का सबसे बड़ा फर्ज हैं। आज जिन लोगों ने आपके आदे 1 की अवहेलना की है, उनको आपने नेम करके बाहर निकाल दिया। इसके अलावा आनरेबल पार्लियामेंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर ने भी एक प्रस्ताव पे 1 कर दिया। इसके अलावा आनरेबल पार्लियामेंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर ने भी एक प्रस्ताव पे 1 कर दिया कि इन मैम्बर्ज को बाकी की प्रोसीडिंग्स में भी हिस्सान न लेने दिया जाये। स्पीकर सर, मेरी आपसे गुजारि 1 है कि आप उस क्राइम की एक बार सजा दे चुके हैं और उसके लिए आज की बैठक से उनको हाथ धोना पड़ेगा। आपके आदे 1 की पालना करनी है, इसलिए आज वे हाउस में नहीं बैइ सकते। पर उसके बाद आज ही दूसरा आदे 1 जारी करना, यह आपकी चेयर पर रिफ्लैक्शन है। कल का दिन कल आएगा। अगर फिर इस तरह की बात आएगी तो कल यह फिर लागू हो जाएगा। स्पीकर सर, हम आपको कस्टोडियन मानकर हमारे राइट्स और डियूटीज के लिए आपका फर्ज बन जाता है। हमारे राइट्स और डियूटीज का आपने ध्यान रखना है और हाउस को बहुत बखूबी चलाना है। इसलिए मेरी आपसे गुजारि 1 है कि कल मुख्यमंत्री साहब ने रिवोक करने के लिए कह दिया था, हालांकि कल भी आपके द्वारा नेम करने के बाद, वे हाउस में नहीं बैठ सकते थे लेकिन आपने इजाजत दे दी और मुख्यमंत्री ने कोई ऐतराज नहीं किया। आज भी आपने उनको आदे 1 दे दिया है और वे बाहर

चले गए हैं। स्पीकर सर, मैं समझता हूँ कि बाकी कार्यवाही के इन-एडवांस कार्यवाही करना भाोभाजनक नहीं होगा।

**चौधरी जगदी ा नेहरा:** स्पीकर सर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जिस-जिस पार्टी का जो लीडर है, उसको अपने मैम्बर्ज के कंक्वट का फैसला करना होता है। जैसे कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री जी अगर कहेंगे तो सारे कांग्रेस के मैम्बर्ज बैठ जाएंगे। इसी तरह अगर सिंह जी की पार्टी है, चौधरी वीरेन्द्र सिंह एंव राम बिलास भार्मा जी की पार्टी है। अगर लीडर ही ऐसी बाता करता है तो कैसे काम चलेगा? लगातार उनका यह बिहेवियर है। हाउस में डिप्टी लीडर भी नहीं हैं। स्पीकर सर, अगर श्री सतबी सिंह कादयान यह ए योर करें कि प्रो० सम्पत सिंह जी का हाउस में कंडक्ट अच्छा रहेगा तो उनको हाउस में आने की इजाजत दी जा सकती है।

**श्री अध्यक्ष:** कादयान साहब, आप बोलिए।

**श्री सतबीर सिंह कादयान:** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैंने भी बाहर निकालने की कोशिश की। मैं पार्टी के सैक्रेटरी की हैसियत से आपको विज्ञापन दिलाता हूँ कि हमारे नेता इस तरह का व्यवहार कभी नहीं किया करते। सत्ता पक्ष के सदस्य यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो मुझे भी जाना पड़ेगा। स्पीकर सर, हमारी पार्टी के अच्छे सीनियर सदस्य बाहर चले गए हैं, उन्हें पनिमेंट दे दी गई है। माफी किस बात की है? मैं

अ योर करता हूं कि कल ठीक-ठाक कार्यवाही चलेगी। जैसा माहौल होगा, वैसी ही बात चलेगी।

**चौधरी जगदी । नेहरा:** स्पीकर साहब, यह क्या कह रहे हैं कि जैसा माहौल होगा वैसी बात चलेगी। कल कोई बात करेख कोई माहौल खराब करें, फिर ऐव इन का रिऐव इन होगा। स्पीकर सर, हमारी तो यही गुजारि । है कि हाउस की प्रोसीडिंग्ज में बार-बार व्यवधान न पड़े और कार्यवाही ठीक-ठाक चले। ( ।ोर एवं व्यवधान) वे बाहर चले गये। दूसरे, दो दिन की सिटिंग से सस्पेंड करने के लिये मो इन मूव किया था। लेकिन अब कादयान साहब की अ योरेंस को देखते हुए हम इस मो इन का पैडिंग रख लेते हैं। ( ।ोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती चन्द्रावती:** स्पीकर साहब, यह जो मो इन सरकार की तरफ से आया है यह पूरी सोच देने के बाद आया हैं। जब आने एक बार उनको नेम कर दिया और वह बाहर चले गये तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि यह मो इन पुट की जावे यह आफटर-थाट है। उनको तो एक सजा हो चुकी है। आगे के लिये किसी बात के बारे में प्रजम्प इन तो नहीं की जा सकती। यही किया जा सकता है कि अगर वह मिस-बिहेव करते हैं तो उनको आप सजा दे सकते हैं। आने उनको सजा भी दे दी है और दूसरी तरफ यह मो इन भी सरकार ले आयी है। इसके कोई मायने नहीं है। यही मरी अर्ज है कि इस मो इन को वापिस लेना चाहिये क्योंकि आज की उनको सजा दे दी गई है।

**चौधरी भजन लाल:** स्पीकर साहब, सारे अपोजी इन के लीडर्ज ने भी इस बात को महसूस किया है कि इनका कंडक्ट ठीक नहीं था। इन्होंने भी यह बात मानी है कि उनका कंडक्ट ठीक नहीं था। कादियान साहब, अपनी पार्टी के जनरल सैक्रेट्री भी हैं। इन्होंने भी अ योर किया है और इनके दूसरे मैम्बर साहेबान ने तथा अपोजी इन के दूसरे लीडर्ज ने भी अ योर किया है कि आगे कार्यवाही ठीक ठाक चलेगी। इन सब को देखते हुए हम इनकी सस्पें इन के मो इन को विदड्रा करते हैं।

**Mr. Speaker:** Is it the pleasure of the House to withdraw the motion?

**Voice:** Yes.

**Mr. Speaker:** The motion is withdrawn by leave of the House and the issue is over. Now, we take up calling attention motion.

### ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/वक्तव्य (पुनरारम्भ)

**श्री सतबीर सिंह कादियान:** स्पीकर साहब मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि 24 जुलाई, 1991 के बाद एक साल के अन्दर-अन्दर डी०ए०पी० फर्टीलाइजर के रेट्स 180 से बढ़कर अब तक 405 रूपये और यूरिया खाद की कीमतें 117 रूपयें से बढ़कर 138 रूपये हो गयी है। एक तरफ तो केन्द्रीय सरकार ने यह कहा है कि हम 50 रूपये सबसिडी देते हैं और दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश की सरकार के मुख्य मंत्री महोदय ने 50 रूपये की एडी नल सबसिडी किसानों को

देने की घोशणा की है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि सरकार ने अपनी तरफ से कितना पैसा इस सबसिडी के लिये दिया है? इसके अलावा, कितना पैसा इतिहास, मूहरी पब्लिसिटी तथा एडवर्टाइजमेंट के लिये सरकार ने खर्च किया है? क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी?

**मुख्य मंत्री: (चौधरी भजन लाल):** स्पीकर साहब, जो इन्होंने कहा है यह ठीक बात नहीं है। जब हमने राज्य का चार्ज लिया तो खाद का भाव महंगा था। हमने यूरिया को सस्ता किया है। जो महंगा हुआ है, वह डी०ए०पी० है। डी०ए०पी० पर एक सौ सोलह रूपए बढ़ाए हैं, लेकिन यूरिया पर पन्द्रह रूपए पर-कट्टा कम किए हैं। एक एकड़ में किसान चार कट्टे से लेकर पांच छः कट्टे तक यूरिया डालता है .....

**श्री सतबीर सिंह कादयान:** स्पीकर साहब निरी.....है। दो या तीन कट्टे से ज्यादा किसान यूरिया नहीं डालता।

**श्री अध्यक्ष:** यह भाब्द रिकार्ड न किया जाए।

**चौधरी भजन लाल:** स्पीकर साहब, जहां पानी काफी उपलब्ध है, वहां किसान पांच छः कट्टे प्रति एकड़ डालता है। स्पीकर साहब, अगर किसान ने चार कट्टे भी यूरिया के डाले तो उसे साठ रूपए का फायदा हुआ। किसान को एक सौ सोलह रूपया डी०ए०पी० के ज्यादा देने पड़े क्योंकि डी०ए०पी० का एक कट्टा डालना पड़ता है।

**श्री सतबीर सिंह कादयान:** डी०ए०पी० के दो कट्टे डालने पडते है ।

**चौधरी भजन लाल:** किसान को एक सौ सोलह रूपए फालतू देने पड़े और साठ रूपए का फायदा हुआ। ( गोर एवं व्यवधान) इस तरह से छप्पन रूपए ज्यादा लगे। ( गोर एवं व्यवधान) सपीकर साहब, छप्पन रूपए फालतू लग गए तो क्या फर्क पड़ा? ( गोर एवं व्यवधान) किसान को एक एकड़ में छप्पन रूपए का फर्क पड़ा लेकिन उसको कम से कम एक एकड़ में पांच सौ रूपए का फायदा होगा। हमने किसान से छप्पन रूपए लिए और पांच सौ रूपए उसकी जेब में डाल दिए। इस तरह से किसान को चार सौ चतालीस रूपए का फायदा होगा। स्पीकर साहब, ये लोग गलत प्रचार कर रहे है। उनको ये कहते है कि याद न डालो। अगर वह खाद नहीं डालेगा तो वह घसियारा हो जाएगा। अगर किसान अनाज पैदा नहीं करेगा तो दे 1 का क्या हाल होगा? अगर किसान खाद नहीं डालेगा तो क्या उत्पादन इतना हो सकेगा? पहले एक एकड़ में किसी के दस मन गेहूं हो जाते थे तो वह अच्छा किसान कहलाता था। कहा जाता था कि इस किसान के दस मन गेहूं पैदा हुए हैं, यह अच्छा किसान है लेकिन आज एक एकड़ में चालीस मन, पचास मन और टौप किसान है, वह सत्तर मन गेहूं एक एकड़ में पैदा करता है। अगर वह खाद नहीं डालता तो क्या उपज इतनी हो सकती थी? स्पीकर साहब, दसरी बात में बिजली के बारे में कहना चाहता हूं।

**श्री सतबी सिंह कादयान:** आप सबसिडी के बारे में भी बताएं कि आपकी सरकार ने कितनी सबसिडी दी है?

**चौधरी भजन लाल:**सबसिडी तो भारत सरकार ने दी है।

**श्री सतबीर सिंह कादयान (पोस्टर दिखाते हुए):** स्पीकर साहब, ये हरियाणा सरकार के पोस्टर कहां से आ गए हैं, ये पोस्टर क्यों पब्लिक में बांटे गए हैं? ( गोर एवं व्यवधान)

**चौधरी भजन लाल:** कादयान साहब, आप बार-बार खड़े क्यों होते हैं? आप तो दूसरी बार हाउस में आए हैं। आपको तो हाउस के नियमों की जानकारी होनी चाहिए।

**श्री सतबीर सिंह कादयान:** मुख्य मंत्री जी सदन को गुमराह न करें, मैं तो इसके विपरीत प्रूफ दे रहा हूँ। (व्यवधान)

**चौधरी भजन लाल:** अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली का ताल्लुक है, हमने कुछ रेट बढ़ाए हैं। स्पीकर साहब, पांच छ महीने पहले सारे दे 1 के पावर मिनिस्टर्ज की एक कांफ्रेंस भारत सरकार ने दिल्ली में बुलाई थी। उसमें अपोजी 1न की गवर्नमेंट्स के मिनिस्टर्ज भी थे और कांग्रेस की गवर्नमेंट्स के भी मिनिस्टर्ज थे। उसमें 'यूनानीमसली फ़ैसला लिया गया था कि सभी जगह बिजली बोर्ड घाटे में जा रहे हैं, इसलिए बिजली के रेट बढ़ाने पड़ेगें। उसमें पचास पैसे पर-यूनिट बढ़ाने का फ़ैसला किया गया। उसमें फ़ैसला लिया गया कि पचास पैसे यूनिट के हिसाब से रेट होने चाहिए। स्पीकर साहब, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि सब से पहले राजस्थान में जहां बी०जे०पी० की सरकार है, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भोखावत ने सब से पहले इस आदे 1 की पालना कीं आप जानते हैं कि बिजली आज घर में 1 रूपया 20 पैसे

पर यूनिट पड़ती हैं किसान को हम 50 पैसे पर-यूनिट के हिसाब से बिजली सप्लाई कर रहे हैं यानी 70 पैसे पर-यूनिट का घाटा सरकार को रहता है आज 266 करोड़ रुपये का घाटा बिजली बोर्ड को एक साल में हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये बार-बार दोहाई देते हैं कि किसानों को बिजली कम मिल रही है, ज्यादा मिलनी चाहिये। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि अगर अगले पांच-छः सालों में और नये प्रोजेक्ट न लगाये गये तो जितनी मांग है, उससे ज्यादा मांग उनकी और बढ़ जाएगी और हम पहले से आधी भी बिजली किसानों को नहीं दे पाएंगे और बिजली बोर्ड फ़ैल हो जाएगा। आज दे 1 व प्रदे 1 में बिजली की बहुत मांग है। इसलिए हमारी पूरी को 1 1 है कि हम केन्द्र सरकार से यह रिक्वेस्ट करें ओर दवाब डालें कि हमारे प्रदे 1 के अन्दर, दे 1 के अन्दर नए प्रोजेक्ट लगाये जाएं ताकि किसानों की बिजली की मांग को पूरा किया जा सके। यह दे 1 व प्रदे 1 के हित में ही होगा। अध्यक्ष महोदय, बिजली खेती व इंडस्ट्रीज के लिये एक रा-मैटिरियल हैं। अगर रा-मैटिरियल ही नहीं होगा, तो बिजली के बगैर खेती कैसे हो सकेगी? बिजली के बगैर इंडस्ट्रीज कैसे चल सकेंगी? बिजली कैसे बनेगी? भारत सरकार के पास हमारे तीन प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम प्रोजेक्ट कहां से लगाएंगे? मैं यहां हाउस को बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार का हमारी तरफ डेढ़ करोड़ रुपया बाकी है। भारत सरकार कहती है कि पहले हमारा बकाया पैसा दो, फिर हम आपके प्रोजेक्ट सैन्कान करेंगे। वे कहते हैं कि धेला आपके पास है नहीं, तो प्रोजेक्ट कहां से लगेंगे?



अध्यक्ष महोदय, मामूली सा हमने बिजली का रेट बढ़ाया है और उससे बड़ी मुश्किल से बिजली बोर्ड को कुल 40 करोड़ रुपये का फर्क पड़ेगा लेकिन इसके बावजूद भी ये लाग किसानों को सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश में मूतवात्तर कर रहे हैं। यह कोई भाभा की बात नहीं है। फिर किसानों को कहते हैं कि आप बिजली के बिल मत दो। इनके राज में क्या होता था कि ये सरचार्ज के तौर पर 10-10 हजार रूपया पहले जमा करवाते थे और मुझे समझ नहीं पड़ती कि आज ये लोग किस मुंह से सरकार को इस मामले में क्रीटीसाईज करते हैं? उल्टा किसानों को बिल न देने के लिये भड़काते हैं। ऐसा करके ये लोग हरियाण के किसानों को बिजली बोर्ड के हाथों नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ताकि बिजली बोर्ड किसानों के कनेक्शन काट दे। किसानों के ट्यूबवैल्व न चलें। किसान घसियारा हो जाए। उनकी बुरी हालत हो जाए परन्तु हाउस के अन्दर मैं इनको बताना चाहता हूँ कि अब हरियाणा का किसान बड़ा समझदार हो गया है। वह सब जानता है कि आज बिजली बोर्ड को बिजली महंगी पड़ती है और किसानों को वह सस्ते भाव पर दे रहा है। सिवाये कुछ गिने चुने लोगों के, कोई भी इन लोगों के साथ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हर वर्ग के, हर पार्टी में लोग होते हैं। कुछ लोग इन जैसे ऐसे होते हैं, जिनका काम केवल लोगों को बहकाना, गुमराह करना ही होता है। इससे ज्यादा ऐसे लोगों का कोई प्रोग्राम नहीं होता जिससे कि सरकार की छवि बिगड़े ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री सतबीर सिंह कादयान:** स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

**श्री अध्यक्ष:** कादयान साहब, आप बीच में इस तरह से डिस्टर्ब न करें। (व्यवधान) आप में तो सुनने की क्षमता नहीं है। ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री सतबी सिंह कादयान:** स्पीकर साहब, हमारा सवाल बड़ा अहम है जी। ( गोर एवं व्यवधान) बीच में क्या हम इनसे सवाल भी नहीं पूछ सकते। ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** नहीं, जब लीडर आफ दी हाउस बोल रहे हैं, तब आप कम से कम सुनने की हिम्मत तो रखें। अब श्री सूरजभान सवाल पूछेंगे।

**चौधरी सूरजभान काजल:** अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इस वर्ष हरियाणा सरकार ने गन्ने का मूल्य एक रूपया प्रति किंवटल बढ़ाया है और दूसरी तरफ किसान से दो रूपये प्रति किंवटल ज्यादा किराया लेने का निर्णय लिया है, क्या यह उचित है? क्या पिछले साल के मुकाबले में यह रेट किसान को कुल दाम का एक रूपया प्रति किंवटल के हिसाब से कम नहीं पड़ है?

**चौधरी भजन लाल:** अध्यक्ष महोदय, हमने कोई नई पालिसी नहीं बनाई है। जो पालिसी पहले थी, वही चल रही है। गन्ने का जो 50 रूपए का भाव आज की सरकार ने दिया है, वह सारे मुल्क में सब से ज्यादा है।

**श्री कृष्ण लाल:** स्पीकर साहब, मैं कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कृषि विभाग सर्कल के अन्दर मक्खन सिंह एक इंस्पैक्टर है।.....

**श्री अध्यक्ष:** इस बात का इससे कोई तालुक नहीं है, आप बैठें।

**श्री अमर सिंह:** स्पीकर साहब, मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या पिछले साल गेहूँ और जीरी प्रदेशों से बाहर ले जाने पर पाबन्दी लगाई गई थी। यदि हाँ, तो यह पाबन्दी कब से हटाई गई है?

**चौधरी भजन लाल:** सरकार ने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया था।

**चौधरी बलवंत सिंह मैना:** स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार ने गन्ने के प्राइवेट क्रैटारों पर पाबन्दी लगा रखी है। यदि वह नहीं लगा रखी तो क्या मुख्य मंत्री जी के नोटिस में है कि ऐसे क्रैटारों के खिलाफ मुकद्दमें दर्ज हुए हैं? यदि मुकद्दमें दर्ज हुए हैं तो कितने हुए हैं और क्यों हुए हैं?

**चौधरी भजन लाल:** अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट क्रैटारों पर कोई पाबन्दी नहीं है। जो चल रहे हैं उन पर कोई पाबन्दी नहीं है। आप लोगों की और किसानों की मांग थी कि मिल के एरिया में कोई क्रैटार नहीं होगा। जो पहले के चल रहे हैं, उन पर कोई पाबन्दी नहीं है। हम

चाहते हैं कि किसान को गन्ने का भाव ठीक मिले और उसका वजन भी ठीक हो।

**चौधरी बलवंत सिंह मैना:** स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि कोई पाबन्दी नहीं है। कोलंगी गांव में एक क्रै 117 चल रहा था और वह एक धर्मपाल नाम के आदमी का था, उसके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं।

**चौधरी भजन लाल:** अध्यक्ष महोदय, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वे क्रै 117 नहीं चला सकते। आप यह बताएं कि जिनका अपजिक्र कर रहे हैं, क्या उनके पास लाइसेंस है? अगर कोई गलत काम किया होगा तो हम उसको दुरुस्त करेंगे ही।

**श्री मोहन लाल पिपल:** स्पीकर साहब, मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हरियाणा के मुकाबिले में पंजाब में ट्यूबवैल का फ्लैट रेट 45 रूपए पर—हार्स पावर की जगह 25 रूपए है। इस तरह से प्रति यूनिट के चार्ज में भी अन्तर है। तो क्या हरियाणा सरकार बिजली के रेट कम से कम पंजाब के बराबर लाने का विचार रखती है?

**चौधरी भजन लाल:** अध्यक्ष महोदय, पंजाब ने भी कुछ रेट बढ़ाए हैं। मुझे यह जानकारी नहीं है कि पंजाब के रेट में ओर हमारे रेट में कितना अंतर है। कुछ समय पहले पंजाब के मुख्य मंत्री जी से मेरी बात हुई थी। उस समय उन्होंने खुद कहा था कि हम भी रेट बढ़ाने जा रहे हैं। उन्होंने कुछ रेट बढ़ाए हैं लेकिन पंजाब का मुकाबला हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी माली हालत ठीक नहीं है। पंजाब में

हालत ओर तरह के है। आप जानते है कि भारत सरकार से सहायता के तौर पर पंजाब को इस साल 500 करोड़ रूपए मिले है। हरियाणा को एक धेला भी नहीं मिला तो हम पंजाब का मुकाबला कैसे कर सकते है? लेकिन हमारी कोि । । यह रहेगी कि किसानों को पूरी बिजली मिले, अच्छा भाव मिले और अच्छी खाद मिले।

### ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

**श्री अध्यक्ष:** दो काल अटैं ।न मो ।ंज हैं। एक श्री लहरी सिंह जी की है और दूसरी श्रीमती चन्द्रावती जी की है। These are under consideration.

**प्रो० राम बिलास भार्मा:** अध्यक्ष महोदय, कल सदन में अयोध्या के बारे में बहुत बातें हुई जैसे गाय जला दी गई, मंदिर तोड़ दिए गए। इस पर मुझे भी आप बोलने का मौका दें।

**श्री अध्यक्ष :** आप इस बारे में कल जीरो आवर में अपनी बात कह लेना।

### तारांकित प्र ।न सं० 337 पर और जानकारी देना

**मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):** अध्यक्ष महोदय, कल सम्पत सिंह जी ने कहा था कि गुड़गांव में एक स्कूली छात्रा के साथ एक टीचर ने बलात्कार किया। उसके बारे में मैं हाउस को बताना चाहूंगा कि हमारी पुलिस ने बहुत कोि । । की कि उस छात्रा के पेरैन्ट्स किसी के खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज करवाएं लेकिन उन्होंने किसी के

खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज नहीं करवाई। लेकिन फिर भी मैंने यह कहा कि आप इस केस के बारे में किसी सो गल वर्कर से एप्लीकेशन ले करके जांच करें। तो इस बारे में मैं सदन को बताना चाहता हूँ। सुश्री भागी बाला एडवोकेट, समाज सेवी के ब्यान पर, स्कूल मास्टर राजीव लाल के विरुद्ध, मुकदमा नं० 487/92, तिथि 21-12-92 अधीन धारा 376 भा०द०सं० थाना भाहर गुडगांव में, कुमारी हेमलता के साथ बलात्कार करने के संबंध में दर्ज किया गया है। मुकदमा जेरे तफती में है। कुमारी हेमलता को उसकी मां ने किसी नामालूम जगह पर भेज रखा है तथा उसकी माता इस मुकदमा के संबंध में ब्यान नहीं देना चाहती और न ही कोई कार्यवाही कराना चाहती।

**वर्ष 1986-87 के लिए अनुदानों तथ विनियोजनों से अधिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान**

**Mr. Speaker:** Hon'ble Members, now the discussion and voting on the Excess Demands over Grants and Appropriations for the year 1986-87 will take place. As per the past practice, in order to save the time of the House, the demands over grants on the order papers will be deemed to have been read and moved. The Hon'ble Members can discuss any demands but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 21,62,304 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1986-87 in respect of Revenue.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 74,604 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1986-87 in respect of Excise & Taxation.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 2,02,35,540 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1986-87 in respect of Finance.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 15,63,38,564 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1986-87 in respect of Building & Roads.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,79,28,557 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1986-87 in respect of Education.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 10,07,20,436 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1986-87 in respect of Irrigation.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 28,36,994 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1986-87 in respect of Animal Husbandry.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 45,93,417 be made to regularise the charges already incurred in excess of the

grant voted by the Legislative Assembly for the year 1986-87 in respect of Community Development.

## वर्ष 1986-87 के लिये अनुदानों तथा विनियोजनों के आर्थिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान

That a grant of a sum not exceeding Rs. 6,82,95,633 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1986-87 in respect of Transport.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 65,286 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1986-87 in respect of Tourism.

**श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल):** अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं डिमांड पर बोलने से पहले एक दो बातें कानून व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूँ। कल यहां पर बोलते हुए सदन के नेता ने कहा है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति में पहले से काफी सुधार हुआ है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि कानून व्यवस्था की जितनी स्थिति आज इनके एक साल के समय में खराब हुई है, उतनी पहले कभी नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पलवल भाहर में एक ओल्डोगा गांव की लड़की सामान खरीदने के लिए आई थी। वह 18 साल की थी। उसने अपनी ससुराल गांव भोजा जाना था। जब वह भाहर में सामान खरीदने के लिए आई तो उस को दिन दहाड़े पलवल भाहर से अगवा कर के ले गए। इस लड़की को राजस्थान के लोग उठा कर ले गए।



**श्री अध्यक्ष:** आप कौन सी डिमांड पर बोल रहे हैं?

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** मैंने तो बोलने से पहले ही आपसे इजाजत मांगी है कि डिमांड पर बोलने से पहले मैं एक दो बातें कानून व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूँ।

**श्री अध्यक्ष:** आप केवल डिमांड पर ही बोलिए। You are going out the way. Please speak on the demands on the agenda.

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** अध्यक्ष महोदय, जो मांग सदन के पटल पर रखी गई है, उनकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इन डिमांड्स पर बोलते हुए मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि इन में फाइनेंस का सवाल है। इन डिमांड्स के जरिए जो पैसा सरकार मांगती है, सदन उसको पास कर देता है। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी हैरानी की बात है कि जब हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाते हैं और यह पता करते हैं कि फलां डिपार्टमेंट के लिए कितना पैसा रखा गया था और उस डिपार्टमेंट ने कितना पैसा किस-किस जिले में किस-किस स्कीम पर खर्च किया तो उसका जवाब दिया जात है कि यह सूचना हमारे पास नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं भवन तथा सड़कें विभाग को बात बताना चाहता हूँ। मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट से पता लगाने की कोशिश की इस स्कीम के लिए कितना पैसा रखा गया था और किस-किस जिले में कितना-कितना पैसा खर्च हुआ है तो एफ०डी० वाले कहते हैं कि यह ब्यौरा हमारे पास नहीं है। अप संबंधित विभाग से पता करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब वित्त विभाग सारे पैसे को कन्ट्रोल करता है तो उनको अपने पैसे का सारा हिसाब रखना

चाहिए कि किस विभाग को कितना पैसा किस-किस स्कीम पर और कहां-कहां पर खर्च करने के लिए दिया गया था और कितना खर्च हुआ? जनता की कड़ी मेहनत का पैसा सरकारी खजाने में जमा होता है। उसका भी ये हिसाब न रखें तो इससे बड़ी अचम्भे की बात और क्या हो सकती है? लोगों के चुने हुए नुमायन्दे जो हैं, उनका भी यह फर्ज है कि वे देखें कि पैसा कहां-कहां पर खर्च हो रहा है। सरकार जो रोजाना लाखों करोड़ों रूपये खर्च कर रही है, उसका पूरा हिसाब-किताब न मिले तो यह बड़े अचम्भे की बात है। अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि इस प्रदेश में, इलाकों में बड़ा भेदभाव किया जाता है। जो भी पार्टी सत्ता में हो, जिस भी पार्टी का नेता मुख्य मंत्री होता है, वह अपने हल्के और अपने चाहने वालों के हल्के में मनमर्जी से पैसा खर्च करते रहे हैं, जब कि प्रदेश के दूसरे हल्कों और गांवों के साथ भेदभाव किया जाता है। (विधन) मिसाल के तौर पर मैं फरीदाबाद का उदाहरण देना चाहूंगा। जहां तक मैं समझता हूँ, फरीदाबाद जिला जनसंख्या के हिसाब से इस प्रदेश में सबसे बड़ा जिला है। पिछली बार भी सत्र के दौरान मैंने सदन के नेता का ध्यान इस जिले की ओर दिलाया था। एक तरह से यह जिला मुख्य मंत्री जी का अपना जिला भी रहा है क्योंकि जब उनको एम० पी० का इलैक्टोरेट बनना पड़ा तो उसके लिए उन्होंने इसी जिले को चुना था और यहां के लोगों ने उनको चुना था। (विधन)

**वाक आउट**

**श्री सतबीर सिंह कादयान:** अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी कालिंग अटैं इन मो इन नं० 1 के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।

**श्री अध्यक्ष:** आप अभी बैठें। क्या आपने बोलने के लिए इजाजत ली है?

**श्री सतबीर सिंह कादयान:** अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने हमारी कालिंग अटैं इन मो इन पर उठे प्रश्नों का जवाब संतोषजनक नहीं दिया है। इसके विरोध में हम लोग सदन से वाकआउट करते हैं।

(इस समय श्री सतबीर सिंह कादयान तथा समाजवादी जनता पार्टी के सभी उपस्थित सदस्य सदन से बाहर चले गये)

**वर्ष 1986-87 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनराम्भ)**

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** अध्यक्ष महोदय, उसके बाद जिला फरीदाबाद के विकास और दूसरे अहम मुद्दों पर इस जिले के साथ भेदभाव किया जाता है। आर्थिक आधार पर विकास की जितनी भी योजनाएं प्रदेश में चलाई जा रही हैं, उनमें जिला फरीदाबाद के साथ भेदभाव किया जाता रहा है। मिसाल के तौर पर मैं इरीगे इन का जिक्र करना चाहूंगा। स्पीकर साहब, इस इलाके में हरियाणा प्रदेश की एक भी नहर नहीं है जो वहां के खेतों में पानी दे सके। एक आगरा कैनल वहां से निकलती है। मुख्य मंत्री महोदय ने जब वहां से इलैक् इन लड़ा था तो लोगों को आवसन दिया था कि चुने जाने के बाद इस आगरा नहर का नियन्त्रण हरियाणा के हाथ में ले लेंगे। स्पीकर साहब,

नियन्त्रण तो दूर रहा, आगरा कैनल की सफाई की व्यवस्था भी नहीं करवाई गई। हमारे जिला में गुड़गांवा कैनल निकलती है। मैं सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान इस और दिलाना चाहूंगा कि हमारे हिस्से का पानी काट कर हमें कम पानी दिया जा रहा है। उटावड़, डिस्ट्रीब्यूटरी कई जगह से कटी पड़ी है। साथ ही खलों को भी सरकार द्वारा कोई देखरेख नहीं की जाती। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले राजौला माईनर क 'नाम से, उस समय श्री रिजक राम, जो मिनिस्टर थे, ने वहां ि लान्यास किया था। इतने साल गुजरने के बाद भी राजौला माईनर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। इस माईनर का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। 8-10 गांवों को इस माईनर से पानी मिलेगा, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। इसी तरह से हथीन डिस्ट्रीब्यूटरी, धतीर डिस्ट्रीब्यूटरी, सिकन्दरपुर जाती है जो बड़ लो-लाईग एरिया है। धतीर डिस्ट्रीब्यूटरी के पानी से सिकन्दरपुर गांव पानी में डूब जाता है और फसलें डूब जाती है। माननीय इरीगे ान मंत्री श्री नेहर साहब हमारे जिले की ग्रिवेन्सिज कमेटी में भी हैं। ग्रिवैन्सिज कमेटी में भी मैंने निजी तोर पर मिलकर उनका ध्यान इस तरफ दिलाया था और इस बारे कार्यवाही करने का निवेदन किया था ताकि इससे गांव का फायदा हो सके। लेकिन सरकार का इन सारी बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, 1986-87 की डिमान्ड्स में रोड्स का भी जिक्र किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पिछली दफा विधान सभा के सै ान में मुख्यमंत्री जी ने दावा किया था कि मेरा नाम भजन लाल है 31 मार्च तक हरियाण प्रदे ा की एक-एक सड़क की मुरम्त करा दूंगा और जहां-जहां भी सड़क टूट गई हैं, उनको ठीक करवाया जाएगा।

(इसी समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरे प्रदेश की बात कह सकता हूँ लेकिन मैं अपने जिले पलवल की बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि पलवल भाहर की जो मेन रेलवे रोड है और जिस पर से 25-30 हजार यात्री रोजाना निकलते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उस सड़क पर 5-5 फुट के गड्ढे हैं। बेचारे गरीब रिक्शा वाले, टांगे वाले कैसे-कैसे मेहनत करके रिक्शा और टांगा खरीदते हैं और वे उस सड़क पर दो या तीन महीने से ज्यादा नहीं चल सकते हैं। इसी प्रकार से पलवल भाहर से गुजरने वाली हर सड़क की हालत देखने वाली है। उपाध्यक्ष महोदय, एक सड़क है जिसे कलवा का रोड कहते हैं। वह आलापुर से होते हुए सीधे सोनापुर जाती है। उस सड़क की हालत ऐसी है कि आए दिन खड्डों की वजह से ऐक्सीडेंट्स होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक कि सरकारी बसों के ड्राइवर भी उन सड़कों पर जाने से मना कर देते हैं। नतीजा यह होता है, वे वहां खड़े रहते हैं। वे जिन लड़के-लड़कियों को स्कूल या कालेजों में जाना होता है, वे वहां खड़े रहते हैं। वे किस तरीके से वहां जाएं? इसी तरह से ट्रांसपोर्ट की डिमान्ड इन्होंने रखी हुई है। मंत्री जी ने कई बातें सदन के सामने बताई कि इतनी बसें हैं और इतनी बसें जला दी गई होंगी। सोनीपत डिपों में बसें जली थी। हमारे फरीदाबाद डिपों में भी कोई ज्यादा बसें नहीं जली थी कि वहां के लोग बसों की सेवाओं से वंचित हो जाएं यह कोई ठीक बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, पीछे की बात तो अलग है लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि जब मन्दिर-मस्जिद का विवाद छिड़ा तो सरकार की वह नीति थी कि गांवों में बसों का जाना बिल्कुल बंद कर दो। यहां तक तो यह बात ठीक थी परन्तु आज कौर सा ऐसा

विवाद छिड़ा हुआ है कि वहां पर बसें नहीं जा रही हैं, क्या मुख्यमंत्री जी सर अरज की सरकार पलवल की जनता से कोई बदला लेना चाहती है? उपाध्यक्ष महोदय, वहां के एक भी गांव में एक भी बस सेवा नहीं है क्योंकि यह आदे 1 दिए गए है कि गांवों में बसों का जाना बिल्कुल बंद कर दो। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्र न दिया था जो अतारांकित था कि जिला फरीदाबाद में जो हरियाण रोडवेज के जी०एम० हैं या जो आर०टी०ए० हैं, उन्होंने विभिन्न प्रकार के चालानों और जुर्मानों से जिला फरीदाबाद से कितनी आय की वसूली की। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे हैरानी होती है कि 12 लाख 45 हजार 976 रूपए हरियाणा रोडवेज के जी०एम० चालान और जुर्माने से वसूल किए हैं और आर०टी०ए० ने जुर्माने और चालानों से 53 लाख 58 हजार 595 रूपए वसूल किए है। (घण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात समझ नहीं आती कि हमारे द्वारा बनाए हुए किस कानून में किसी जी०एम० और किसी आर०टी०ए० को यह ताकत दी है कि वह लोगों को पांच-पांच या दस-दस हजार रूपए जुर्माने का वसूल कर सकें। इसी प्रकार से मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। हमारी सरकार का दावा रहा है कि इन्होंने लड़कियों की शिक्षा फ्री शिक्षा कर दी है। लेकिन आज सदन में मंत्री महोदया ने यह स्वीकार किया है कि जिला पलवल में 14 स्कूल ऐसे है जो दूसरी बिल्डिंग में चलते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात दावे के साथ कहता हूं कि जितना किराया ये उन बिल्डिंग का भर चुके हैं, अगर उस पैसे को बिल्डिंग बनाने में खर्च करते तो आज सरकार की अपनी बिल्डिंग होती। वहां पर कुछ प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं, जिनकी हालत इतनी खस्ता है कि पता नहीं वे कब गिर जाएं और बच्चे

मर जाएं। सरकार को इस बारे में कोई चिंता नहीं। दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, डी-सैन्ट्रल्राईजे इन और प्लानिंग के तहत जो पैसा जाता है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सरकार के पास एक डिमांड का भी ब्यौरा नहीं है कि इन्होंने इतना पैसा वहां-2 पर खर्च किया है। करोड़ों रुपये की राशि। डीसैन्ट्रल्राईजे इन पर प्लानिंग के तहत आती है। हमने मांगे राम गुप्ता जी का कह कि हमें इस ब्यौरे के बारे में कुछ पता नहीं है। यहां तो यह पास हो जात है कि इतना लाख रुपया फलां गांव और फलां म्युनिस्पल कमिटी में जाएगा और उसके बाद वह पैसा काहं खर्च हुआ, कहां गया, इसका कोई भी ब्यौरा न ग्रिवसिंज कमिटी में आता है और न ही मैं समझता हूँ कि सरकार में आता होगा।

**Mr. Deputy Speaker:** Dalal Sahib, Please wind up.

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** ठीक है जी, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा बातें नहीं कहनी हैं। इन्होंने प्रदे 1 लेवल पर कृषि विज्ञान केन्द्र हर जगह खोल है। हरियाणा में दो-तीन जिले हैं जहां इनकी लोके इन ठीक नहीं है, जैसे कि फरीदाबाद है। इसमें पलवल चूंकि सबसे पुरानी तहसील है और इसके चारों तरफ बल्भगढ़, हथीन, हसनपुर आते हैं इसलिए पलवल उन सबके बीच में आता है। यहां पर एक कृषि विज्ञान केन्द्र था जिसका दफतर भी पलवल में ही था लेकिन अब वह अधिकारियों की मिलिभगत के कारण फरीदाबाद में आ गया है, जहां ज्यादातर उद्योगपति हैं या अन्य दूसरे लोग हैं जिना इस कृषि विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। हमारे बार-बार अनुरोध करने पर भी सरकार ने अभी तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। हम चाहते हैं कि

यह केन्द्र पलवल में वापस लाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय इसी प्रकार से एग्रीकल्चर में एक “काडा” का महकमा होता है। वह ‘काडा’ का महकमा भी पहले पलवाल में ही हुआ करता था। लेकिन एक पुलिस के डी०आई०जी० का अपना मकान किरायें पर उठाने के लिए, जो फरीदाबाद में है, इस काडा के दफ्तर को अपनी कोठी में फरीदाबाद ले गए। जब वह ‘काडा’ पलवल में हुआ करता था, तो काफी जमींदार आते थे और उससे फायदा उठाते थे, ज्ञान की बात किया करते थे। उपाध्यक्ष माहेदय, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो दफ्तर लोगों की सेवा के लिए है, उसको इस तरह से उठाकर फरीदाबाद ले जाया गया। हर अधिकारी, हर विधायक या हर मंत्री लोगों की सेवा करने के कलए ही है। मेरे ख्याल से भायद ही कोई अफसर ऐसा होगा जिसकी कोठी फरीदाबाद में न हो, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन महज एक अधिकारी की कोठी को किराए पर देने के लिए इस ‘काडा’ के दफ्तर को फरीदाबाद लाकर किसानों का नुकसान किया जाये, तो यह कोई अच्छी बात नहीं है (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, प्लानिंग कमीशन की तरफ से यह बात रखी गयी है कि जो जिला ज्यादा साक्षर होगा, ज्यादा लिट्रैसी का होगा, उस जिले को ज्यादा ग्रांट दी जायेगी। सर मेरे क्षेत्र पलवल में घतीर, अहरावा, जनौली, बिधौड़ इतने बड़े-बड़े गांव हैं लेकिन वहां पर लड़कियों के लिए केवल एक ही प्राईमरी स्कूल की व्यवस्था है। इसी प्रकार से बिधौड़ में भी, जिसकी आबादी बीस हजार से ज्यादा है, लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को ऐसी नीति बननी चाहिए कि या तो जनसंख्या के आधार पर स्कूलों को अपग्रेड करें या हल्के-वाईज या जिलेवाईज स्कूलों को अपग्रेड करे



जबकि इस तरह की कोई भी बात नहीं हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से कम्युनिटी डिवैल्पमेंट की बात है। मैं इस बारे में दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो पिछड़े हुए वर्ग है, हरिजन हैं या जो दलित लोग हैं, उनके लिए वहाँ पर कम्युनिटी सेंट्रज या कॉमन लैटर्रीज की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमारे पलवल में कस्बा मौहल्ला, जैनीपुरा मौहल्ला सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमारे पलवल में कस्बा मौहल्ला, जैनीपुरा मौहल्ला में जो हरिजनों की बड़ी-बड़ी बस्तियां हैं, उपाध्यक्ष महोदय, वहाँ की औरतों को 6-6 किलोमीटर दूर लैटर्रीन के लिए जाना पड़ता है। सरकार से बार-बार अनुरोध करने पर अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह से पलवल के कैम्प में एक कम्युनिटी हाल बना हुआ है। सरकार का इस हाल पर कम से कम 7-8 लाख रूपया खर्च हुआ है लेकिन इस हाल पर आज तक छत नहीं डाली गयी है इसीलिए भाहर के जितने भी आवारा पशु हैं, वे उसके अन्दर घुते रहते हैं (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, फाईनैस की जो ग्रांट्स रखी गयी है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस सरकार ने इलैक्शन लड़ा था तो बहुत लम्बे-चौड़े वायदे किए थे। उनमें से यह भी था कि जो बुजुर्ग 60 साल के होंगे उनको हम पेंशन देंगे। लेकिन आज हर गांव में यह सरकारी फरमान पहुंचता है कि 80 लोगों की पेंशन काट दी गयी, 20 लोगों की पेंशन काट दी गयी। उपाध्यक्ष महोदय, या तो यह साफ कहें कि सरकार यह पेंशन देने में असमर्थ है क्योंकि लोग इस तरह से बेइजती महसूस करते हैं, उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। यह कोई अच्छी बात नहीं है (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी चले गये हैं। मैंने पहले भी यह बात

कही थी कि हमारे पलवल में बाहमनी खेड़ा गांव की 17 साल की एक ब्राहमण लड़की को, 10 तारीख को कुछ गुंडे उठाकर ले गये और उसके साथ रेप किया तत्प चात उसका मर्डर किया उपाध्यक्ष महोदय, मैं वहां से 20 तारीख से चला हूं लेकिन आज तक उन लोगों को पकड़ा नहीं गया है। तो यह इस सरकार की कानून और व्यवस्था रह गयी है और इस प्रकार की कानून व्यवस्था का यह सरकार ठीक होने का दावा करती है। (घंटी)

**श्री उपाध्यक्ष:** दलाल साहब, आप बैठिए। आपका टाइम समाप्त हो चुका है। अमीर चन्द मक्कड़ जी अब आप बोलिए।

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** .....

.....

**Mr. Deputy Speaker:** Dalal Sahib you please sit down.  
Shri Ram Rattan Ji you also please sit down.

**Shri Karna Singh Dalal:**

.....

**Shri Ram Rattan:**

.....

**Shri Karna Singh Dalal:**

.....

**Mr. Deputy Speaker:** All that has been said without my permission will not go on record. अब मक्कड़ साहब बोलेंगे।

**श्री अमीर चन्द मक्कड़ (हांसी):** उपाध्यक्ष महोदय, यह जो डिमांड्ज रखी गई हैं, मैं इनके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ( गोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती चन्द्रावती:** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ़ आर्डर है। यह जो डिमांड्ज हैं यह 1986-87 की हैं और ये अब इनको रैगुलराईज करवाने के लिए लाए हैं। हम तो इस पर बोलेंगे ही। उसके बाद दो सरकार बदल चुकी हैं। दो-दो चीफ़ मिनिस्टर बदल गए हैं। पहले चौधरी देवी लाल की मिनिस्ट्री थी, अब चौधरी भजन लाल की मिनिस्ट्री है। सरकार इस मामले पर अपना ऐक्प्लेनेशन दे कि इन्होंने इन डिमांड्ज को रैगुलराईज करवाने में इतनी देरी क्यों लगाई? (व्यवधान व भाोर) यह जो डिमांड यहां पर ला रहे हैं, यह आपको एजेंडे पर एडमिट नहीं करनी चाहिए थीं। वर्ष 1986-87 की डिमांड्ज तो आपको बिल्कुल एडमिट नहीं करनी चाहिये थीं और न ही इनको एजेंडे पर लाना चाहिये था। मैं यह कहती हूं कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की दोबारा मीटिंग बुलानी चाहिये। और उस मीटिंग में यह बात बिल्कुल आनी चाहिए। यह इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे अकाउन्टेंट जनरल को भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि 1986-87 की डिमांड्ज अब कैसे आर रही हैं? यही नहीं, पांच-पांच साल पहले की रिपोर्ट भी हाउस में आती हैं। इतनी देरी से इन रिपोर्टों के आने के कारण हम अपनी बात नहीं कह सकते। वास्तव में जो घपले होते हैं, यहां पर देरी से रिपोर्ट आने की वजह से हम उन घपलों के बारे में अपनी बात नहीं कह सकते। सरकार को इस बात की

एक्सप्लेने इन देनी चाहिए और इसको आज के एजेंडे पर नहीं रखना चाहिये था।

**श्री उपाध्यक्ष:** बहिन जी, अब आप उठकर जा रही हैं, जवाब तो सुन लें। देखिये, जहां तक डिमांड्स का असैम्बली के अन्दर आने का ताल्लुक है, it is as per the provisions of the Constitution. जहां तक देरी की बात का ताल्लुक है, उस बारे में भायद फाईनांस मिनिस्टर साहब कुछ कहेंगे।

**वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता):** डिप्टी स्पीकर साहब बहिन चन्द्रावती जी हमारी बहुत सीनियर मैम्बर हैं। आपनको कानून का पता ही है।

**साथी लहरी सिंह:** सीनिय नहीं हैं, she is the senior most member in the House.

**श्री मांगे राम गुप्ता:** आपकी बात ठीक है। डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें सिर्फ संवैधानिक अड़चन है, और कोई दिक्कत नहीं है। लेट होने के बारे में भी हमारी सरकार का कोई कसूर नहीं है। आर्टीकल 205 आफ दी कांस्टीच्यू इन के तहत ऐसा प्रावधान है कि जो कुछ बजट प्रोवीजन था, अगर उससे एक्सस पैसा डिपार्टमेंट खर्च कर ले तो उसको रैगुलेराईज कराना पड़ता है। वह विधान सभा से या पार्लियामेंट से पास होता है। यह बजट पास हुआ विधान सभा में 1986-87 में, ओर इस बारें में आडिटर जनरल की रिपोर्ट 21-2-1989 को आयी। वह रिपोर्ट पी०ए०सी० के पास गयी जो विधान सभा की एक

कमेटी ह। उसने 22-4-92 को इस बारे में अपनी रिपोर्ट पे 1 की। 22-4-92 को यह रिपोर्ट पे 1 होने के बाद हम आर्टिकल 205 की दिक्कत को पूरी करने के लिये विधान सभा के सामने, चूंकि इसे लाना जरूरी था, इसलिये इसे लेकर आये हैं। इस में कोई किसी किस्म की कोताही नहीं हुई है। इन डिमांडज के बहाने दलाल साहब ने अपनी बात हाउस में कह ली और मक्कड़ साहब भी अग बोल रहे हैं। इसका फायदा यही है, और कोई फायदा नहीं है।

**चौधरी आम प्रकाश बेरी:** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहब, जैसे कि अभी फाइनांस मिनिस्टर साहब ने बताया है कि एक्ससैस डिमांडज को, आर्टिकल 205 आफ दी कांस्टीच्यूशन आफ इंडिया के तहत, विधान सभा को अधिकार मिलता है कि वह उनको रैगुलराईज कर सके। अब चूंकि यह सारा पैसा खर्च हो चुका है, इसलिये इस बारे में मैम्बर साहेबान का अपने हल्के की मांग रखना बेकार है क्योंकि बजट तो पास हो चुका है। यह पैसा भी वहां पर खर्च किया जा चुका है। यह सारे बाते इररैलैवेन्ट हैं। मेरे ख्याल में हाउस का समय इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिये। यह पैसा तो खर्च हो चुका है। इस पर डिस्कशन करना कोई जायज बात नहीं है। इस बारे में मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा।

**श्री अमरी चन्द मक्कड़:** डिप्टी स्पीकर साहब, जैसे गुप्ता जी ने बताया कि ऐसा कोई लैकूना है उसके तहत हम अपनी बात यहां हाउस में कह सकते हैं। मैं 1986-87 की डिमांडज पर बोलते हुए अपने हल्के की कुछ मांगे यहां पर रखना चाहूंगा। यह बात ठीक है कि यह

पैसा तो खर्च हो चुका है लेकिन मैं अपाकी मार्फत सरकार के ध्यान में कु सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं। इन डिमांडज में सड़कों के बारे में भी डिमांड है। मैं उस पर बोलते हुए अपने हल्के की कुछ लिंक रोडज जो बननी रह रही हैं, के बारे में प्रार्थना करना चाहता हूं कि उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाये।

**Shri Ram Pal Singh Kanwar:** On a point of clarification, we want to know, how is it relevant to this demand? When the money has already been spent in the year 1986-87, on what matter are we discussing now? Now he is saying that these works in this constituency should be done, how is it relevant? The Finance Minister has already said that the money which has already been spen in excess in the year 1986-87 has to be regularised by the Assembly. There cannot be any discussion on those demands and there cannot be any further demand on those demands. My question is how is it relevant? We want your ruling on this.

**Mr. Deputy Speaker:** As I stated earlier that the discussion which is taking place now is under Article 205 of the Constitution of India, because these demands are to be regularised by the Assembly. So, the discussion is taking place and these demands are under consideration of the House.

**Shri Hari Singh Nalwa:** Discussion on what? This is what we want to knwo?

**श्री राम पाल सिंह कंवर:** जो पैसा खर्च हो चुका है, उस पर डिस्कान का क्या फायदा है? फ्यूचर में खर्च करने के लिये तो पैसा

दिया नहीं जा रहा है जो मैम्बर साहब अपने यहां की प्रोबलम्ज रख रहे हैं?

**श्री अमीर चन्द मक्कड़:** डिप्टी स्पीकर साहब मेरे साथी एतराज कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे यहां पैसा खर्च होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे इलाके में भी बजट से ज्यादा पैसा खर्च होना चाहिए। ( गोर एवं व्यवधान)

**Shri Ram Pal Singh Knanwar:** How are you allowing the discussion on the amount which has already been spen in the year 1986-1987 and which has fo be regularised by the Assembly? There cannot be any further discussion on that.

**Mr. Deputy Speaker:** The money is to be regularise by the Assembly and he is raising discussion on that (Interruptions). Makkar Sahab, you please continue your speech.

**श्री अमीर चन्द मक्कड़:** डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना है कि मेरे इलाके में भी सड़कें बननी चाहिए। जो सड़कें बननी चाहिए वे हैं— खरखड़ा से हांसी, सुल्तानपुर से डंडेरी, बाटला रोड से धर्मपुर, कुतबपुर से कुलाना, जींद रोड से डानी चांदपुर, डीपल से मामनपुरा और जी०टी० रोड से ढानाकलां। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना है कि गांवों में जो सड़के अधूरी पड़ी है, उनको पूरा किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं माईनर्ज के बारे में कहना चाहता हूं मेरे हल्के में एक सुल्तानपुर माईनर है। वर्ष 1986-1987 में वह मन्जूर हो चुकी थी, उसका एस्टीमेट भी बन चुका था और उस पर काम भी

भारु हो चुका था लेकिन किसानों की हितैशी कहे जाने वाली सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उस माईनर को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। दूसरी बीड माईनर है, उस पर काफी दिनों से काम चल रहा है। मेरी प्रार्थना है कि उसको जल्दी ही पूरा किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, डिमाण्ड नम्बर प्रार्थना है कि उसको जल्दी ही पूरा किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय डिमाण्ड नम्बर 18 पं. 10 पालन के बारे में हैं। मेरे हल्के में सीसर खरबला, उमरा सुलतानपुर और कुलाना में पं. 10 पालन का अस्पताल बनना चाहिए ताकि लोगों की तकलीफ दूर हो सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमाण्ड नं० 24 के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे हांसी के अन्दर एक टूरिस्ट कम्पलैक्स का बनाया जाना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि वह एक बहुत बड़ा भाहर है ताकि वहां पर जितने यात्री आएँ, उनको इस तरह की सहूलियतें मिल सकें। सरकार से आशा है कि सरकार मेरे इस सुझाव पर अवश्य विचार करेगी और वहां पर टूरिस्ट कम्पलैक्स बनाएगी।?

इसके साथ डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अयोध्या में जो घटनाएं घटीं, उस बारे में कुछ कहना चाहूंगा जैसे हम इस देश के वासी होने के नाते यह दावा करते हैं कि यहां पर हिन्दुइजम है। यहां पर हर धर्म के लोग बसते हैं। गंगा-यमुना-सरस्वती जैसी बड़ी-बड़ी पवित्र नदियों के जलधारा बहती हैं और सभी धर्मों के लोगों को इनका जल पीने का अधिकार है चाहे कोई किसी भी कौम का हो, उन सब को इन नदियों के जल को ग्रहण करने का पूरा अधिकार है। उसी तरह से हर धर्म के



मानने वाले को अपने अपने धर्मों के प्रति पूजा पाठ का पूरा पूरा अधिकार है। हर दे आवासी को अपने धर्म की रक्षा करने व प्रचार करने का पूरा हक हमारे संविधान के अन्दर विद्यमान है। सभी को पूरी आजादी है। इस महान भारतवर्ष में कितने बड़े बड़े सन्त महात्मा हुए, पीर पैगबर हुए। इस दे आ में गुरुनानक जैसे व गौतम जैसे उच्च ऋशि व संत हुए।

**प्रो० छत्तर सिंह चौहान:** डिप्टी स्पीकर साहब मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह किस डिमांड पर बोल रहे हैं? यूंही ऐसा मसला उठा रहे हैं और हाउस का कीमती समय बरबाद कर रहे हैं। इनको ऐसी बातें कहने से रोका जाना चाहिये। यह मसला किसी भी डिमांड पर आधारित नहीं है। ( ओर एंव व्यवधान)

**श्री अमरी चन्द मक्कड़:** डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इसकलए इस बात का जिकर कर रहा था कि कल कुछ भाइयों ने मेरे बारे में कहा था कि मैं राम का विरोधी हूं। इन लोगों ने जो कुछ वहां करवाया तभी मुझे इस बात का जिकर करना पड़ रहा है। ई वर इनको सनमती दे। महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा था कि ई वर अल्लाह तेरो नाम, सब को सनमति दे भगवान। मैं तो ई वर से यह प्रार्थना करूंगा कि ई वर इन सब भाइयों को सनमति दे और ये लोग सभी महात्माओं, संतो ओर पीरों व ऋशिमुनियों के चलाये हुए रास्ते पर चलें। जो उपदे आ श्री राम जी ने अपने रामराज में दिये थे, उन के बताए हुए रास्ते पर ये लोग चलें। मेरी ई वर से यही प्रार्थना है। सभी कौमें एक बराबर हैं। किसी के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यहार करान संविधान में नहीं लिखा है।

**श्री उपाध्यक्ष:** मक्कड़ साहब, आप कृपया अनी डिमांडज पर ही बोलें।

**श्री अमीर चन्द मक्कड़:** ठीक है डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमांड पर ही आता हूँ इनको सच्ची बातें सुनने में भाग्यद कोई तकलीफ का अनुभव हो रहा है। चलो मैं नहीं कहता। कहने तो वे कितने ही सैकुलर बनते फिरें, लेकिन ये लोग गुरुओं, संतों व ऋशियों के बताए हुए मार्ग पर चलना ही नहीं चाहते। इतना ही कहता हुआ कि जो कुछ इस मुल्क के अन्दर ऐसी भाक्तियों ने करवाया है, वह निन्दास्पद है अन्त में इतना कहता हुआ अपना स्थान लेता हूँ कि जितनी भी डिमांडज के मुताल्लिक मैंने सरकार से प्रार्थना की है, उन सभी डिमांडज पर सरकार अब य विचार करे ओर उन्हें पूरा करने का भरसक प्रयत्न करें। धन्यवाद।

**प्रो० छत्तर सिंह चौहान (मुंडाल खुर्द):** उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। सब से पहले मैं डिमांड नं० 9 को एजुके ान से संबंधित है, पर बोलना चाहूंगा। हरियाणा में आज िाक्ष का स्तर मेरे ख्याल में हिन्दुस्तान की उन प्रांतों जैसा है जिनमें निम्न से निम्न स्तर कहा जाता है। इसके लिए सरकार कितने कदम उठा रही है? पीछे अप्रैल में जो मैट्रिक और दस जमा दो के एग्जाम हुए थे, उनके बारे में मुख्य मंत्री और िाक्षामंत्री ने आ वासन दिया था कि इन्कवायरी करावाई जाएगी। यह भी कहा था कि चाहे कोई भी हआदमी किसी भी पद पर आसीन हो, अगर उसका दोश होगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने में कोताही

नहीं होगी। लेकिन पूरा साल बीतने के बाद भी कोई भी प्रभाव गाली कदम नहीं उठाए गए। शिक्षा के संबंध में विशेष रूप से हायर एजुकेशन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट कालेजिज का 70 प्रतिशत भारत पहले सरकार उठाती थी। उसके बाद 1-1-1986 से ग्रेड रिवीजन की गई थी। उस वक्त सरकार ने प्राइवेट कालेजिज को आवासन दिया था कि कालेजिज का 95 प्रतिशत भारत सरकार उठाएगी। आज 1993 का साल भुरु होने वाला है। और जिस कालेज में उस समय यानी 1986 में 600 स्टूडेंट्स थे, आज उनकी संख्या बढ़कर तीन हजार तक हो गई है। लेकिन पोस्टों के बारे में सरकार ने नियम बना रखा है कि जो पोस्टें 1-1-1986 को सैंकंड थीं, उन्हीं का 95 प्रतिशत खर्चा देगी जबकि कालेजों के उपर उसके बाद दोगुना और तीन गुना भार बढ़ गया है। उसको वहन करने के लिये सरकार तैयार नहीं है। जुलाई 1991 में डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने प्राइवेट कालेजिज को एक लैटर लिख कि वे कोई नई भरती नहीं कर सकते। मुझे एक बात याद आ गई है। सैकिंड वर्ल्ड वार के समय जब चर्चिल प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने सभी डिपार्टमेंट्स के खर्चे कम कर दिए लेकिन एजुकेशन का खर्च कम नहीं किया। उनके मन्त्रियों ने उनसे पूछा कि आपने सभी डिपार्टमेंट्स का खर्चा कम कर दिया लेकिन एजुकेशन का क्यों नहीं किया, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने कहा था कि मैं आने वाली देश की पीढ़ी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। लेकिन हमारी हरियाणा सरकार एजुकेशन के लिए पूरा पैसा नहीं देती और न ही मैनेजमेंट टीचर्स को पूरी तनखाह देती है जबकि वह स्टूडेंट्स के हिसाब से स्टाफ भरने की इजाजत दी जाए। मैं आपके

माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि प्राइवेट कालेजिन में स्टाफ और स्टुडेंट्स की वही रे गो हो, जो गवर्नमेंट कालेजिज में है। इसके अलावा प्राइवेट कालेजिज के उपर एक पाबन्दी है। आप हैरान होंगे कि अगर गवर्नमेंट कालेज में कोई पार्ट टाइम लैक्चरार नियुक्त करना हो तो उसे 2500 रुपये महीना दिए जाते हैं। लेकिन प्राइवेट कालेजिज को कहा जाता है कि 500 रुपए देकर पार्ट टाइम के लिये लैक्चरार लगाएं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि गवर्नमेंट कालेजिज और प्राइवेट कालेजिज में इतना भेद भाव क्यों किया जा रहा है? आज हरियाणा में जे०बी०ट० टीचर्स और लैक्चरार्स की कोई कमी नहीं है लेकिन आप किसी भी स्कूल या कालेज में चलें जाएं, कहीं पर भी आपको हैडमास्टर नहीं मिलेंगे, प्रिंसिपल नहीं मिलेंगे, साईंस मास्टर नहीं मिलेंगे और सोशल स्टडी मास्टर नहीं मिलेंगे। हरियाणा के अन्दर एक तरफ तो लोग बेकार बैठे हैं और दूसरी तरफ सरकार उनको कोई काम नहीं दे रही है जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाने वाले नहीं हैं। बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार ने पिछली बार अध्यापकों की जो भर्ती की, उसके बारे में लोगों ने उंगलियां उठाईं। ...

.....  
( गोर)

**लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री आनन्द सिंह डांगी):** डिप्टी स्पीकर साहब, जैसे वाली बात रिकार्ड पर नहीं आनी चाहिए।

**Mr. Deputy Speaker:** This has nothing to do with the subject under discussion. This will not go on record. Please speak on the subject only.

**प्रो० छत्तर सिंह चौहान:** डिप्टी स्पीकर साहब, आप सर्वे सर्वा हैं। हम आपका हुक्म मानेंगे। अब मैं डिमांड नम्बर 8 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा जोकि बिल्डिंग एण्ड रोड के बारे में हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री माहेदय का ध्यान भिवानी जिले की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। भिवानी जिले में जितने भी सड़कें हैं, उनकी हालत बहुत खराब हैं। हमारी ग्रिवेंसि कमेटी में पहले तो बहिन करतार देवी जाती थीं लेकिन आजकल श्री ए० सी० चौधरी जाते हैं। श्री ए० सी० चौधरी और बहिन करतार देवी ने खूद माना है कि भिवानी जिले की सड़कों की दशा बहुत भावनीय और दयनीय है। पिछले बजट सेशन में इस सरकार के मुख्यमंत्री जी ने बड़े अदब के साथ हाउस में कहा था कि 31 मार्च 1992, तक सभी सड़कों की मरम्मत कर दी जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि भिवानी जिले की चाहे कोई एप्रोच रोड हो और चाहे बड़ी रोड हो, सभी सड़कों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वहां पर नई सड़कें बनाना तो दूर रहा, जो पुरानी सड़कें हैं, उनकी मरम्मत भी नहीं करवाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि माननीय सदस्यों के हल्कों की जो भी बात हो उसे वे लिख करके भेज दें, उस पर जरूर गौर किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी को याद होगा, इन्होंने मार्च में एक बात कह थी कि आज हरियाणा में कोई गांव ऐसा नहीं है, जिसकी आबादी एक हजार की हो

और वह सड़क से न जुड़ा हो। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में एक गांव ऐसा है, जिसकी आबादी 1000 नहीं बल्कि 1000 वोट वहां पर बनी हुई हैं। वह गांव आज तक सड़क से नहीं जुड़ पाया है। कल माननीय मंत्री ने कहा था कि उस गांव की सड़क से जोड़ देंगे लेकिन आपने कहने से नहीं बल्कि लोगों के कहने से जोड़ेंगे। मैं तो यही कह रहा हूँ कि उस गां को सड़क से जोड़ दिया जाए। मेरे कहने से न सही, लोगों के कहने से ही सही लेकिन उस गांव तक सड़क बना दी जाये, आपकी मेहरबानी होगी। (विघ्न) डांगी साहब, आप वह दिन भूल गए जब आप भी एक साधारण आदमी की तरह मदीना में घूमते थे। आज आप एक जिम्मेवार मंत्री पद को सु गोभित कर रहे हैं, इसलिये अब आपकी जिम्मेवारी भी बढ़ गई है।

**श्री आनन्द सिंह डांगी:** चौहान साहब, जो कुछ मैंने किया है, वह साधारण लोगों के लिये ही किया है।

**प्रो० छत्तर सिंह चौहान:** यहां पर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उस सड़क को 31 मई 1992 से पहले पहले सड़क से जोड़ दिया जायेगा लेकिन आज तक वह सड़क पूरी नहीं हुई। अब संबधित मंत्री कह रहे हैं कि इस सड़क को 30 जून, 1993 तक जोड़ दिया जाएगा। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि जब मुख्य मंत्री जी के आ वासन का यह हाल है, तो मंत्री जी को आ वासन का क्या होगा?

**श्री आनन्द सिंह डांगी:** जो हमने कह दिया सो कह दिया।

**प्रो० छत्तर सिंह चौहान:** अच्छी बात है आ ता है आप अपनी बात पर कायम रहते हुए उस सड़क को जल्दी से जल्दी बना देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नं० 15 जो सिंचाई से संबंधित है, के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इस समय सिंचाई मंत्री जी सदन में बैठे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि भिवानी जिले में दो ग्रुप हैं। अब इनका नाम बदल कर बुटाना ग्रुप कर दिया है। कोई बात नहीं नाम बदलते रहते हैं और आदमी और उनके कार्य बदलते रहते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमने मुख्यमंत्री महोदय को लिखित रूप से बड़े विस्तार के साथ लिख कर दिया है और इसके अतिरिक्त ग्रिवेंसिज कमेटी में जो इनके एक मंत्री, प्रतिनिधि के यप में जाते हैं, उनके सामने भी यह बात रखी है कि भिवानी जिले में पानी बहुत कम जा रहा है। यह तो रिकार्ड की बात है कि जुलाई 1991 से लेकर आज तक वहां पर 40 परसेंट से ज्यादा पानी नहर में नहीं पहुंचा। इसके अतिरिक्त भिवानी जिले की नहरें रेत से भरी पड़ी हैं, जब तक उस रेत को नहीं निकाला जायेगा, पानी भी पूरी तरह से नहीं जा पायेगा। इस बारे में मेरी प्रार्थना है कि वहां की नहरों की डी.सिलिंटिंग की जाये। इसके अतिरिक्त एम०आई०टी०सी० की तरफ से जो खलें बनाई गई थी, वह भी टूट गई हैं। आज उनकी रिपेयर की आवश्यकता है। वहां पर मेरी सिंचाई मंत्री जी से प्रार्थना है, यदि एक मंत्री एक एम०एल०ए० के कहने पर सड़क न बनाने की बात कहता है तो सिंचाई मंत्री जी से प्रार्थना है कि आप तो कम से कम मेरी बातों पर ध्यान देते हुए भिवानी जिले में पूरा पानी पहुंचाने की कृपा करें।

आपको पता है कि पानी की काफी कमी है और वह इलाका 50 प्रति 100 बारिश पर ही निर्भर करता है। यदि वहां पर पानी का इंतजाम नहीं होगा तो उस इलाके की क्या दशा होगी, आप भी इस बारे में अच्छी तरह से जानते हैं वैस्टर्न जमुना कैनल में यदि पानी की कमी है तो इस कमी को पूरा करने के लिए भाखड़ा से इस नहर को लिंक करके पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है। डांगी साहब, दादरी फीडर से आप के इलाके को भी पानी मिलता है। आपके इलाके को तो चोरी छिपे पूरा पानी मिल जाता है लेकिन हमारे इलाके में पूरा पानी नहीं पहुंच पाता। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भिवानी जिले की पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए वहां पर पानी पहुंचाने का प्रबन्ध किया जाये।

**लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के) मंत्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी):** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सीधा मेरा नाम लेकर एक बात कही है। इन्होंने कहा है कि जो नहर हमारे इलाके से निकल कर आगे इनके इलाके में जाती है, हमारे लोग उसका पानी चोरी छिपे काट लेते हैं और इस वजह से इनको पानी कम जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह बात गलत है। रिकार्ड उठा कर देख लें, जितना पानी इनको मिलना चाहिये था उससे ज्यादा ही मिला है। इरिगेशन मंत्री महोदय यहां पर बैठे हैं अगर माननीय सदस्य चाहें तो रिकार्ड मंगवा कर देखा जा सकता है कि इनको पानी कितना मिला है।



**प्रो० छत्तर सिंह चौहान:** डिप्टी स्पीकर साहब मुझे इनका चैलेन्ज मन्जूर हैं ये जुलाई 191 से 1992 तक का रिकार्ड मंगवा कर देख लें। दादरी फीडर में जितना पानी जाना चाहिये था, अगर उसका 60 प्रति त भ गया हो तो मैं इनका कसूरवार हूं। हम लोग कागजों का रिकार्ड नहीं देखते हैं, हम तो खेतों में जाकर देखते हैं कि कितना पानी दिया जाता है। नेहरा साहब यहां पर बैठे है। अगर आप इतनी कृपा करें तो हम मौके पर चलते है। मैं इनके साथ चलने को तैयार हूं। आपके पास सरकारी गाड़ी है इसलिए इनकी जेब से कोई पैसा भी नहीं लगना है। दादरी फीडर पर चलते हैं। अगर भिवानी डिस्ट्रीब्यूटरी में उसके हिस्से का 40 प्रति त पानी भी चल रहा होगा, तो मैं मा लूंगा। यह कहना बहुत ही सहज है कि पूरा पानी चल रहा है लेकिन पानी पूरा नहीं हैं अगर हम लोग आज विपक्ष में हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम गलत फैक्टस कहते हैं। जो बात आलोचना करने की है वह तो हम कहेंगे ही लेकिन अगर सरकार कोई अच्छी बात करती है तो हम सरकार की तारीफ भी करते है। अपने हल्के की बात तो हम उठाएंगे ही और अगर किसी काम के लिए मुझे डांगी साहब के पास जाना पड़ेगा तो बिना किसी हिचकिचाहट के जा सकता हूं। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड नं० 6 फाईनैन्स डिपार्टमेंट से संबधित है। वित्त मंत्री महोदय भी बैठे है। सबसे बड़ी बात यह है कि जून 1991 में जब यह सरकार सत्ता में आई थी तो इसने बड़ी उदघोशणा की थी कि हमने पैं इन पाने वालों की उम्र घटा कर 60 साल कर दी है। उपाध्यक्ष महोदय, इस हिसाब से तो जितने लोगों को पहले पैं इन मिल रही थी, उससे ज्यादा लोगों को पैं इन

मिलनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप रिकार्ड मंगवा कर देख लीजिए इस सरकार से पहले जा सरकार थी, उस समय कितने लोगों को पैंान मिल रही थी और आज कितने लोगों को पैंान मिल रही है। 65 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र होने पर पैंान पाने वाले की संख्या बढ़नी चाहिए थी लेकिन वह घट कर 50 प्रतिशत रह गई है। मेरी कांस्टीच्यूएँसी के गांवों की लिस्ट मंगवा कर देख लीजिए। कितने ही लोग ऐसे रह गए हैं, जिनको पैंान मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिल रही है।

**श्री उपाध्यक्ष:** आपने अपनी सारी बातें कह दी हैं और आपका टाइम भी खत्म हो गया है, इसलिये अब आप बैठिए।

**प्रो० छत्तर सिंह चौहान:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी कुछ बातें और कहना चाहता था लेकिन आपकी बात मानते हुए और आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

**चौधरी अजमत खां (हथीन):** उपाध्यक्ष महोदय, जो डिमाण्डज हाउस में आई हैं, ये 5-6 साल के बाद आई है। अव्वल तो इन पर बोलना ही उचित नहीं है यह कौन सा अफसर है जिसेन 5-6 साल के बाद इन डिमाण्डज को यहां पर रखा है? वर्ष 1986-1987 की ये डिमाण्ड हैं, इन पर कोई क्या बोलेगा और क्या कहेगा, लेकिन फिर भी मैं अपने काम की एक बात इसमें से निकाल ही लेता हूँ। यह बात हरियाणा में एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में है। डिप्टी स्पीकर साहब, आज स्कूलों में पूरे टीचर्स नहीं हैं। हमारे नन्हें-नन्हें फूल स्कूलों में

पढ़ने के लिये जाते हैं। अगर वहां पर टीचर्स नहीं होंगे तो ये फूल पूरी तरह से खिल नहीं सकेंगे और कुम्हला जाएंगे उनके लिये सही ऐजुकेशन का प्रबन्ध होना चाहिये। आज स्कूलों में टीचर्स की भारी कमी है। जिस टीचर को जब चाहा उठा दिया, यह ठीक नहीं है। पिछले साल 15 मई 1991 की टीचर्स स्टेटमेंट के आधार पर टीचर्स को दोबारा लगा दिया जाना चाहिए। आज कितना कम स्टाफ है, उनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए टाइम नहीं है। अगर ऐजुकेशन का यही हाल रहा तो ये तमाम लोग न घर के रहेंगे न घाट के। ये चोर, डकैत, बदमाश, लफंगे बनकर रह जाएंगे। यह समाज इन पर थू-थू करेगा। इसलिए ऐजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय 100 बच्चों के उपर एक टीचर रखना चाहिए और यह क्राइटेरिया बना देना चाहिए। यह नहीं कि कहीं तो 4-4 और 10-10 टीचर फालतू रख दें और कहीं एक भी नहीं। जैसे ही 15 मई को स्टेटमेंट आतही है, वैसे ही इनको 15 जुलाई तक स्टाफ लगा देना चाहिए और जहां पर ज्यादा टीचर्स हों वहां कम कर देने चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय इस बारे में ज्यादा क्या बोलें यह तो बहुत ही पुरानी बात है। अगर ये 5-5 या 10-10 साल बाद डिमांडज लायेंगे तो इस बात से साफ जाहिरा होता है कि किस तरह से हमारे आफिसर्स काम करते हैं और क्या हमारी सरकार काम कर रही है। (घंटी) अच्छा जी धन्यवाद।

**श्री धर्मपाल सिंह (दादरी):** आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं० 9 के माध्यम से शिक्षा मंत्री को अपने ही हल्के की दिक्कतों के बारे में बताना चाहता हूँ। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, आप

सबको मालूम है कि हरियाणा के अन्दर शिक्षा नाम मात्र ही रह गई है। हर शिक्षा केन्द्र में नकल का बोल-बाला रहता है। मेरे हल्के के अन्दर एक मलोटा गांव है, जहां 10 जमा 2 का स्कूल है लेकिन वहां पर सिर्फ 6 ही अध्यापक हैं। आप ही हिसाब लगाएं, जहां 12 क्लासिज हों, 12 क्लासिज के दो-दो, तीन-तीन सैक एनज हों और 6 अध्यापक हों तो वे कितने सैक एनज को पढ़ा सकेंगे? मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदया को नोट कराना चाहता हूं कि वे इस तरफ ध्यान दें। दूसरे गृहकलां हाई स्कूल है वहां इससे भी बुरा हाल है वहां भायद तीन से भी कम अध्यापक हैं। इसी तरह से दादरी हल्के के दूसरे स्कूल हैं, जिनमें पांच-छः से ज्यादा अध्यापक नहीं है और वे 10 जमा 2 के स्कूल है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार चाहती है कि भिवानी हल्के को ही हरियाणा से काट दिया जाए तो ठीक है। इसे अलगा से एक स्टेट बना दिया जाए तो हमें कोई दुख नहीं होगा। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कर्मद्व योजना के तहत भिवानी जिले को बहुत पीछे धकेलने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहां पर शिक्षा नाम की चीज ही खत्म हो गई है। अध्यापकों की नई पोस्टें सैक एन नहीं की जा रही हैं। अगर कुछ पोस्टें हैं भी तो वे खाली पड़ी है इसी तरह से हमारे वहां पर एक कालेज है जिस में स्टुडेंट्स की भरमार रहती है। वहां पर 8-10 हजार बच्चे पढ़ते हे। वहां भी ये कोई पोस्ट नहीं दे रहे हैं और बच्चों को दाखिला देना पड़ता है। अगर दाखिला न दें तो वे हड़ताल कर देते हैं ओर कहते हैं कि हमें दादरी में ही दाखिला नहीं मिलेगा तो और कहीं कैसे मिलेगा? तो दाखिला मैनेजमेंट को देना पड़ता है लेकिन मैनेजमेंट कहां तक इस खर्चे को वहन करेगी? मैनेजमेंट की इतनी

हैसियत नहीं है कि वह इतने भारी खर्च को वहन कर सके। इसलिए मैं गुजारी करता हूँ शिक्षा मंत्री महोदय से और हरियाणा सरकार से कि जिस जगह पोस्टस हैं लेकिन खाली पड़ी हैं, वहां पर अध्यापकों को भेजें और जिस जगह पर जरूरत से ज्यादा अध्यापक हैं, वहां कम किए जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मेरा आपके द्वारा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि जहां पर लड़कियों के स्कूल या कालेज हैं, वहां सरकार को चाहिए कि लेडी हैड-मिस्ट्रेस और लेडी अध्यापिकाएं रखें यदि किसी खास स्थिति व वहां पर किसी अध्यापक को रखना भी पड़े तो उसकी उम्र को देखते हुए रखना चाहिए। इसी वजह से देवराल में एक घटना घटी वहां पर 30-35 लड़कियों के साथ रेप हुआ। जिसने रेप किया वह एक नौजवान अध्यापक था। उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ और सस्पेंड किया गया, अब वह जेल में है। मेरा शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध है, चूंकि ये खुद महिला हैं इसलिये, विशेष तौर पर पूरे हरियाणा में, लड़कियों के स्कूलों में इस बात का ध्यान रखें। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में मेरी एक और बात रह गई है कि दादरी हल्के में पिछले वर्ष दो स्कूलों को अपग्रेड किया जबकि और नींवली तीन स्कूल हैं। तीन गांव और हैं, अगर इस दफा इनाका कोई विचार है तो मेरा अनुरोध है इन गांवों को भी जरूर ये कंसीडर करें। अगर ये डांगी साहब की विचारधारा का ध्यान रखते हैं तो हमारे कहने से नहीं, लोगों के कहने से इन स्कूलों का जरूर ध्यान रखें।

उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड नं० 18 प गुपालन के बारे है। हमार इलाका विशेष तौर पर कृषि प्रधान है। नौकरियां इस इलाके में

कम है जमींदार होने का खतरा रहता है इसलिये आपको कम से कम हर पटवार हल्के में एक-एक पट्टा चिकित्सालय, दादरी हल्के में खोलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड नं० 23 का जहां तक संबंध है, इस संबंध में मैंने पहले भी एक क्वैश्चन के माध्यम से पूछा था और अब भी इस समय दादरी डिपो के अन्दर केवल 108 बसिज हैं जो एक सब-डिपो से भी कम हैं। जब आपने वहां पर इतनी कम बसिज दे रखी हैं तो फिर वहां पर जी० एम० या दूसरा स्टाफ लगाने की क्या जरूरत है? उपाध्यक्ष महोदय, दादरी डिपो में बसिज बहुत कम है। उनमें से भी सात बसिज ऐसी हैं जो बिल्कुल टूटी हालत में होने के कारण चलने के काबिल नहीं है। अगर ये बसें चलती भी हैं तो एक या दो किलोमीटर पर जाकर रुक जाती हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि दादरी डिपो में कम से कम पचास बसिज सरकार को और देनी चाहियं। अगर सरकार वहां पर बसिज देने में नाकामयाब है तो सरकार को कम से कम जी० एम० रोडवेज और आर० टी० ए० रोहतक को यह आदेश देना चाहिए कि जो प्राइवेट व्हीकलज वहां पर चलते हैं, उनका चालान न करें क्योंकि सरकार के पास इतने साधन ही नहीं हैं कि वहां पर ज्यादा बसें मुहैया करा सकें सरकार को, यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये प्राइवेट व्हीकलज वालों को इजाजत देनी चाहिए और उनका चालान नहीं करना चाहिए। हरियाणा के घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को, कम से कम प्राइवेट व्हीकलज वालों पर जुर्माना नहीं लगाना चाहिए। मेरी सरकार से यह विनती है कि वह इस तरह का व्यवहार न करें। सरकार तो घूती फिरती रहती हैं। आज इनकी सरकार है, कल को हमारी सरकार भी हो

सकती है इसलिये आज जैसी परिपाटी ये लोग डालेंगे, कल को वैसी ही परिपाटी हम डालेंगे वैसा ही अनुसरण हम करेंगे। अगर आप लोग सोचते हैं कि यह सब ठीक है तो कोई बात नहीं, कल को हम भी यहां बैठ सकते हैं जहां आज आप लोग बैठे हो। इसलिये मैं आपसे यही कहूंगा कि आप किसी मामले में भेदभाव न करें और सारे हल्कों को एक समान मानकर विकास करें। जयहिन्द।

**प्रो० रामबिलास भार्मा (महेन्द्रगढ़):** उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये आपका धन्यवाद। सर, यह अनुदान स्वीकृति से अधिक हो गया और 1986-87 से संबंधित है। हमारे वित्त मंत्री श्री मांगे राम गुप्ता जी खनदानी वित्त विभाग के विशेषज्ञ हैं। मगर फिर भी इन अनुदानों को रैगुलराईज कराने में इतनी देर क्यों लगी है, यह तो मंत्री जी ही बता सकते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, मैं भवन तथा सड़कें मांग संख्या आठ पर कहना चाहता हूँ पहले राजस्थान की तरफ से आने वाला सारा ट्रैफिक जी०टी० रो दिल्ली होकर जाता था लेकिन अब नांगल चौधरी भिवानी से हो गया है जबकि वहां सड़कें पहले की तरह अब भी सिंगल ही बनी हुई हैं। लगभग दो हजार व्हीकल्ज रोहतक दादरी, भिवानी से होकर जाने लगे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप उस सड़क की हालत स्वयं देखें तो आप देखेंगे कि उस सड़क की क्या हालत है? अगर आपको कभी बीकानेर जैसलमेर की तरफ जाने का सौभाग्य मिले तो आप देखेंगे कि इससे बुरी हालत किसी भी सड़क की नहीं होगी। जहां तक इस सड़क को नेशनल हाईवे बनाने की बात है, इस पर सरकार को गौर करना

चाहिए क्यों कि इससे बहुत सारा रैवेन्यू आ रहा है। इनके बेरियर्ज की जो संख्या है, या जो नम्बर आफ व्हीकल्ज हैं, उससे इन्कम वैरीफाई कर इस पर तुरन्त ध्यान दें।

एक बात मुझे माननीय बहन भान्ति राठी जी से कहनी है कि प्रौढ़ शिक्षकों का मामला बहुत दिन से लटका हुआ है। कोई दो-तीन हजार लोग हैं। काफी लोग तो इन्होंने एकोमोडेट कर लिए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इनमें कुछ लोग हैं जिन्होंने 10-15 साल तक प्रौढ़ शिक्षा के तहत काम किया है और अब उनकी उम्र 35 साल से अधिक हो गई है लेकिन उन्हें सरकारी सेवा में नहीं लिया जा सकता। कुछ दिन पहले ये प्रौढ़ शिक्षक बहिन जी से मिले थे और उन्होंने उनको आवासन भी दिया था कि कंडेन्सकोर्स बनाकर जी से मिले थे और उन्होंने उनकी आवासन भी दिया था कि कंडेन्सडकोर्स बनाकर इनको पक्का कर देंगे। हरियाणा में छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़ रही है और उस अनुपात में अध्यापकों की संख्या कम पड़ रही है। मैं मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि प्रौढ़ शिक्षकों के बहुत लम्बे समय से चले आ रहे इस आन्दोलन को देखते हुए इनको जे०बी०टी० मान लिया जाए या कोई 4-6 महीने का कंडेन्सड कोर्स चलाकर इनका समायोजन किया जाना चाहिए। नहीं तो हरियाणा के ये बेचारे तीन हजार भाई-बहन किसी नौकरी में नहीं आ सकेंगे। जो प्राइवेट और रिकोगनाइज्ड कालिजिज है, उनको सरकार 95 प्रतिशत अनुदान देती है। यू०जी०सी० से जो ग्रांट मिलती है, उसकी राशि लगभग एक करोड़ रुपये बनती है। उसको भी सरकार किसी कारण से उपयोग नहीं कर पाई।



मैं एक बात की राव इंद्रजीत सिंह के महकमें से गुजारि । करूंगा कि फौरेस्ट विभाग के लोग बहुत दिन से यह मांग कर रहे हैं कि उनकी नौकरी पुलिस के बराबर है। रात दिन उनको डियूटी देनी पड़ती है। अतः उनको पुलिस के समानान्तर सुविधाएं दी जाएं उनकी इस मांग पर सहानुभूति-पूर्वक विचार होना चाहिये और हरियाणा में जैसे फौरेस्ट का विस्तार हो रहा है और खासकर अरावली पर्वत के साथ-साथ हो रहा है उसको देखते हुए उन कमचारियों की मांगों को स्वीकार करके उनके वेतन इत्यादि रिवाईज कर दें तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा और वे बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री अमर सिंह जी, आप बोलिये।

**श्री अमर सिंह (बवानी खेड़ा-अनुसूचित जाति):** उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे डिमांडज पर बोलने का मौका दिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वैसे बहिन चन्द्रावती जी ने और चार पांच अन्य मेम्बरान साहिबान ने प्वायंट आउट किया था, परन्तु मैं भी यह बात कहना चाहता हूँ कि ये 1986-87 की मांगें हैं। क्या चार पांच साल तक पी०ए०सी० की कमेटी नहीं बनी थी? यदि बनी थी तो वित्त मंत्री जी बताएंगे कि इसमें किस वजह से डिले हुई? अब मैं डिमांड नं० 9 तथा 15 पर जो एजुके िन और इरीगे िन के बारे में हैं, पर कुछ समय लेना चाहता हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब, इरीगे िन डिपार्टमेंट के बहुत बेहतरीन काबिल मंत्री श्री जगदी ि नेहरा जी बैठे हैं। इरीगे िन में 10 करोड़ 7 लाख, 20 हजार, 436 रूपये का ऐक्सैस खर्च हुआ है। वर्ष 1986-87 के दौरान मई, 1987 में तालू माइनर को ऐक्स्टेन् िन के लिए

तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री भाम ार सिंह सुरजेवाला ने फाँउडे ान स्टोन रखा था। तालू माइनर सिर्फ तालू के लिए रह गई थी तो लोहारी, जाटू भटाना, पुर, सिवाड़ा इन गांवों में पानी को जो प्रोबलम है, इसको हल करने के लिए सिवाड़ा के पास से एक माईनर की आधार िला रखी गई थी। बाद में जून 1987 में सरकार बदल गयी। उसके बाद वह स्कीम भी बदल गयी। इसलिये मैं अपने इरीगे ान एण्ड पावर मिनिस्टर साहब से यह निवेदन करूंगा कि वह उन कागजों को दोबारा तला ा करके हमारे उन चार गांवों की मु ि कल का हल निकालें। यह स्वयं मानते हैं कि तालू माईनर की टेल पर तो पानी आज भी नहीं जाता। लोहारी जाटू, मढ़ाना पुर और सिवाड़ा में तो आज तक भी पानी नहीं पहुंचता। इन चार गांवों का पानी एक गांव ही पी रहा है। इन चार गांवों में का त के लिये भी पानी नहीं मिलता ओर पानी की बड़ी समस्या रहती है। इस मसले को हल करने के लिये कुछ योगदान करें। इसी तरह से भूरे माईनर के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला ने 1987 में इस माईनर की आधार िला रखी थी। बाकायदा इसक एस्टीमेट बनाकर इसके लिये पैसा निकाला था। इन दोनों माइनरों का पैसा वहां पर खर्च नहीं किया गया बल्कि कहीं और खर्च किया गया। मंत्री महोदय इस बात का जवाब दें कि कहां और क्यों खर्च किया गया? गेंडावास माईनर की निलोई माईनर का भी मई, 1987 में फाँउडे ान स्टोन रखा गया लेकिन बाद में इसको डिस्बैंड कर दिया गया मैं यह जानता हूं कि यह 1986-1987 की डिमांडज हैं, लेकिन मैंने जो स्कीमें आप के सामने हाउस में रखी है, इनका एस्टीमेट भी बाकायदा बनाया गया था। अगर एस्टीमेंट बनाया

गया था तो यह पैसा डाईवर्ट कैसे किया गया? मैं यह समझता हूँ कि मंत्री महोदय यहां पर आ वासन दें कि मेरे इलाके के गांवों की तकलीफ को ध्यान में रखते हुए इन माईनर्ज को बनाएंगे। आज ही एक सवाल का जबाब देते हुए मंत्री जी ने बताया है कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट की माईनर्ज और सब-माईनर्ज की 269.7 किलोमीटर लम्बाई की डी-सिलिंटग की गयी है। अब कितनी डी-सिलिंटग हुई है और कितनी नहीं हुई है, यह खुद तो स्पष्ट नहीं है। मैं यह कहता हूँ कि वहां पर कोई ऐसी बात नहीं है। (व्यवधान व भाोर) मैं अब भी यह कहता हूँ कि वहां पर कोई डिसिलिंटग नहीं हुई है। डिसिलिंटग के काम का तो तब पता चले जब पानी टेल पर पहुंच जाये। जब हैड पर ही पानी नहीं तो टेल पर कहां से आयेगा? मंत्री जी ने तो खुद ब्याद दे दिया है कि इरीगे इन डिपार्टमेंट ने एक कीर्तिमान कायम किया है, लेकिन मैं यह बात दाते के साथ कहता हूँ कि तालू माईनर की टेल पर धमाना माईनर की टेल पर, नलवी माईनर की टेल पर, सिवानी माईनर की टेल पर और हरीता माईनर की टेल पर कोई पानी नहीं पहुंचा है। यही नहीं, चार साल तक ताऊ का राज रह लिया, तब भी वहां पर कोई पानी नहीं गया। हां, जगदी ा नेहरा के मंत्री बनने के बाद एक बार पानी अव य गया है लेकिन उसके आगे-पीछे कभी नहीं गया।

**सिंचाई मंत्री (चौधरी जगदी ा नेहरा):** एक बार को तो मानते हो। ( गोर व व्यवधान)

**श्री अमर सिंह:** हां, वह तो मानता हूँ। आज ग्रो-मोर-फूड की बात होती है। अगर पानी होगा, तभी तो अनाज पैदा होगा। बगैर

पानी के, बगैर खाद के और बगैर किसान की मेहनत के अगर पैदावार बढ़ती है तब फिर वह जादू का ही कोई लैम्प होगा। इनके पास अगर ऐसा लैम्प है तो दूसरी बात है। लेकिन नलवी माईनर की टेल पर पानी पहुंचने के बारे में मैं बताना चाहता हूँ जो नलवी वाटर सप्लाई स्कीम है, उसमें नलवी गांव है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। इरीगे इन में यह है कि इरीगे इन डिपार्टमेंट का तो कमाण्ड एरिया है भिवानी जिला और वाटर सप्लाई का कमाण्ड एरिया है हिसार जिला, उनकी तालमेल नहीं बनती। इससे गांव के लोगों को तकलीफ होती है। इस तकलीफ को दूर किया जाना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं ऐजुके इन के बारे में कहना चाहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, ऐजुके इन एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर हमारा भविष्य निर्भर करता है और सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जहां हमने विकास किया है, वहां दूसरी ओर शिक्षा का स्तर गिरा है। इसके बीच में नकल एक बुराई आ गई है। हमारा हायर ऐजुके इन पर जोर है। प्रान्त में गवर्नमेंट कालिज केवल तीस है और प्राइवेट कालिज एक सौ चालीस है। एक सौ चालिस कालिजों में इस बात का अनरैस्ट है कि गवर्नमेंट उनके टीचर्स को बुलाकर बात नहीं करना चाहती। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर एक सौ चालीस कालिज बन्द हो जाते हैं तो अनरैस्ट स्टुडेंट्स में भी होगा और टीचर्स में भी होगा। इसको हल करने की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) स्पीकर साहब आप ऐजुके इनिस्ट रहे हैं और ऐजुके इन से आपका सम्बन्ध रहा है। 1-1-1986 को जितना स्टाफ था, उसी के

हिसाब से उनको 95 प्रतिशत ग्रांट दी जाएगी। स्पीकर साहब, 1986 के बाद स्टुडेंट्स की संख्या में कई गुना बढ़ गई जहां पांच सौ स्टुडेंट्स थे वहां तीन हजार स्टुडेंट्स हो गए और जहां एक हजार स्टुडेंट्स थे वहां पांच हजार हो गए। इसलिये रेगुलेशन को देखते हुए हमें एडीशनल स्टाफ की भी ग्रांट देनी चाहिए और उनको बुलाकर बात करनी चाहिए। स्पीकर साहब, सरकार ने छः महीने की मैटरनिटी लीव देने का फैसला कर दिया है लेकिन छः महीने तक रिप्लेसमेंट की इजाजत न हो तो स्टुडेंट्स क्या करेंगे? मैडम तो चली गई, ऐसी हालत में स्टुडेंट्स क्या करेंगे? इस बात की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्पीकर साहब, फीस और फण्डज गवर्नमेंट ट्रेजरी में सौ परसेंट जमा होते हैं लेकिन उनको स्टाफ लगाने की इजाजत नहीं है। वाइस चांसलर का नौमिनी जाएगा जब तक वह ऐप्रूवल नहीं देगा तब तक वहां कोई आदमी अप्वाइंट नहीं किया जा सकता। इससे स्टुडेंट्स का बहुत नुकसान होता है। आने वाली पीढ़ी का भविष्य अन्धकारमय हो जाएगा। नई पीढ़ी हमारे देश के निर्माता होंगे, इसलिए उनकी तकलीफों को अनदेखी नहीं करनी चाहिए।

स्पीकर साहब, जुलाई 1992 में डी०एच०ई० ने एक लैटर जारी किया है कि मैनेजमेंट कोई भी स्टाफ नहीं लगा सकता, जब तक की वाइस चांसलर की इजाजत न हो। मेरी गुजारिश है कि प्राइवेट कालिज का जो अदारा है, उनके मैनेजमेंट को मुख्य मंत्री जी बुलाएं और उनकी रिपोर्ट को सुनें। अगर ये कालिज बन्द हो गए, जैसा कि विचार चल रहा है तो उससे बड़ा भारी नुकसान होगा। गवर्नमेंट के

केवल तीन कालिज है और प्राइवेट कालिजों के स्टुडेंट्स की हम इन कालिजों में अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे।

इसके अलावा स्पीकर साहब, ऐक्साइज एण्ड टैक्सो इन की बात है। ऐक्साइज एण्ड टैसे इन का थोड़ा सा अमाउन्ट है ( गोर एवं व्यवधान)। 1986 में मुख्य मंत्री बदले थे। आप सैन्टर में चले गए थे और चौधरी बंसी लाल मुख्य मंत्री बने थे। जून 1987 में लठाधी 1 सरकार आ गई। मई 1987 में जो प्रोग्राम बना था, वह खत्म हो गया। मेरा कहना यह है कि इससे पहले जो प्रोग्राम बनाया गया था, वह लागू करना चाहिए। हमने तो फांउडे इन स्टोन-ले करवा दिया था। उसके बाद सरकार बदल गई फिर न आपकी जिम्मेवारी रही, न हमारी जिम्मेवारी रही। जिनकी जिम्मेवारी रही उन्होंने निभाई नहीं। यह जो 1986-87 का खर्चा हो चुका है, इसमें हमें अब तो कोई रेलैवैन्सी दिखाई नहीं देती लेकिन रेलैवैन्सी इस बात की जरूर है कि उस वक्त जो काम भुरू हुआ, उसको अगली सरकार को इन हैंड लेना चाहिये था। बस इतना ही कहते हुए आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

**वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता):** अध्यक्ष महोदय, आज सदन में पूर्व मांगो पर हबस हो रही है। उसी सम्बंध में मैं अपने विचार आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। मैंने पहले भी हाउस को बताया था कि 1986-87 का जो बजट इस विधान सभा ने पास किया था, उस वक्त पांच विभागों ने 42.41 करोड़ रूपये का खर्चा कुछ ज्यादा कर दिया था और अब उसको विधान सभा से रेगुलेराईज करवाना या पास करवाना

था। कम्पट्रोलर एंड आडिटर जनरल की जो रिपोर्ट थी, वह 21-2-89 को इस हाउस में पेश हुई, उस रिपोर्ट को हमारी लोक लेखा समिति ने बड़े ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हमारा जो पिछला बजट सेशन था उसके बाद इसकी रिपोर्ट 22-4-92 को हमारे पास पेश हुई लेकिन विधान सभा की जो पिछली लोक लेखा समिति थी, उसके चेयरमैन या माननीय सदस्य जो थे, उन्होंने इस कार्य में क्यों डिले की, क्यों रिपोर्ट के आने के बाद यह पहला सेशन है। पहले ही इस अड़चन को आर्टिकल 205 के तहत दूर करना चाहिये था, लेकिन ऐसा नहीं जिस कारण से हम इस अड़चन को दूर करने के लिये इस इंतजार को इस हाउस में लाए हैं। ओर सभी माननीय सदस्यों ने इस बात को माना भी है कि इस फारमैलिटी को पूरा करना ही है, इसलिये इसमें विशेष चर्चा की कोई बात नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, हमारे कई माननीय सदस्यों ने इन डिमांडज पर डिस्कशन के बहाने ही अपने-अपने हल्कों की मांगों को भी हमारे नोटिस में लाने का प्रयत्न किया है और कई मैम्बर्ज ने खूब चर्चा भी की है। मेन चर्चा के विशय तो दो तीन ही दिखायी दिये। कुछ माईनर्ज के बारे में भी चर्चा रही और कुछ मैम्बर्ज की शिकायत भी थी कि डी सिलिंटिंग में कुछ कमी रही है। सड़कों की मुरम्मत में भी कमी रही। ऐजुकेशन में भी कुछ कमियों का जिकर किया गया कि प्राइवेट कालेजों में टीचर्ज की कमी है। ला एण्ड आर्डर के बारे में भी चर्चा की गई जिसका कर्ण सिंह दलाल ने खास जिकर किया। कुछ पेंशन वगैरह का भी जिकर किया गया। रेलवे रोडज का भी जिकर किया गया। कर्ण सिंह दलाला जी ने बोलते हुए एक विशेष बात कह दी कि 10-12-1992 को नामवती पुत्री सुखराम, ब्राहमण, गांव

ब्राह्मनी खेड़ा तहसील पलवल की ला 1 गांव में मिली जिसको कि गला दबाकर मारा गया था। साथ में यह कह दिया कि उस लड़की के साथ बलात्कार भी हुआ था लेकिन मेरे साथी यहां पर बैठे नहीं है, अगर बैठे होते तो बेहतर होता। ( गोर)

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** मैं हाउस में हाजिर हूँ जी।

**श्री मांगे राम गुप्ता:** तो फिर आप अपनी सीट पर आ जाइएगा। स्पीकर साहब, जब यह बात सरकार के नोटिस में आई तो उसी दिन धारा 302 के तहत दोशी के खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज करवा दी गई और यह पाया गया कि लड़की को मारने से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया था। दोशी जीवन ऊर्फ जीवा अहेड़ी को 21-12-1992 को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुलजिम उसी गांव का है, जिस गांव के मेरे आदरणीय साथी कर्ण सिंह दलाल है।

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** स्पीकर साहब, मेरी पर्सनल एक्सप्ले न है। मंत्री जी इस लड़की के मर्डर केस के बारे में कह रहे हैं कि ट्रेस हो गया है। जिन 13-14 बे कसूर आदमियों को मार पीट की गई उनका क्या होगा? एफ०आई०आर० को दर्ज हुए तीन महीने हो गए हैं लेकिन उस लड़की के अपहरणकर्ताओं का कुछ पता नहीं लगा है।

**श्री मांगे राम गुप्ता:** ट्रेस करने में टाईम लग सकता है। अगर दलाल साहब को मुलजिमों के बारे में पता ही तो ये हमारे नोटिस में ला दें, हम फौरन एक न न लेंगे।

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** हमने उसका नाम बता दिया था।



**श्री मांगे राम गुप्ता:** उसको तो हमने पकड़ लिया है यहां पर एजुके इन के बारे में भी चर्चा हुई। हमारे आदरणीय विधायकों को गिला है कि एजुके इन का स्टैंडर्ड बहुत गिर गया है और इसके कई कारण बताए। एक तो टीचर्स की कमी बताई, दूसरे नकल की चर्चा की और तीसरी बात यह कही कि प्राइवेट कालेजिज की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि 1986 से 1991 तक जो पिछली सरकारें यहां रहीं, उन्होंने प्राइवेट कालेजिज के लिए एक भी पोस्ट को सैंक इन नहीं दी। लेकिन आज आपकी सरकार ने प्राइवेट कालेजों की मांग को उचित समझते हुए 6 साल के बाद पहली बार माना है। उनकी पूरी डिमांड तो हम नहीं मान सके, लेकिन उनसे कंसल्ट करके जितना जरूरी समझते थे, उतनी सैंक इन हमने दे दी है।

**साथी लहरी सिंह:** इसमें स्टुडेंट्स की लाइफ और राष्ट्र निर्माण का सवाल है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जो पोस्टें नई सैंक इन की गई हैं, उनके अगेंस्ट अप्वायटमेंट कब तक कर दी जाएगी?

**मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):** हम जल्द ही करने की कोशिश करेंगे।

**प्रो० छत्तर सिंह चौहान:** अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायट आफ आर्डर है। मैं जानना चाहता हूं कि हरियाणा में इन्होंने प्राइवेट कालेजों को कितनी पोस्टें सैंक इन की हैं और गवर्नमेंट कालेजों को कितनी की है?

**श्री मांगे राम गुप्ता:** फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एजुके इन डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके कि कितनी ऐसी जरूरी पोस्टें है जिनकी बहुत जरूरत है और उनको न भरने की वजह से नुकसान हो रहा है, उसे मुताबिक हमने सैंक इन दे दी है। अब वह किस-किस कालेज को देनी है, यह एजुके इन डिपार्टमेंट का काम है।

**श्री अध्यक्ष:** वे तो लम्प-सम पूछ रहे हैं कि कितनी पोस्टें प्राइवेट कालेजों को दी है और कितनी गवर्नमेंट कालेजों को दी है।

**श्री मांगे राम गुप्ता:** अभी हमने 150 पोस्टों की सैंक इन दी है। इसमें से 75 गवर्नमेंट कालेजों के लिए है और 75 प्राइवेट कालेजों के लिए हैं। इसके अलावा 250 पोस्टें सीनियर सकेण्डरी स्कूलों के लिए दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को एक बात बताना चाहता हूं। चौहान साहब ने एजुके इन बोर्ड के बारे में कह कि एग्जामिने इन के दौरान नकल होती है। अध्यक्ष महोदय, अभी तक एजुके इन बोर्ड के चेयरमैन पोलिटिकल आदमी नियुक्त होते रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष:** आपने कालेजिज की सारी बातों का जवाब तो नहीं दिया। जो लेडी टीचर मैटरनिटी लीव पर चली जाती है उसकी जगह पर जो दूसरी टीचर लगाई जाती है, उसको तनखाह क्यों नहीं देते? जब पहले तीन महीने मैटरनिटी लीव होती थी, उस वक्त आप उनको पे-डिस्वर्स करते थे। अब आपने जो तीन महीने की लीव बढ़ा कर 6 महीने की है, वह भी जायज नहीं की है।

**श्री मांगे राम गुप्ता:** अध्यक्ष महोदय, पहले तो ऐसा था कि लेडी टीचर को हर इ पू पर तीन-तीन महीने को मैटरनिटी लीव दी जाती थी और इ पूज पर कोई पाबंदी नहीं थी। एक लेडी टीचर ने जितनी बार ई पूज होते थे, उतनी बार वह तीन-तीन महीने की मैटरनिटी लीव लेती थी। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने फ़ैमिली प्लानिंग की वजह से जो पालिसी डिसाइड की है, हमने उसी पालिसी को फ़ोलो किया है। अब हमने केन्द्रीय सरकार की पालिसी के अनुसार लेडी टीचर को मैटरनिटी लीव लेने के लिए दो बार की लिमिट कर दी है। अब लेडी टीचर दो बार 6 महीने की मैटरनिटी लीव ले सकती हैं। लेडीज की तरफ से यह मांग थी कि अगर उनके उपर दो इ पूज की पाबन्दी लगाई जा रही है तो उन्हें दो ई पूज की अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए 6 महीने का समय तो अवय मिलना चाहिये। लेडीज की इस मांग को उचित समझते हुए मैटरनिटी लीव तीन महीने से बढ़ा कर 6 महीने की गई है। 6 महीने की मैटरनिटी लीव के कारण स्कूलों और कालेजिज में पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है, वह भी सरकार के विचाराधीन है। उसका भी कोई न कोई हल जरूर निकाला जाएगा।

**श्री अध्यक्ष:** पहले जब कोई लेडी टीचर मैटरनिटी लीव पर जाती थी तो उसकी जगह पर जो दूसरी टीचर लगाई जाती थी, उसकी पे डिसबर्स करते थे। क्या अब भी करेंगे इन लीव आफ़ देट।

**श्री मांगे राम गुप्ता:** वह पे तो उसको देंगे।

**श्री अध्यक्ष:** देंगे लेकिन अभी तक तो नहीं दे रहे?

**श्री मांगे राम गुप्ता:** नहीं जी, पे तो दे रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष:** पीछे से देंगे जब से वह कन्टीन्यूड है?

**श्री मांगे राम गुप्ता:** अध्यक्ष महोदय, जो तीन महीने की मैटरनिटी लीव बढ़ा कर 6 महीने की है, उसको पूरा करने के लिए मामला विचाराधीन है और उसको कम्पनसेट करना चाहते हैं, अभी मामला विचाराधीन है।

**श्री अध्यक्ष:** गुप्ता जी मामला विचाराधीन में ओर देंगे में बहुत फर्क है। आप सही बात बताएं। अभी आपने कहा है कि देंगे। देंगे means you assure.

**श्री मांगे राम गुप्ता:** अध्यक्ष महोदय, इस बारे में एजुके टान डिपार्टमेंट ने फ़ैसला करना है। हम तो केन्द्रीय सरकार की नीति के मुताबिक जो हिदायतें हैं, उनको फोलो कर रहे हैं।

**श्री अमर सिंह:** स्पीकर साहब माननीय वित्त मंत्री जी बात को गोलमोल कर रहे हैं। सही जवाब नहीं दे रहे हैं, मंत्री जी को ठीक जवाब देना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष:** अब पहले लेडी टीचर तीन महीने की मैटरनिटी लीव पर जाती थी और उसकी जगह जो दूसरी टीचर लगाई जाती थी, उसको आप सेलरी डिस्बर्स करते थे तो क्या अब भी आप उसको सेलरी देंगे?

**श्री मांगे राम गुप्ता:** अध्यक्ष महोदय, यह मामला एजुके ान डिपार्टमेंट के विचाराधीन है। इस बारे में अभी तक कोई फाईनल डिसीजन नहीं लिया गया है। जब इस बारे में कोई फाईनल डिसीजन हो जाएगा तो बता देंगे।

**श्री अमर सिंह:** स्पीकर साहब, पे देते है और देगें, में तो बहुत फर्क है?

**मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):** अध्यक्ष महोदय, आपका हमें ही एजुके ान की तरफ बहुत रूझान और झुकाव रहा है। आप यह जानते है कि प्राइवेट कालेजिज में आज तक भी लेडी टीचर को, जो तीन महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है उसको पे मिलती है, उसको पे मिली हो लेकिन गवर्नमेंट कालेजिज में यह मिलती है।

**श्री अध्यक्ष:** हम भी कालेज चला रहे है, मैं कालेज सोसाइटी का प्रैजिडेंट हूं। जो लेडी टीचर तीन महीने की मैटरनिटी लीव पर जाती थी और उसकी जगह जो दूसरी लेडी टीचर लगाते थे, उनको उसी तरह की तनख्वाह दी जाती थी।

**चौधरी भजन लाल:** अध्यक्ष महोदय, जो प्रोसीजार पहले चल रहा है, वह ज्यों का त्यों रहेगा। अगर प्राइवेट कालेजिज में यह सुविधा मिलती थी तो वह आगे भी मिलती रहेगी और सरकारी कालेजिज में तो खैर यह सुविधा थी ही।

**श्री अध्यक्ष:** ठीक है।

**श्री मांगे राम गुप्ता:** अध्यक्ष महोदय, एजुके ान बोर्ड के अन्दर हमे ा से ही राजनीतिक व्यक्ति चेयरमैन लगता रहा था। लोगों की यह डिमांड थी कि इस बोर्ड का चेयरमैन कोई राजनीतिक व्यक्ति न होकर ि ाक्षाविद होना चाहिये। पहले वह राजनीतिक लोग बोर्ड के चेयरमैन लगते रहे, तो उस समय नकलें बहुत अधिक होती थीं और बोर्ड का सारा सिस्टम ही खराब हो चुका था। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक रिटायर्ड प्रोफ़ैसर श्री जय भगवान को एजुके ान बोर्ड का चेयरमैन लगाया है। उनके बारे में आप स्वयं भी श्री अध्यक्ष, अच्छी तरह से जानते हे। अब हमने उनको पूरा अधिकार दिया है कि बोर्ड कि अन्दर पहले जो नकलें होती रही हैं या और दूसरी गड़बड़ियां होती रही है, उनकी पुनरावृत्ति न हो। हमें पूरी उम्मीद है कि वे इस और ध्यान देते हुए पिछली गलतियों को दूर करेंगे जिससे बोर्ड के कामकाज में ओर अधिक सुधार हो सकेगा। (विघ्न)

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह फैसला लिया हुआ है कि जो पहली ओर दूसरी कक्षा के बच्चे पढ़ते हैं, यदि वे परीक्षा में फेल भी हो जाएं, तो भी पास कर दिया जाये। मेरा इस संबंध में सुझाव है कि यदि कोई बच्चा फेल है तो उसे फेल ही रहने दिया जाये और जो बच्चा पास हो, उसे पास कर दिया जाये।

**श्री अध्यक्ष:** जब आपको बोलने का समय दिया गया था तब यह बात कहनी चाहिये थी।

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** अब मैं आपकी इजाजत से फिर कह देता हूँ।

**श्री अध्यक्ष:** अब आप बैठिये। गुप्ता जी आप अपना जवाब दीजिए।

**श्री मांगे राम गुप्ता:** कुछ विधायकों ने यह कहा कि कुछ स्कूलों में टीचर सरप्लस है और कुछ में टीचरों की कमी है। मैं इस संबंध में सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जिन स्कूलों में सरप्लस टीचर थे, उनको बदल दिया गया है और जहाँ पर कमी थी, वहाँ पर लगा दिया गया है। इसके अलावा, ओर जो भी कमी बनी हुई है, उसके लिए हमने टीचरों के इन्टरव्यू ले लिए हैं और जल्दी ही रिजल्ट निकाल कर खाली स्थानों पर उन्हें लगा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने मन्जूरी दे दी है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात आदरणीय चौहान साहब ने पैन इन के बारे में कहीं कि पिछली सरकार ने 65 साल की उम्र रखी थी लेकिन अब 60 साल कर दी गई, लेकिन लोगो को ठीक पैन इन नहीं मिल रही। इन्होंने बोलते हुए अपने गांव का हवाला भी दिया था। इस संबंध में इनकी जानकारी के लिये और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि उस सरकार मैं तो पैन इन का कोई क्राईटेरिया था ही नहीं। जो लोकदल के लोग थे, या जो ग्रीन बिग्रेड के लोग थे, जो गरीब लोग थे, बैकवर्ड क्लासिज के लोग थे, या हरिजन तबके के लोग थे, उनकी पैन इन देने में इग्नोर किया गया था चाहे कोई 80

वर्ष का बूढ़ा हो उसको भी पेंशन नहीं दी गई। हमारी सरकार ने पेंशन देने के लिए जहां उम्र 65 साल से घटा कर 60 साल की रखी, वहीं इनके साथ ही साथ पेंशन के कलए कुछ क्राइटीरिया भी बनाये जो लोग पेंशन के लिए डिजायरेबल हों, जिसको पेंशन चाहिए, सरकार से जिसको मदद की जरूरत है उसी को पेंशन मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं कि हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। जो निर्धारित क्राइटीरिया पूरा करता हो, भले ही वह किसी भी जाति से सम्बंध रखता हो, उसको पेंशन देने से इग्नोर नहीं किया गया।

**श्रीमती चन्द्रावती:** अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

**श्री अध्यक्ष:** मंत्री जवाब दे रहे हैं आप उनको बोलने दें। आप जो कुछ कहना चाहती हैं वह लिख कर उनको भेज सकती हैं।

**श्रीमती चन्द्रावती:** स्पीकर सर, मैं पेंशन से सम्बन्धित ही बात कहना चाहती हूं। अभी मंत्री जी कह रहे थे कि पेंशन देने के बारे में किसी को इग्नोर नहीं किया गया, लेकिन कुछ आदमी ऐसे हैं जो पेंशन से वंचित रह गए हैं। मेरे हल्के के कुछ लोगों की पेंशन नहीं मिली जब कि वे उसके हकदार हैं। मैंने इस बारे में लिख कर भी भेजा है कि 70-70, 75-75 साल के लोग हैं जो पेंशन से वंचित रह गए हैं। मैंने इस मामले को ग्रिवैन्सिज कमेटी में भी उठाया है। मेरे हल्के के चाहड़ और बारावास गांवों के कुछ लोगों को पेंशन से वंचित रखा



गया है। मैंने इस बारे में श्री भार्मा जी को भी लिख कर दिया है। स्पीकर साहब, मैं इस बात को आन दि फलोर आफ दि हाउस कहती हूँ कि जो लोगों की परे ानी है, उसको दूर किया जाए। जो लोग पैँ ान नहीं पा सके, उनको दी जानी चाहिये। स्पीकर साहब, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी कसे यह नम्र निवेदन है कि जिन लोगों को अब तक किसी कारण से पैँ ान नहीं मिल पाई है, उनके नाम पैँ ान के लिये भामिल किये जाने चाहिये।

**चौधरी वीरेन्द्र सिंह:** स्पीकर सर, पैँ ान के मामले में खासी गड़बड़ है। कई लोग ऐसे हैं, जिनको पैँ ान मिलनी चाहिए लेकिन उनके नाम पैँ ान के लिए दर्ज नहीं हो सके। हम लोग जब गांवों में जाते हे तो अक्सर लोग इस बारें में बात करते हैं। लोगों को पैँ ान न मिलने के बारें में आमतौर पर 2 कारण बताएं जाते हैं। एक कारण यह है कि गांवों मे गुटबाजी और पार्टीबाजी है। भायद पैँ ान के कागजों में सरपंच से कुछ तसदीक करवानी पड़ती है। अगर सरपंच दूसरी पार्टी का हुआ तो वह तसदीक करने से इन्कार करता हैं। दूसरा कारण यह है कि 60-65 साल के लोग है, उनको सी०एम०ओ० आफिस से उम्र का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता क्योंकि उनका जन्म अस्पताल में तो हुआ नहीं अपनढ़ लोग थे, उस वक्त अस्पतालों में कौन जाता था? हममें से कितनों का जन्म अस्पताल में हुआ है? अस्पताल के रिकार्ड में तो उनका नाम दर्ज नहीं होता। (विघ्न) हम तो पता नहीं कहां पैदा हुए? एक दफा तो डाक्टर भायद गांव में उम्र सर्टिफिकेट के लिए जाता भी है लेकिन अगर कोई आदमी उस दिन किसी वजह से न हो या डाक्टर

के पास न आ सके, तो फिर वह सारा साल परे जान होता रहता है। इसलिये मैं सरकार से गुजारि । करूंगा कि इसका कोई समाधान किया जाए। एक बार फिर एक महीने के लिए नामों के रजिस्ट्रेशन का काम करें। उससे पहले, इसके लिए पूरी ऐडवर्टाईजमेंट करवाएं ताकि लोगों को पता चल सके और जो लोग वाकई में क्राईटीरिया पूरा करते हैं लेकिन किसी वजह से पैंशन से वंचित रह गए हैं, पैंशन मिल सकें, यही मेरी गुजारि । है।

### **बैठक का समय बढ़ना**

**श्री अध्यक्ष:** यदि हाउस की सहमति हो तो बैठक का टाईम 5 मिनट के लिये बढ़ा दिया जाए।

**आवाजें:** ठीक है, टाईम 5 मिनट बढ़ा दिया जाए।

**श्री अध्यक्ष:** बैठक का टाईम 5 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

**वर्ष 1986—1987 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)**

**मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):** स्पीकर साहब, हमने बाकायदा तीन महीने तक ऐडवर्टाईज किया था। जो आदमी किसी कारणवश पैंशन पाने से वंचित रह गए हैं, उनके लिए बन्द नहीं किया है। साल में एक दफा वे ऐप्लीकेशन दे सकते हैं। जो आदमी आज 60 साल का हो गया है, वह पैंशन के लिए ऐप्लीकेशन दे

सकता है। स्पीकर साहब, जो लोग किसी कारणवश मैं उन नहीं ले सकें और क्राईटीरिया पूरा करते हैं उनको मैं उन दी जाएगी।

**श्री वीरेन्द्र सिंह:** वे डेट आफ बर्थ मांगते हैं।

**चौधरी भजन लाल:** अध्यक्ष महोदय, दूसरे इन्होंने सरपंच की बात कही। उसमें सरपंच नहीं पटवारी तसदीक करता है। उसमें कोई प्रोब्लम नहीं है।

**श्री कर्ण सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने अभी सदन के सामने जो बात मैं उन के बारे में बताई है भायद इनको इस बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा तो यह है कि वे जिले के डिप्टी कमी नर से बात करें। वे तो सीधे तौर पर जवाब देते हैं। और मैं सदन में यह बात कहना नहीं चाहता। माननीय गुप्ता जी हमारे जिले की ग्रैवेंसिज कमेटी के चेयरमैन हैं और मीटिंग के बीच में गुप्ता जी ने यह बात कही थी कि लोगों को मैं उन दी जाती है, यह उनको डिमोरेलाईज करने के लिए दी जाती है। यह मैं उन की पालिसी अच्छी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरकार या तो खड़ी होकर कह दे कि यह मैं उन नहीं दे सकती। अगर कोई फाईनेन्स की प्रोब्लम है, तो अलग बात है। अध्यक्ष महोदय, चीफ मिनिस्टर के लिए 22 लाख की कार खरीदी जाती है। मुख्य मंत्री की कार खरीदने के लिए पैसे हैं और बुजुर्गों को मैं उन देने के लिए पैसे नहीं हैं।

**श्री अध्यक्ष:** यह कोई इमोशनल बात नहीं है। गुप्ता जी आप कन्टीन्यू करें।

**वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता):** अध्यक्ष महोदय, मैं आज भी वही बात कहने को तैयार हूँ मैंने अपने साथी को यह कहा था कि अगर क्राईटेरिया में 70 वर्ष का आदमी आता है, तो उस पर कोई डिसप्यूट नहीं हो सकता। आज जिस डिसप्यूट की हमारे विधायक िकायत करते हैं, वह यह है कि जो 55 साल से 60 साल के बीच के आदमी हैं, वे भी पैंान की डिमांड करते हैं। मैंने यह कहा है कि पैंान के मामले में ऐसे आदमियों को ज्यादा इनकरेज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे लोगों को इनकरेज करेंगे तो कल को 50 साल वाले भी तैयार हो जाएंगे और सारा बजट पैंान पर ही खर्च हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज जो हम स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों आदि की मांग करते हैं, वह कुछ भी पूरा नहीं हो सकेगा और सारा का सारा बजट पैंान पर ही खर्च हो जाएगा। ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐ योर कर दिया है कि यह पालिसी चालू है।

**श्री मांगे राम गुप्ता:** अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि 1986-87 के बजट प्रावधान में जो 5 महकमों की तरफ से डिमांडज् नं० 6,8,9,15 और 23 में टोटल 42.41 करोड़ रूपए फालतू खर्च हो गए थे विधान सभा ने इसकी स्वीकृति लेनी जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से चाहूंगा कि सदन इसको स्वीकृति दे ताकि इसको रेगुलराईज किए जाए। धन्यवाद।

**Mr. Speaker:** Now, i shall put the various demands to the vote of the House.

**Mr. Speaker:** Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 21,62,304 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1986-87 in respect of Revenue.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 74,604 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1986-87 in respect of Excise & Taxation.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 2,02,35,540 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1986-87 in respect of Finance.

**The motion was carried**

**Mr. Speaker:** Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 15,63,38,564 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1986-87 in respect of Buildings & Roads.

**The motion was carried**

**Mr. Speaker:** Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,79,28,557 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1986-87 in respect of Education.

**The motion was carried**

**Mr. Speaker:** Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 10,07,20,436 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1986-87 in respect of Irrigation.

**The motion was carried**

**Mr. Speaker:** Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 28,36,994 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1986-87 in respect of Annimal Husbandry.

**The motion was carried**

**Mr. Speaker:** Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 45,93,417 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1986-87 in respect of Community Development.

**The motion was carried**

**Mr. Speaker:** Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 6,82,95,633 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1986-87 in respect of Transport.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 65,286 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1986-87 in respect of Tourism.

**The motion was carried**

**Mr. Speaker:** Now, the House stands adjourned till 9:30 a.m. tomorrow.

**13:35 P.M.**

(The sabha then adjourned till 9:30 a.m. on Wednesday, the 23<sup>rd</sup> December, 1992.)